लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 3, बुधवार, 19 फरवरी, 1969/30 माघ, 1890 (शक)
No. 3, Wednesday, February 19, 1969/Magha 30, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
31. भारत ईरान औद्योगिक सहयोग	Indo-Iranian Industrial Collaboration	..	1—2
32. भारत ईरान आर्थिक सहयोग	Indo-Iranian Economic Cooperation	..	2—7
33. समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार	Monopoly of Newspapers	..	7—14
34. कच्चाटीबू के प्रश्न का समाधान	Settlement of Kachchativu Issue	..	14—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
35. तारापुर अणु बिजलीघर	Tarapur Atomic Power Plant	..	18—19
36. नेपाल में चीनियों द्वारा 'इण्डियन एक्सप्रेस' के मुख्य सम्पादक का रोका जाना	Detention of the 'Indian Express' Chief Editor by the Chinese in Nepal	..	19—20
37. नागा विराम सन्धि की अवधि	Naga Truce Period	..	20
38. चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	..	20—21
39. दिल्ली का योजना परिव्यय	Plan Outlay of Delhi	..	21
40. पाकिस्तान के लिये रूस के 'मिग' विमान	Soviet 'Migs' for Pakistan	..	21—22
41. निजी थैलियों के बारे में लार्ड माउंटबैटन का पत्र	Lord Mountabatten's Letter Regarding Privy Purses	..	22

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
42. आकाशवाणी में करनाटक संगीतज्ञ	A.I.R. Carnatic Musicians ..	23
43. केरल के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala ..	23—24
44. केरल में मालापुरम जिले का निर्माण	Creation of Mallapuram District in Kerala	24
45. चीन के साथ बातचीत	Negotiations with China ..	24
46. चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय परिव्यय	Central Outlay for the Fourth Five Year Plan ..	24—25
47. आकाशवाणी से हिन्दी समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन के बारे में तमिलनाडू सरकार का विरोध	Tamil Nadu Government's Protest Against the change in A.I.R. News Bulletin's Timings ..	25
48. काश्मीर के बारे में मध्यस्थता करने के लिये ईरान के शाह का प्रस्ताव	Offer from Shah of Iran to Mediate on Kashmir ..	26
49. आकाशवाणी के लिये निगम	Corporation for A.I.R. ..	26
50. ब्रिटेन में आप्रवासियों का प्रवेश	Entry of Immigrants to U.K. ..	26—27
51. पाकिस्तान के लिये रूसी ट्रांसमीटरों की सप्लाई	Supply of Russian Transmitters to Pakistan	27
52. पाकिस्तान तथा चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र का उल्लंघन	Violations of Indian Territory by Pakistan and China ..	27—28
53. रोडेशिया के साथ व्यापार	Trade with Rhodesia ..	28
54. एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers ..	28—30
55. बेरुबाड़ी	Berubari	30—31
56. गढ़वाल का पिछड़ापन	Backwardness of Garhwal ..	31
57. भूटान को वित्तीय सहायता	Financial help to Bhutan ..	31
58. अखबारी कागज बनाने के कारखाने	Newsprint Plants ..	31—32
59. ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय	Indian Immigrants to U.K. ..	32

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
201. पाकिस्तान जाने वाले यात्री	Visitors to Pakistan ..	33
202. पाकिस्तान को हथियारों की सहायता	Arms Aid to Pakistan ..	33—34
203. भूतपूर्व सैनिकों की पेंशनें	Pensions of Old Soldiers ..	34
204. विदेशी दूतावासों के लिये आवंटित भूमि	Land Allotted to Foreign Embassies in India ..	34—37
206. जनसत्ता का अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota of 'Jansatta' ..	37—38
208. राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth P.M's. Conference ..	38—39
209. आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of A.I.R. Station, Raipur	39
210. रानीखेत के लिए आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station for Ranikhet ..	39
211. विशिष्ट क्षेत्र की सूची में क्षेत्र विशेष को सम्मिलित करना	Inclusion of an Area in the List of Specified Area ..	40
212. इलैक्ट्रानिक उद्योग का विस्तार	Expansion of Electronics Industry ..	40
213. आयुध कारखानों में ए०एम० आई० ई० पास व्यक्ति	A.M.I.E. Qualified Persons in Ordnance Factories ..	40—41
214. शान्ति पर्यवेक्षक दल का मोजेमा दौरा	Peace Observer Group's Visit to Mozema	41
215. नागालैंड में प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबन्धों को उदार बनाना	Liberalisation of Restrictions on entry into Nagaland ..	42
216. श्रीनगर केन्द्र के लिये हिन्दी समाचार बुलेटिन	Hindi Bulletin for Srinagar Station ..	42
217. आकाशवाणी के प्रसारणों में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को बराबर का दर्जा	Equal Status for Hindi and Regional Languages in A.I.R. Broadcasts ..	42—43
218. अफ्रीकी-एशियाई देशों को संसद् सदस्यों का शिष्टमंडल	M.Ps. Delegation to Afro-Asian Countries..	43
219. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निकाले गये प्रकाशन	Publications Brought out by the Ministry of Information and Broadcasting ..	43—44

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
220. अखबारों को दिये गये सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements to Newspapers	44—45
221. पाकिस्तान से विचार विमर्श	Talks with Pakistan ..	45—46
222. हिन्दी समाचार अभिकरण	Hindi News Agencies ..	46
223. रस्टन्बर्ग में भारतीयों को दिया गया आदेश	Order on Restenburg Indians ..	47
224. ताशकंद घोषणा	Tashkent Declaration ..	47
225. आकाशवाणी से वार्ताएं	Talks on A.I.R. ..	48
226. समाचार पत्र वित्त निगम	Newspaper Finance Corporation ..	48—49
227. पूर्वी अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum Submitted by Indians Residing in East African Countries ..	49
228. इसरायली नागरिकों का भारत में आना	Immigration of Israel Citizens to India ..	49—50
229. विदेशों के लिये प्रसारण	External Broadcasts ..	50
230. चौथी पंचवर्षीय योजना का तैयार किया जाना	Formulation of Fourth Five Year Plan ..	50—51
231. चीन द्वारा उद्जन बम का विस्फोट	Chinese Hydrogen Bomb Explosion ..	51—52
232. प्रधान मंत्री के साथ लन्दन गये अधिकारी	Officials who Accompanied P.M. to London	53
233. प्रतिरक्षा उपमंत्री द्वारा लक्कदीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह का दौरा	Deputy Defence Minister's visit to Laccadive and Minicoy Islands ..	53
234. कोचीन नौसैनिक अड्डा	Cochin Naval Base ..	53—54
236. समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता	Financial help to Newspapers ..	54
237. आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in Ordnance Factories ..	54—55
238. 26 जनवरी, 1969 के लिए दिल्ली प्रशासन की झांकी	Delhi Administration's Tableau for 26th January, 1969 ..	55
239. तटस्थ देशों का सम्मेलन	Non-aligned Conference ..	56

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
240. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Limited ..	56—58
241. पर्वतीय विकास बोर्ड	Hill Development Board ..	58
242. अधिक योजना परिव्यय के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा सुझाव	Suggestions by the Federation of Chambers of Commerce and Industry for More Plan Outlay ..	58—59
243. विभिन्न राज्यों के बारे में 1969-70 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय	Annual Plan Outlay for 1969-70 in Respect of Different States ..	59
244. मिग विमान	MIG Aircraft ..	59—60
245. वर्मा द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Industries by Burma ..	60—61
246. अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन	All-India Newspapers Editors' Conference	61—62
247. कराची में शिखर सम्मेलन	Summit Conference in Karachi ..	63
248. कड़पा और विशाखापटनम के आकाशवाणी का दर्जा बढ़ाता	Upgrading of A. I. R. Stations of Cudapah and Vishakhapatnam ..	63
249. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	Bharat Electronics Limited ..	64
250. इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड	Indian Rare Earths Limited ..	64—65
251. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd. ..	65
252. मंत्रालय में अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाना	Extension to Officers in the Ministry ..	65—66
253. आकाशवाणी से गढ़वालियों के बारे में प्रसारण	Broadcast by A.I.R. Re. Garhwalis ..	66
254. प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना	Extension Granted to Class I Officers	66—67
255. उगांडा से भारतीयों का निकाला जाना	Expulsion of Indians from Uganda ..	67
257. जम्मू रेडियो स्टेशन से स्वामी दयानन्द जी के बारे में वार्ता	Talks on Swami Dayanandji from Jammu Radio Station ..	68
258. छावनी बोर्ड	Cantonment Boards ..	68

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
259. सूअर का सूखा मांस तैयार करने का कारखाना	Pork Dehydrating Factory	..	68
260. टूण्डला कारखाना	Tundla Factory	..	69
261. फिजी की स्वतंत्रता	Independence of Fij	..	69
262. लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त में कर्मचारियों में कमी के कारण हुई मितव्ययता	Economic due to Reduction of Staff in India High Commission, London	..	69—70
263. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी	National Defence Academy	..	70
264. विदेश जाने वाले केन्द्रीय मंत्री	Union Ministers going Abroad	..	70
265. प्रतिरक्षा लोक सम्पर्क विभाग	Defence Public Relation Department	..	71
266. भारत का राष्ट्र-मण्डल को छोड़ना	India Leaving Commonwealth	..	71
267. नेफा और लद्दाख को चीन का भाग दिखाना	Showing NEFA and Ladakh as Parts of China	..	71—72
268. चीन और पाकिस्तान को भेजे गये विरोध पत्र	Protest Notes Sent to China and Pakistan	..	72
269. मार्क्सवादी कार्यकर्त्ता को चीनी दूतावास का पत्र	Chinese Embassy Letter to Marxist Worker	..	72
270. सामुदायिक विकास विभाग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission Report on Community Development and Corporation	..	73
271. मंत्रिपरिषद् सचिवालय का विस्तार	Extension in Cabinet Secretariat	..	73
272. पाकिस्तान को तुर्की द्वारा अमरीकी टैंकों की सप्लाई	Supply of American Tanks to Pakistan by Turkey	..	73—74
273. सैनिक समाचार	Sainik Samachar	..	74—75
274. अरवनकाडु स्थित कोरडाइट फैक्टरी	Arvankadu Cordite Factory	..	75
275. पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों के बारे में, प्रधान मंत्री का बी० बी० सी० से इन्टरव्यू	P. M's B.B.C. Interview About East African Indians	..	76
276. पाकिस्तान और चीन से नागाओं को सहायता	Aid from Pak and China to Nagas	..	76—77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
278. दिल्ली में हनोई के वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी द्वारा एक भारतीय लड़की का अपहरण	Kidnapping of Indian Girl by Hanoi Consulate Official in Delhi ..	77
279. गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station for Gorakhpur ..	77—78
280. समाचारपत्रों में साम्प्रदायिक लेख	Communal Writings in Newspaper ..	78
281. तकनीशनों तथा अधिस्नातकों की बेरोजगारी की समस्या	Unemployment Problem of Technicians and Post Graduates ..	78—79
282. अंडरट्वेंटी फाइव के अन्तर्गत वार्ता का प्रसारण	Broadcast of Talk Under Twenty-Five ..	79
283. केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects in the Central Public Sector ..	79
284. जाम्बिया से भारत मूलक निवासियों का निकाला जाना	Squeeze on Indian Settlers in Zambia ..	80
285. भारतीय मिशनों के अध्यक्षों के रूप में राजनीतिज्ञ	Politicians as Heads of Indian Missions ..	80—81
286. फिल्म वित्त निगम	Film Finance Manufacturing Factory, Kanpur ..	81
287. कोरापुट स्थित कारखाने से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति	Persons Resigning from Factory at Koraput	81—82
288. कानपुर में विमान निर्माण कारखाना	Aeroplane Manufacturing Factory, Kanpur ..	82
289. केनिया के भारतीय को भारत में बसाना	Settlement of Kenya Indians in India ..	83
290. फाजिलका क्षेत्र में टावरों का गिराया जाना	Demolition of Towers in Fazilka Sector ..	83—84
291. अपोलो—8 के संकेत प्राप्त करना	Picking up Signals of Apollo-8 ..	84
292. नागालैंड में चीनियों द्वारा घुसपैठ	Infiltration of Chinese in Nagaland ..	84
293. श्रमिकों से सम्बन्धित समाचार पत्र	Labour Newspapers	85

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

294. नागाओं के साथ बातचीत	Talks with Nagas ..	85—86
295. विमान उद्योग	Aircraft Industry ..	86—87
296. सरकारी प्रचार का केन्द्रीकरण	Centralisation of Government Publicity ..	87
297. चिलका में नौसैनिक प्रशिक्षण संस्था	Naval Training Institute at Chilka ..	87—88
298. सरकारी समान	Government Stores ..	88
299. पारपत्र फार्म	Passport Forms ..	88
300. योजना आयोग में इलेक्ट्रोनिक संगणक	Electric Computer in the Planning Commission ..	88—89
301. क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या	Problem of Regional Imbalances ..	89
302. श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति	Repatriates from Ceylon ..	89—91
303. प्रथम प्रतिरक्षा योजना	First Defence Plan ..	91—92
304. संयुक्त अरब गणराज्य स्थित भारतीय दूतावास में विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारी	Staff Attached to Indian Embassy in U.A.R. Knowing Foreign Languages	92
305. ब्रिटेन स्थिति भारतीय उच्चायोग का प्रचार अनुभाग	Publicity Section of the Indian High Commission in U. K. ..	92—93
306. ब्रिटेन में भारतीय उत्प्रवासियों का व्यवहार	Behaviour of Indian Emigrants to U. K. ..	93
307. दिल्ली में जन संचार संस्था	Institute of Mass Communication in Delhi	93—94
308. भारतीय लड़के द्वारा लड़की के वेश में लंदन में प्रवेश करने का प्रयास	Attempted Entry of an Indian Boy into U. K. in the Guise of a Girl ..	94
309. टेलिविजन बनाने वाली लाइसेंसशुदा फर्मे	Firms Licenced to Manufacture T. V. ..	94—95
311. स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा बेरोजगारी के बारे में योजना आयोग को दिये गये सुझाव	Suggestions by the Late Prime Minister to the Planning Commission Regarding Unemployment ..	95
312. योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commission ..	95—96
313. कीनिया तथा मलावी में भारतीय व्यापारियों को लाइसेंस देने से इन्कार करना	Refusal of Licences to Indian Traders in Kenya and Malawi ..	96

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
314. अपोलो-8 के जमीन पर उतरने के बारे में समाचार	News about Apollo-8's Landing ..	97
315. बिड़ला की इथोपिया यात्रा	Birlas' Visit to Ethiopia ..	97
316. मार्लबोरो हाउस के सामने प्रदर्शन	Demonstration before Marlborough House	98
317. चीन और तिब्बत में भारतीय सम्पत्ति को क्षति	Indian Property Damaged in China and Tibet ..	98
318. फिल्म वित्त निगम	Film Finance Corporation ..	98—99
319. चीनी दूतावास द्वारा माओ प्रचार साहित्य का परिचालन	Circulation of Mao Publicity Literature by Chinese Embassy ..	99
320. भारत तथा चीन के राजदूतों के बीच वार्ता	Indo-China Ambassadors' Talk ..	99
321. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd. ..	100
322. पाकिस्तान द्वारा प्रचार	Propaganda by Pakistan ..	100
323. यू० ए० आर० ई०–300 इंजनों के उड़ान परीक्षण	Flight Trials of UARE-300 Engines ..	101
324. पाकिस्तान वायुसेना में वृद्धि	Increase in Pak-Airforce ..	101
325. अरब देशों से यहूदियों का प्रव्रजन	Migration of Jews from Arab Countries ..	101
326. कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र "स्टेट्समैन" की बिक्री	Circulation of "Statesman", Calcutta ..	102
327. आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के एक भाग का स्थानान्तरण	Shifting of a Part of Office of Director General of Ordnance Factories ..	102—103
328. बलिया तथा देवरिया जिलों में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in the Districts of Ballia and Deoria ..	103
329. उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-servicemen in U.P...	103—104
331. निजामापटनम में गश्ती जहाज का धंस जाना	Running Aground of Patrol Vessel at Nizamapatnam ..	104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
332.	नये ट्रांसमीटर	New Transmitters ..	104—105
333.	टेलिविजन सेट	Television Sets ..	105
334.	विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों द्वारा तस्करी	Smuggling by Foreign Embassy Staff ..	105
335.	राजदूतों के लिए वाणिज्य तथा व्यापार का ज्ञान	Knowledge of Commerce and Trade for Ambassadors ..	105—106
336.	भारत-तिब्बत सीमा से साथ-साथ चीनियों के सैनिक प्रतिष्ठान	Chinese Military Installations Along Indo-Tibetan Border ..	106
337.	केनिया निवासी भारतीयों के सुझाव	Suggestions by Kenya Indians ..	106—107
338.	अवाड़ी में टैंक निर्माण कारखाना	Tank Factory at Avadi ..	107
339.	पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक अड्डा	US Base in Pakistan ..	108
341.	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा जप्त की गई युद्ध सामग्री	War Material Captured by Pakistan During Indo-Pak Conflict ..	108
342.	पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई	Arms Supply to Pakistan ..	108
343.	सशस्त्र सेनाओं के राशन में कटौती	Reduced Rations for Armed Forces ..	108—109
345.	अन्तरिक्ष सम्बन्धी समझौता	Outer Space Treaty ..	109—110
346.	हमारे विदेशस्थ मिशनों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों की सहायता	Assistance to Indian Nationals by our Missions Abroad ..	110
348.	श्रम तथा पूंजी की अभ्रयुक्ता	Unemployment of Labour and Capital..	110—111
349.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के दूसरे कारखाने का स्थान	Location of Second Unit of Bharat Electronics Ltd. ..	111
350.	पूर्वी अफीकी देशों में भारतीय व्यापारियों का दमन	Squeeze of Indian Traders in East African Countries ..	111—112
351.	नई काचार सड़क	New Cachar Road ..	112
352.	चुनाव सम्बन्धी प्रसारण	Election Broadcasts ..	112—113

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
356. पाकिस्तान के साथ पुनः व्यापार आदि आरम्भ करना	Resumption of Trade with Pakistan ..	113
357. रेडियो मास्को द्वारा भारत के मंत्रियों की आलोचना	Criticism of Indian Ministers by Radio Moscow ..	113
358. पाकिस्तान की जेल में भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals in Pakistan Jail ..	114
359. टेलीविजन सेटों का निर्माण	T. V. Manufacture ..	114—115
360. बिहार के राज्यपाल द्वारा राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करने के लिये बुलाई गई बैठक	Meeting Called by Governor of Bihar to Draft Fourth Plan for the State ..	115
11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4196 के उत्तर में शुद्धि	Correction of the Answer to the Unstarred Question No. 4196 dated 11 December, 1968 ..	115
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मास्को 'पीस ऐण्ड प्रोग्रैस रेडियो' द्वारा भारत के कुछ राजनैतिक दलों के विरुद्ध प्रचार	Propaganda by Moscow 'Peace and Progress Radio' against Certain Political parties in India ..	115—120
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
चौसठवां प्रतिवेदन	Sixty-fourth Report ..	120
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
उन्तालीसवां तथा बयालीसवां प्रतिवेदन	Thirty-ninth and Forty-second Reports..	120—121
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
तेइसवां प्रतिवेदन	Twenty-third Report ..	121
कार्यमंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	Twenty-eighth—Report ..	121
रेलवे आय व्ययक, 1969-70—प्रस्तुत किया गया	Railway Budget, 1969-70—Presented ..	122—134
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ..	122—134

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-confidence in the Council of Ministers ..	134—165
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel ..	134—*136*
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	136—139
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha ..	139—141
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ..	141—144
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	144—147
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai ..	147—152
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav ..	152—154
श्रीमती गायत्री देवी	Shrimati Gaytri Devi ..	154—157
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait ..	157—159
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigarhi ..	159—160
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan ..	160—162
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhury ..	162—163
श्री एम० नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy ..	163—165
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon ..	165

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 19 फरवरी, 1969/30 माघ, 1890 (शक)
Wednesday, February 19, 1969/Magha 30, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Manibhai J. Patel : Mr. Deputy Speaker, I want to know.....

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : शायद माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगले प्रश्न को भी इसके साथ ही ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

भारत-ईरान औद्योगिक सहयोग

+

*31. **श्री मणिभाई जे० पटेल .**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री शिवप्पा :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की० अमीन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान और भारत के बीच औद्योगिक सहयोग के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों के बीच हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस करार के फलस्वरूप भारत को किस हद तक लाभ होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). जी हां। ईरान के शहंशाह और भारत की प्रधान मंत्री के बीच विचार-विमर्श के बाद, 22 जनवरी 1969 को भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए सम्मिलित भारत-ईरानी आयोग स्थापित करने के बारे में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था। इस करार में यह व्यवस्था है कि यह सम्मिलित आयोग दोनों सरकारों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। इस आयोग के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए उप-समितियां बनाई गई हैं जो व्यापार, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, इंजीनियरी उद्योग, बिजली और पानी के विकास और यातायात का काम देखेंगी।

(घ) अभी इस समझौते के सम्भावित लाभ का परिणाम स्थिर करना कठिन है। फिर भी, भारत सरकार का यह विश्वास है कि दोनों देशों के बीच वर्धित आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग पारस्परिक रूप से लाभदायक होगा।

भारत-ईरान आर्थिक सहयोग

\+

*32. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शशिभूषण वाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 में ईरान के शाह ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रस्ताव किया था कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक तथा तकनीकी सहयोग के उपाय निकालने के हेतु मंत्रि-स्तर पर एक संयुक्त व्यवस्था की जाये।

(ख) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). जी हां। ईरान के शहंशाह और भारत की प्रधान मंत्री के बीच विचार-विमर्श के बाद 22 जनवरी, 1969 को भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए सम्मिलित भारत-ईरानी आयोग स्थापित करने के बारे में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था। इस करार में यह व्यवस्था है कि यह सम्मिलित आयोग दोनों सरकारों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी

सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। इस आयोग के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए उप-समितियां बनाई गई हैं जो दूसरे बातों के अलावा व्यापार, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरी उद्योग, बिजली और पानी के विकास और यातायात का काम देखेंगी।

Shri Manibhai J. Patel: Apart from the goods being exported at present, what additional goods are going to be exported which can benefit India?

Shri Dinesh Singh: Goods under various items are exported from our country. It is a long list. As to what other items can be exported, how we can improve trade between our two countries—for this very purpose this commission has been set up.

Shri Manibhai J. Patel: What are the items that are being exported?

श्री दिनेश सिंह : यदि आप चाहें, तो मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इसे सभा-पटल पर रख दिया जाये।

श्री नन्द कुमार सोमानी : भारत सरकार की ओर से निरंतर देरी तथा टाल-मटोल के परिणामस्वरूप ईरान के शहंशाह ने खास कर कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक मामलों को बढ़ावा देने के लिये एक संयुक्त तालिका बनाई जाये। इसे दृष्टि में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह संयुक्त तालिका महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे मीठापुर उर्वरक परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय करने के मामले में अपने लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य का तर्क सही नहीं है। माननीय सदस्य ने जिस तथाकथित देरी की ओर निर्देश किया है, यह आयोग उसको दूर करने के लिये स्थापित नहीं किया गया है। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिये बनाया गया है। किसी परियोजना विशेष के बारे में तो निर्णय हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ही करना है।

श्री एन० शिवप्पा : इस करार के पीछे क्या शर्तें हैं। हमारी पूंजी जो ईरान में लगाई जायेगी, ईरानियों की तुलना में हमारा उसमें क्या हिस्सा होगा ? वे हमें क्या पूंजी सहायता तथा तकनीकी जानकारी देने जा रहे हैं ? भारत और ईरान के बीच सहयोग के लिये एक पृथक आयोग स्थापित करने की बजाय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये सभी देशों के साथ सहयोग हेतु एक सांझा बोर्ड क्यों नहीं स्थापित किया जाता है ? ईरान को इस करार के अन्तर्गत क्या-क्या तैयार माल तथा कृषि वस्तुएं भेजी जायेंगी ? क्या चावल भी उनमें से एक है और यदि हां, तो क्या इससे देश में हमारी अनाज की आवश्यकता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह अब भी पूरी नहीं हो रही है ? क्या ईरान से कच्चा तेल भारत आएगा ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मुझे ठीक-ठीक नहीं समझा है। यह करार इन मामलों पर विचार करने के लिये किया गया है। इस तरह के मामले में सभी देशों

के साथ एक सांझा बोर्ड बनाने का प्रश्न है, विभिन्न देशों से हमारी बातचीत हुई है और क्षेत्रीय आधार पर भी। यह व्यवस्था काफी अच्छी तरह काम कर रही है। मेरी राय में सभी देशों के साथ एक सांझा बोर्ड स्थापित करने से इस समय कोई लाभ नहीं होने वाला है।

श्री कृ० मा० कौशिक : क्या इस करार में यह शर्त है कि इजराइल जैसे देशों के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कोई व्यापार करार नहीं किया जा सकता ?

श्री दिनेश सिंह : किसी अन्य देश के साथ सीधी बातचीत के रास्ते में इससे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

श्री रा० की अमीन : टाटा उर्वरक परियोजना के सम्बन्ध में हम ईरान से एमोनिया आयात करना चाहते थे और नमक का निर्यात करना चाहते थे। क्या हम कोई ऐसा करार कर सकते हैं जिससे हम ईरान में एमोनिया के निर्माण में भाग ले सकें और साथ-साथ अपने नमक का निर्यात करके ईरान में नमक पर आधारित रसायन उद्योग स्थापित कर सकें ताकि विदेशी मुद्रा का प्रश्न साथ-साथ हल हो जाये ?

श्री दिनेश सिंह : ठीक है। इस बारे में इस प्रकार का ही विचार-विमर्श किये जाने की आशा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आगामी वर्षों में कच्चे तेल की कमी.....

कुछ माननीय सदस्य : माननीय सदस्य का नाम प्रश्न पूछने वालों की सूची में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक ही दल के सभी सदस्यों को पुकारा जाय तो अन्य सदस्य आपत्ति करेंगे। मैं उनमें से चार को बुला चुका हूं। मैं अन्य सदस्यों को भी अवसर देना चाहता हूं। यदि सभी प्रश्न पूछने वालों को पुकारा जाये तो एक प्रश्न पर 15 मिनट लग जायेंगे। एक प्रश्न के लिये मैंने समय सीमा निश्चित की है। मुझे उसका पालन करना है। श्री पाणिग्रही बैठ जायें। मैं उन्हें बाद में बुलाऊंगा।

श्री रंगा : मुझे आशा है कि आपने जो कहा है वह आपका विनिर्णय नहीं है। क्योंकि आपको कार्य मंत्रणा समिति या विरोधी नेताओं से परामर्श किये बिना ऐसा विनिर्णय देने का अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सारा समय एक ही प्रश्न पर लगा दिया जाये ? एक प्रश्न को 10-12 मिनट से अधिक नहीं दिया जा सकता।

श्री रंगा : आपको माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए। यह मैं मानता हूं। परन्तु आप पुरानी परम्पराओं के विरुद्ध नहीं जा सकते।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यदि आप अब तक पालन की जा रही परम्परा से भिन्न रास्ता अपनाना चाहते हैं तो केवल दो सम्भावनाएं हो सकती हैं। एक यह है कि आप समय-सीमा

निर्धारित कर दें और उन सदस्यों को अवसर देते जायें जिन्होंने प्रश्न की सूचना दी है, चाहे वे एक दल के ही हों क्योंकि उन्होंने प्रश्न की सूचना दी है और प्रश्न काल में दल का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं । प्रश्न समय का है ।

श्री बलराज मधोक : मैं यह कहता आ रहा हूं कि प्रश्नकाल में कम से कम 10 प्रश्न लिये जाने चाहिए । परन्तु आप किसी एक दिन के लिये भिन्न प्रक्रिया नहीं अपना सकते । यह सब विरोधी दलों के नेताओं के सहयोग से किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो प्रश्नों की सूचना देते हैं उन्हें सामान्यतया अन्य प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री रंगा : सभा में जो प्रक्रिया रही है, उसी पर हमें चलना है । माननीय सदस्यों से परामर्श किये बिना आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते ।

Shri Sheo Narain : I have been a member of Legislative Assembly, Council and this Parliament. I want to submit that your authority is supreme. You have the right to regulate the proceedings of the House. But I think that the practice of clubbing 10-20 names in a question is not wholesome. You may call any Hon. Member who be standing in the House.

श्री देवकी नन्दन पादोदिया : इस समय ईरान के साथ भारत का व्यापार बहुत कम है और उसे बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि हम अपना निर्यात बढ़ायें । इस संदर्भ में ईरान ने भारतीय इंजीनियरी सामान आयात करने तथा भारत के सहयोग से ईरान में अनेक इंजीनियरी कारखाने स्थापित करने के लिये सहमति व्यक्त की है । क्या मैं जान सकता हूं कि ईरान के सहयोग से कौन से कारखाने स्थापित करने का विचार है और भारत से किस इन्जीनियरी सामान का निर्यात किया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : जैसाकि माननीय सदस्य को पता है, गत वर्ष भारत से ईरान को लोहे और इस्पात के निर्यात में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और हमें आशा है कि बहुत से अन्य सामान जैसे रेलवे उपकरण, ट्रांसमिशन टावर, दूर संचार उपकरण और अन्य निर्मित सामान जैसे पम्पों, इंजनों की ईरान में अच्छी मांग होगी । समिति ने अनेक उपसमितियां नियुक्त की हैं जो उन क्षेत्रों का पता लगायेंगी जिनमें सहयोग की आवश्यकता है और ऐसी वस्तुओं का भी पता लगाएंगी जिनमें दोनों देशों की रुचि है ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : क्या ईरान सरकार के साथ टाटा फर्टिलाइजर्स के सहयोग का कोई प्रस्ताव है ताकि ईरान से एमोनिया तथा अन्य कच्चा माल प्राप्त हो सके ? क्या मंगलौर उर्वरक कारखाने के बारे में भी ऐसा ही कोई प्रस्ताव है क्योंकि कच्चा माल—एमोनिया तथा पेट्रोलियम उत्पाद—ईरान से प्राप्त किया जाना है ? अन्य किन परियोजनाओं के लिये सहयोग प्राप्त करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : इस समय भारत की किसी फर्म विशेष के साथ किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने का हमारा कोई इरादा नहीं हैं। हम एमोनिया और उर्वरकों के निर्माण में भारत और ईरान के बीच सहयोग की सम्भावना पर बातचीत कर रहे हैं।

Shri Meetha Lal Meena: When is the first meeting of these sub-committees going to take place? Will they be held in Tehran or in Delhi? May I know the other countries with which such agreements have been concluded? Did we benefit from them or suffered any loss? If we have not benefited from them, what is the use of setting up these committees etc.?

Shri Dinesh Singh: I am surprised at the conclusion reached by the Hon. Member that we have not benefited from them. Such benefits have appeared in newspapers from time to time and mention has also been made in this House about them. So far as collaboration with Iran is concerned, these subcommittees have met twice in India. We hope that the Ministers of the two countries will be able to meet by May and by that time all their meetings would have been held.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या मीठापुर परियोजना के सम्बन्ध में सहयोग के बारे में भारत सरकार ने ईरान सरकार को उत्तर दे दिया है और क्या फर्म कमानीज को ईरान में विद्युत टावर आदि लगाने के कुछ ठेके दिये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक मीठापुर परियोजना का सम्बन्ध है, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इस पर हमने विचार करना है और किसी अन्य सरकार का बीच में आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जहां तक कमानीज का सम्बन्ध है, मेरी राय में उन्हें ईरान को ट्रांसमिशन लाईनें सप्लाई करने के लिये कुछ क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

श्री क० प्र० सिंह देव : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये श्री शिवप्पा के प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि इस समय एक विश्वजनीय तालिका (ग्लोबल पैनल) से क्या हानि है और प्रत्येक देश के लिये एक तालिका रखने से क्या लाभ है ?

श्री दिनेश सिंह : विदेश व्यापार मंत्रालय स्वयं एक विश्वजनीय तालिका है। यह विश्व के सभी देशों के साथ आर्थिक सहयोग के बारे में विचार-विमर्श करेगा। लेकिन मैं उस विशिष्ट विचार-विमर्श की बात कर रहा हूं, जिसके लिये समितियां बनाई गई हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri: May I know whether Government of Iran has invited some Indian industrialists to set up new industrial units in that country and if so, the results of the negotiations and when these units are likely to be set up?

Shri Dinesh Singh: I am not aware of any specific invitation by Government of Iran but I know that Government of Iran have said that they will certainly consider any offer to set up industries in Iran by Indians in collaboration with the local people or otherwise.

श्री स्वैल : क्या भारत और ईरान के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपाय के रूप में ईरान के शाह ने अपनी गत यात्रा के दौरान भारत सरकार को सुझाव दिया था कि सोवियत

संघ और पश्चिम यूरोप के लिये ईरान के जल और थलमार्ग से होकर एक नये परिवहन संचार मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई वचन दिया है ?

श्री दिनेश सिंह : विचार-विमर्श के दौरान हमारा ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि ईरान ने कुछ पत्तन सुविधाओं और परिवहन सुविधाओं का विकास किया है, जिनका सोवियत संघ और यूरोप को हमारा माल भेजने के लिये उपयोग किया जा सकता है। इस विषय पर हम विस्तृत रूप में विचार करेंगे।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know from the Hon. Minister a rough estimate of amount to be invested by Iran under the collaboration arrangements and what will be the estimated annual return thereon to Iran in the form of profit or interest ?

Shri Dinesh Singh : I am unable to follow the point made by the Hon. Member. It is too early to estimate profits since the discussions are going on. It can only be settled after discussions. Let the discussions proceed further. How can it be known in advance ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस समय विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के आयात पर प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देशीय अशोधित तेल के उत्पादन और तेल शोधक कारखानों की अशोधित तेल की आवश्यकता के बीच अन्तर बढ़कर एक वर्ष में 70 लाख टन हो जायेगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारत और ईरान के बीच वर्तमान सहयोग का लाभ उठाकर ईरान से भारतीय तेल कम्पनी के जरिये अशोधित तेल का सीधे आयात करने का विचार कर रही है ताकि हम विदेशी मुद्रा बचा सकें ?

दूसरी बात, ईरान के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले पेट्रो-रसायनिक उद्योग समूह में ईरान सरकार से हुई चर्चा के अनुसार ईरान सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को मालूम है कि अभी बैठक नहीं हुई है। मैं यह कैसे बता सकता हूं कि कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हम माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

समाचारपत्रों में एकाधिकार

+

*33. **श्री द० रा० परमार :** **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री बलराज मधोक :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों के एकाधिकार के बारे में अपनी नीति अन्तिम रूप

में निर्धारित कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार समाचारपत्र उद्योग में स्वामित्व के संचय के खतरे के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क है, जिससे विचार तथा मत का एकमार्गीकरण हो सकता है और जहां तक हो सकेगा वह इसे रोकने की कोशिश करेगी । इस दिशा में निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) प्रेस पंजीयक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के स्वामित्व का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन करता है और सांझे स्वामित्व वाले एककों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है तथा उन्हें "प्रेस इन इंडिया" में प्रकाशित करता है ताकि जनता को समाचारपत्रों के स्वामित्व के बारे में तथ्यों का पता लग सके ।

(2) प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत बनाए गये समाचार पंजीयन (केन्द्रीय), नियम 1966 के अन्तर्गत समाचारपत्रों के लिये समाचारपत्रों के मालिकों तथा उनकी कुल अंश पूंजी में एक प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखने वालों के बारे में प्रतिवर्ष फरवरी के अन्तिम दिन के बाद के प्रथम संस्करण में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है । इसका पालन न करना प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के अन्तर्गत एक अपराध हैं जिस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

(3) अखबारी कागज आवंटन नीति के अन्तर्गत नया प्रकाशन आरम्भ करने के लिये समाचारपत्रों के समूहों को अतिरिक्त अखबारी कागज नहीं दिया जाता है । अन्य शब्दों में, उन्हें नए प्रकाशन के लिये अपने वर्तमान कोटे पर ही निर्भर करना पड़ता है ।

(4) दिवाकर समिति की सिफारिश पर मुद्रण तथा कम्पोजिंग मशीनों के लिये उपलब्ध की जाने वाली कुल वार्षिक विदेशी मुद्रा में से 50 प्रतिशत छोटे पत्रों (15,000 कापियों की बिक्री तक), 35 प्रतिशत मध्यम समाचारपत्रों को (15,000 से 50,000 की बिक्री तक) और केवल 15 प्रतिशत बड़े समाचारपत्रों (50,000 से अधिक की बिक्री वाले) को दी जाती है।

(5) सरकार की विज्ञापन नीति का उद्देश्य समाचारपत्रों को बारी-बारी से विज्ञापन देने की है ताकि जहां तक संभव हो सभी पत्रों को विज्ञापन मिल सकें और बड़े पत्रों को ही अधिक सरकारी विज्ञापन न मिल सकें ।

(6) भारतीय प्रेस परिषद् का काम उन परिवर्तनों का अध्ययन करना है जिनसे समाचारपत्र उद्योग में एकाधिकार तथा स्वामित्व के संचय को बढ़ावा मिले। इस अध्ययन में समाचारपत्रों के स्वामित्व या वित्तीय ढांचे का अध्ययन भी शामिल है और यदि आवश्यक हो तो यह परिषद उसके लिये उपाय भी सुझाती है। कुछ समय पहले उन्होंने इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा जनता की राय जानने के लिये एक प्रश्नावली परिचालित की थी परन्तु कम संख्या में उत्तर प्राप्त हुए और वे उत्तर पूरे भी नहीं थे। इसलिये कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना बेकार था। फिर भी परिषद ने दोबारा प्रयत्न करने का निर्णय किया और एक उपसमिति नियुक्त की। परिषद ने यह महसूस किया कि इस समस्या के अच्छी तरह से अध्ययन के लिये जानकारी प्राप्त करने के मामले में उन्हें जो सुविधाएं तथा शक्तियां प्राप्त हैं उनके बारे में प्रेस परिषद अधिनियम में अनेक कमियां हैं। फिर भी परिषद ने उपसमिति से अपना काम करते रहने के लिये कहा है।

(7) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक पर, जिसके अन्तर्गत एकाधिकार तथा निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग स्थापित किया जायगा, संसद में विचार हो रहा है।

श्री द० रा० परमार : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने छोटे समाचारपत्रों की सहायता करने के बारे में कोई ठोस नीति अपनाई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा समाचारपत्रों की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार ने गुजरात राज्य के जनसत्ता तथा लोकसत्ता नाम के समाचारपत्रों को कोई वित्तीय सहायता दी है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

श्री इ० कु० गुजराल : प्रेस परिषद की सलाह के अनुसार सरकार ने इन समाचारपत्रों को कोई सहायता नहीं दी है। छोटे समाचरपत्रों की सहायता का प्रश्न सरकार ने सिफारिशों के लिये प्रेस परिषद को सौंपा और उनका सुझाव यह है कि एक प्रेस वित्त निगम इस तरीके से स्थापित किया जाय कि समाचारपत्रों की तथा पढ़ने वालों की स्वतन्त्रता बनी रहे। हमने उनसे इसका विवरण मांगा है।

श्री द० रा० परमार : सरकार ने श्री आर० आर० दिवाकर की अध्यक्षता में छोटे समाचारपत्रों के बारे में एक समिति नियुक्त की थी और उसका प्रतिवेदन प्रेस परिषद के पास है। क्या प्रेस परिषद ने कोई सिफारिश की है और यदि नहीं तो वह कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश करेगी?

श्री इ० कु० गुजराल : दिवाकर समिति की बहुतसी सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं तथा उसके कुछ भागों पर विचार हो रहा है।

Shri Yogendra Sharma : The Hon. Minister has now accepted the danger of regimentation due to monopoly of the Press. Will the Hon. Minister admit that the measures taken so

far in this direction are inadequate and they are having the opposite effect? What steps will be taken to review the same and to break the concentration?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं सदस्य महोदय से सहमत हूं कि अपनाये गये कार्यों से यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। ठोस कार्य तो सदन द्वारा एकाधिकार विधेयक के पास करने से ही होगा।

श्री स० चं० सामन्त : प्रेस परिषद अधिनियम के अनुसार प्रेस परिषद का कार्य समाचार पत्रों में एकाधिकार प्रवृत्तियों का पता लगाना है। क्या सरकार प्रेस परिषद द्वारा बताई गई इस बात पर विचार करेगी कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर सकी तथा प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन करके उसे दूर किया जायेगा?

श्री इ० कु० गुजराज : हमने प्रेस परिषद से इसके बारे में पूछा है। संसद् को भी प्रेस परिषद ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। हमने प्रेस परिषद को इनके अध्ययन करने तथा ठोस सिफारिशें करने को कहा है।

श्री बलराज मधोक : आधुनिक टेक्नालाजी के कारण बाकी उद्योगों की भांति समाचारपत्रों में भी छोटे समाचारपत्र समाप्त हो रहे हैं। दूसरे कुछ समाचारपत्रों पर राजनीतिक दलों का नियन्त्रण है। केवल कम्युनिस्ट पार्टी का नियन्त्रण 200 समाचारपत्रों पर है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस एकाधिकार को रोकने के लिये क्या कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह रोक प्रेस परिषद लगायेगी अथवा स्थापित किये जाने वाला एकाधिकार आयोग?

श्री इ० कु० गुजराल : सदस्य महोदय इस बात से बेकार परेशान हैं। इस समय देश में 10 बड़ी फर्में आधे से अधिक समाचारपत्रों की मालिक हैं। इसी प्रकार 62 मालिक 74.3 प्रतिशत समाचारपत्रों पर नियन्त्रण रखते हैं। इस कारण दिक्कत इनकी ओर से है। राजनीतिक दलों के समाचारपत्रों से खतरा नहीं है। एकाधिकार को रोकने के लिये सदन के सामने एकाधिकार विधेयक है तथा प्रेस परिषद ने अब तक अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं।

Shri Yashpal Singh: May I know whether it is a fact that additional special quota was given to those newspapers who took part in the strike and those newspapers were neglected who did not participate.

Shri I. K. Gujral: This is not correct. But it is a fact that they were given more newsprint so that they may print more newspapers but no decision has been taken regarding the quota of newsprint for those who participated in the strike.

श्री अनन्तराव पाटिल : मंत्री महोदय के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को मालूम है कि अखबारों के स्वामित्व का एकीकरण बढ़ रहा है और यदि हां, तो क्या उन्होंने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथा उन्मूलन विधेयक के अन्तर्गत अखबारों के एकाधिकार को शामिल कर लिया है जो कि शीघ्र ही प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ-साथ सभा के सामने आ रहा है? यदि नहीं, तो मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को अखबारों के

एकाधिकार को भंग करने की दिशा में 14 वर्ष पूर्व स्थापित प्रेस आयोग की सिफारिशों का पता है जिस पर कि अब तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री इ० कु० गुजराल : सरकार को प्रेस आयोग की 14 वर्ष पूर्व की गई सिफारिशों के बारे में मालूम है तभी तो इस समस्या के प्रति विचार उत्पन्न हुआ । तबसे यह सब कदम उठाये गए हैं । मैंने पहले ही कहा है कि एकाधिकारी विधेयक सभा के सामने अनिर्णीत पड़ा है और इस माननीय सभा ने इसके भाग्य का निपटारा करना है । मैंने पहले ही सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम अथवा उठाये गए कदमों के बारे में विवरण दिया है ।

Shri Bharat Singh Chauhan : According to the statement laid on the table of the House, those companies who do not submit their reports under registration of Papers Act are fined up to Rs. 500. I want to know the number of such papers who have not adhered to this rule and the number of those who have been punished under this rule.

श्री इ० कु० गुजराल : करीब सभी समाचारपत्र हमें यह सूचना देते हैं और हमारे पास अब तक की सूचना उपलब्ध है ।

Shri Prem Chand Verma : The two questions were asked in the statement laid on the table by the Hon. Minister, i.e. what is the policy of the Government to curb the monopoly and the time by which the decision will be taken in direction. These two questions have not been replied. I also want to know whether it is a fact that it was the opinion of the committee on the Press Council, that the bill of Monopoly Commission which is coming up before the Parliament is different as compared to the monopoly on newspapers, i.e. there is a difference between the monopoly of Industries and monopoly of newspapers. Whether Government are aware of this fact, if so, then will the Government institute a Committee on the Press monopoly for which the bill is coming, Government intend to consider the possibility of taking strong steps to curb the Press monopoly? I want a categorical reply from the Hon. Minister.

Shri I. K. Gujral : I have just stated that we asked the Press Council to intimate us the steps to be taken in this connection. We are ready to consider the steps as will be suggested by them. As far as the bill is concerned, it is the matter of Privilege of the House to decide what things should be included in it.

श्री उमानाथ : 1964 में एकाधिकारी आयोग ने यह पाया कि उद्योगपतियों के करीब 6 समूह काफी बड़े परिमाण में समाचारपत्रों के प्रसार पर नियंत्रण रखे हुए हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, और साथ ही विज्ञापनों पर एकाधिपत्य जमाए हुए हैं, उन्होंने कुछ समूह टाटा, बिड़ला, गोयनका, डालमिया, मफतलाल आदि के नाम बताए हैं, मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार एकाधिपत्य की निति के विरुद्ध है अतएव प्रतिबन्ध आदि लगाने के पक्ष में है । परन्तु व्यवहार रूप में मैं कुछ और ही देखता हूं कि सरकार के महत्वपूर्ण नेता स्वयं इस श्रंखला को और आगे बढ़ाने में संरक्षण दे रहे हैं । हाल ही में उपप्रधान मंत्री जी ने स्वयं "दी टाइम्स आफ इण्डिया" के गुजरात संस्करण का उद्घाटन करके इस समूह की श्रंखला में एक और नई कड़ी

जोड़ दी है। एक ओर तो सरकार कहती है कि वे एकाधिकार के विरुद्ध हैं परन्तु दूसरी ओर उपप्रधान मंत्री वर्तमान श्रंखला को और आगे बढ़ाने में संरक्षण दे रहे हैं । मैं इसका कारण जानना चाहता हूं कि सरकार के ऐसे महत्वपूर्ण नेता व्यवहार में समाचारपत्रों की श्रंखला में और अधिक विस्तार तथा और अधिक एकत्रीकरण को क्यों संरक्षण दे रहे हैं।

यह इसलिए है कि क्योंकि वे इस उद्योग पर नियंत्रण रखने वाले ये समूह काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस दल को धन देने वाले हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य सदा की भांति बेकार की बातों में बहक जाते हैं।

श्री उमानाथ : नहीं, यह बेकार की बातें नहीं हैं, यह ठीक बात है ।

श्री इ० कु० गुजराल : प्रश्न यह नहीं है कि क्या समाचारपत्र का उद्घाटन किया जाये या नहीं अपितु यह है कि क्या इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है या नहीं ।

श्री उमानाथ : परन्तु वे इस प्रकार के विस्तार का उद्घाटन करके इस प्रवृत्ति को उकसावा दे रहे हैं, ऐसा कहने में क्या तथ्य है, कि वे एकत्रीकरण के विरुद्ध हैं और इस पर कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं सभा के सामने यह मुख्य बात रख रहा हूं कि सरकार इस विस्तार और एकत्रीकरण को रोकने के लिए वचनबद्ध है। (**व्यवधान**) मेरे उत्तर देने के बाद अगर वे संतुष्ट नहीं हैं तो वे और प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री उमानाथ : परन्तु उन्हें प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ।

श्री इ० कु० गुजराल : उनको मेरे उत्तर देने से पूर्व पता चल जायेगा उससे पहले नहीं, जैसा कि मैंने कहा है कि मुख्य बात यह है कि एकीकरण रोकने की नीति के प्रति हम उतने ही वचनबद्ध हैं जितने कि दूसरे, इसलिए जो कदम हमने उठाये हैं वे हमने विवरण में दिये हैं, साथ में मैंने कहा है कि हमने प्रेस परिषद को विशिष्ट सिफारिशें देने को कहा है। हमने इस सभा में एक विधेयक पेश किया है···

श्री उमानाथ : मेरे प्रश्न के उत्तर को टाला जा रहा है।

श्री इ० कु० गुजराल : मुझे समाप्त कर लेने दो। हमने सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। हमने यह चिन्ता भी व्यक्त की है कि हमारे कार्यवाही को करने के बावजूद भी स्थिति नियंत्रण के बाहर है, अतएव इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम अग्रेतर कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या सरकारी अधिकारियों के समारोह में भाग लेने से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है या नहीं तो मैं कहूंगा कि यहां यह विषय नहीं है।

श्री उमानाथ : परन्तु यह तो मेरा प्रश्न है ।

श्री इ० कु० गुजराल : किसी नए समाचारपत्र को आरम्भ करने में कोई पाबन्दी नहीं है, प्रश्न यह है कि अगर यह प्रवृति चलती रही तो इससे हमें लाभ नहीं मिलेगा ।

श्री उमानाथ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । उनका कहना है कि प्रश्न यह नहीं है । और निश्चित ही यह मेरा प्रश्न है । जब सरकार कहती है कि वे उन श्रंखलाओं के अग्रेतर विस्तार और एकाधिकार और केन्द्रीकृत व्यवस्था के विरुद्ध है और जब उपप्रधान मंत्री जी, जो कि सरकार के महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं, वर्तमान श्रंखला में एक नई कड़ी जोड़ते जाते हैं तो यह दो बातें कैसे एक साथ चल सकती हैं । उनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है ? क्या इसलिए कि कांग्रेस दल को धन देने वाले बहुत हैं ? यह मेरा प्रश्न था । साथ ही विस्तार की दृष्टि से उस अखबार को और अधिक कोटा दिया गया है ? उन्हें सीधा उत्तर देना चाहिए ।

श्री इ० कु० गुजराल : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एक नया अखबार निकालना कानूनी दृष्टि से निषिद्ध नहीं है ।

श्री उमानाथ : ऐसा नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या यह इस प्रवृति को प्रोत्साहन नहीं देता है ?

श्री इ० कु० गुजराल : वे एक अच्छे साम्यवादी हैं । उन्हें बेकार की बातों की ओर ध्यान न देकर मूलभूत विषयों पर सोचना चाहिए । जहां तक कोटे का सम्बन्ध है, कोई भी अतिरिक्त कोटा नहीं दिया गया है ।

Shri P. L. Barupal : It is a matter of pleasure that the Hon. Minister has just stated that special quota was given to those newspapers who did not participate in the strike. But I want to know whether the quota, which was given daily for use to those newspapers who participated in the strike, but did not use the same, was given to those papers who published their newspapers on those days ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं सभा-पटल पर रखे गए विवरण के उप-पैरा (3) की ओर ध्यान दिला सकता हूं और मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि हड़ताल के बाद इन बड़े एकाधिकारियों को कितना अतिरिक्त अखबारी कागज दिया गया है ताकि वे परिशिष्ट निकाल कर शुद्ध लाभ कमा सकने में समर्थ हो सकें ? भार तथा मूल्य में इसका कुल परिमाण कितना है ?

श्री इ० कु० गुजराल : आवंटन मासिक नहीं वार्षिक होता है । अतः अप्रैल में हम इन बातों पर विचार करेंगे जब कि हम अपनी नयी नीति निर्धारित करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने अखबारी कागज का कोटा 59 दिन के बंद होने की क्षतिपूर्ति में दिया है । मैंने एक दिन टाइम्स आफ इंडिया का संस्करण खरीदा था जिसको भार

के रूप में बेचकर मुझे 8 आने मिले जबकि इसको समाचारपत्र के रूप में 18 पैसे का खरीदा था।

श्री इ० कु० गुजराल : हमने कोई अतिरिक्त कोटा नहीं दिया है, प्रश्न यह है कि अखबारी कागज का कोटा कम करना चाहिए या नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई अतिरिक्त कोटा दिया है।

श्री लोबो प्रभु : मुझे मंत्री महोदय या सभा को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक स्वतंत्र देश है। समाचारपत्रों के पढ़ने के सम्बन्ध में किसी पाठक को बाध्य नहीं किया जाता कि वह अमुक समाचारपत्र पढ़े। अगर पाठक कोई समाचारपत्र उसकी विशेषताओं के कारण पढ़ना चाहता है तो मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह इस विशेषता के एकाधिकार के कारण नहीं है ? जब तक यह देश स्वतंत्र है तब तक आप पाठक का मुंह बन्द नहीं कर सकते अथवा समाचारपत्र पढ़ने के उसके अधिकार पर पाबन्दी नहीं लगा सकते। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को एकाधिकार के दुरुपयोग के बारे में कुछ मालूम हुआ है ? क्या ऐसे समाचारपत्र सामने आये हैं जो किसी विशेष विचारों को फैला रहे हैं और जो कि देश के लिए घातक हैं ? यदि नहीं तो सरकार का इस निर्णय पर पहुंचने का औचित्य क्या है कि समाचारपत्रों का एकाधिकार ठीक नहीं है ?

श्री इ० कु० गुजराल : अगर आखिरी प्रश्न का पहले उत्तर दिया जाये, तो सरकार ने प्रेस आयोग और प्रेस परिषद की सिफारिश पर अपना निर्णय निकाला है। जहां तक पाठक की स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके पास चुनाव करने के लिए विभिन्न पाठन सामग्री है और यह उसके चुनाव करने की शक्ति को सीमित करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम उसके पाठन सामग्री के चयन करने के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिले। अगर जो हो रहा है, उसको ऐसे ही चलने दिया जाये तो पाठकों की स्वतंत्रता इन 62 या 10 समूहों तक सीमित हो जायेगी।

Settlement of Kachchativu Issue

*34. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Hem Raj :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri George Fernandes :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri M. N. Reddy :
Shri Onkar Singh :
Shri Samar Guha :
Shri Kameshwar Singh :
Shri Rabi Ray :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Bhola Nath Master :
Shri K. Lakkappa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Ceylonese Prime Minister made a statement at Karachi on his way to the Commonwealth Prime Ministers' Conference to the effect that the question of the 'Kachchativu' had been settled ;

(b) whether the statement cited above is correct ; and

(c) if so, the details regarding the agreement reached in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) (a) to (c). Government understand that during a brief stop-over while on his way to London, to attend the Commonwealth Prime Ministers' Conference, the Prime Minister of Ceylon in answer to a question by pressmen whether he would take up the Kachchativu issue at the Conference stated that he would not do so as the matter was being mutually settled by the Governments concerned—Ceylon and India.

Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Prime Minister be pleased to state whether any solution has been found in the discussion between the Prime Ministers and Foreign Ministers on the issue of Kachchativu ?

Shri Dinesh Singh : No solution has yet been found and the talks are going on.

Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Hon. Minister be pleased to state whether the Government of India have scrutinized their record in respect of the Kachchativu Island and map or not so that like other incident some other event may not take place on this question.

Shri Hem Raj : Will the Prime Minister be pleased to state whether the Government have examined the statement of the Prime Minister of Ceylon regarding Kachchativu, in which he stated that there has been a compromise regarding this between the two countries ?

Shri Dinesh Singh : No Sir, there has been no compromise yet.

Shri George Fernandes : I want to know from the Prime Minister whether the Government have any doubt in their mind about Kachchativu which is a part and parcel of India.

Shri Dinesh Singh : Much discussions had taken place on it in the last session of Parliament and it was decided that both countries should have talks regarding this. At present it is difficult for me to go in details regarding this subject when the talks are going on between the two countries. But if any member wants to give me any suggestion, he can do so with pleasure.

Shri George Fernandes : My question is clear and the Hon. Minister may reply it directly. I am asking Government of India and not from the Foreign Minister of Ceylon. I want to know whether the Government have any doubt in their mind about Kachchativu which is a part and parcel of India ? My question may be replied clearly.

Shri Dinesh Singh : I have no doubt about it when talks are going on between the two countries. There was no meaning in having talks when we had any doubt in it. When the talks are going on between the two countries.....

Shri Hukum Chand Kachwai: You declare that it belongs to us.

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है । आप उन्हें यह आदेश नहीं दे सकते कि वह अमुक शब्दों में उत्तर दें ।

Shri Madhu Limaye : He has asked whether I had any doubt **(interruption).** We should get a clear reply. He should not give a vague reply.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने उत्तर में बात स्पष्ट कर दी है। अब वह यहीं समाप्त करें।

Shri Rabi Ray : We are not getting any reply. It is the question of country's integrity.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझते हैं कि उन्हें टाल दिया गया है; जबकि मंत्री महोदय ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने उत्तर दिया है। आप उन्हें इस पर बाध्य नहीं कर सकते कि वह उन्हीं शब्दों और उसी भाषा में उत्तर दें।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister has now come from the Commerce Ministry. He should do something good. How can it go like that ?

Shri S. M. Joshi : We are the Members of this House and you have to protect our rights. We are asking a straight reply as to whether there is any doubt or not. We want a hypothetical answer.

उपाध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि हम बात चीत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वह हमारा है...(**व्यवधान**)।

Shri Madhu Limaye : When they are negotiating, that means there is some doubt.

Shri S. M. Joshi : And that also means that they are prepared to give it up.

Shri Kanwar Lal Gupta : This matter has been hanging on since long. I believe, Government want to delay it deliberately because on one hand they do not want to displease the Ceylon Government and on the other they fear the Iindian public opinion. They are following a delaying policy. I want to know the present position of the case and also the stage which it has reached so far ? Have you discussed the matter with the Celonese Prime Minister ?

My second question is whether our patrolling, pending the settlement, is going on, there, and also what arrangements have been made in connection with the festival which is going to be held there in the coming March, since people had to keep sitting on bank itself for many days last year ?

Shri Dinesh Singh : As regards the arrangement for the pilgrims going there, we are negotiating with Ceylonese anthorities as to what facilities will be accorded by them to the pilgrims from India as well as Ceylon side.

About the question of delay, I want to say that it is not being done from our side. We are having talks and quite a number of things are considered. Both sides put their case. But neither we nor they like to delay the matter.

Shri Kanwar Lal Gupta : I have asked whether our patrolling, pending the settlement, has been going on, or not ? What further talks did you have ?

Shri Dinesh Singh : In the very beginning I have said that we had talked to the Ceylonese Prime Minister.

As regards patrolling, it is going on as it should have been.

श्री ए० नारायण रेड्डी : आज प्रातः के समाचार-पत्रों में समाचार है कि श्रीलंका सरकार तस्करी और श्रीलंका आने वाले यात्रियों पर निगाह रखने के लिये अपने विमान और हैलीकोप्टर गश्ती उड़ानों पर भेज रही है। क्या श्रीलंका सरकार के लिये ऐसी उड़ाने आयोजित करना उचित है जबकि इस समस्या का समाधान करने के बारे में दोनों सरकारों के मध्य बात-चीत चल रही है ? क्या इसका अभिप्राय यही है कि भारत की ओर से इस द्वीप पर की जा रही गश्त को रोका जाये अथवा उसमें बाधा डाली जाये ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं, इसका अर्थ हमारे द्वारा की जा रही कार्यवाही को रोकना नहीं है। समाचार-पत्र पढ़कर मुझे तो यही अनुभव हुआ है कि इसका ध्येय यह प्रतीत होता है कि श्रीलंका सरकार इस बात का निश्चय करना चाहती है कि अगले मार्च में होने वाले मेले से किसी अनधिकृत यात्री को वहां घुस आने का अवसर न मिले। हम इस मामले पर भी बातचीत करेंगे।

Shri Rabi Ray : My point is whether the attention of the Hon. Minister has been drawn towards the news items in today's Statesman—I read it out first here :

> "All pilgrims visiting Kachchativu island for the annual St. Anthony's festival in mid-March will have to obtain special permits from the Government to undertake the pilgrimage."

Then, will the Indian pilgrims also have to obtain such permits from the Government of Ceylon ? I want to know whether or not there is any restriction on Indian pilgrims ?

Shri Dinesh Singh : Let him kindly read a bit more and it will be clear to him. These restrictions are for the Ceylonese citizens who will have to show this permit when they return to Ceylon and so that the Ceylonese authorities may ensure that no undesirable people have come in.

Shri Rabi Ray : I want to know that the Officers deputed there will be of Government of India or of Ceylon ? Last year they were from Ceylon.

Shri Dinesh Singh : The House is aware that officer's from both sides have been going there from time to time.

Shri Rabi Ray : What are the arrangements this year ?

Shri Dinesh Singh : That is what we are negotiating about.

श्री रामावतार शर्मा : जब यह सिद्ध करने के लिये कि कच्चाटीवू का स्वामित्व हमारे पास रहा है तथा उसका नियन्त्रण हमारे हाथ रहा है, पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण हैं, तो फिर बजाय यह कहने के कि यह हमारी सम्पत्ति है सरकार ने यह स्थिति क्यों स्वीकार की है कि वह एक विवादग्रस्त क्षेत्र है ? यदि सपकार के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं तो मेरे हाथ में पर्याप्त सामग्री है। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि मैं इसे सभा-पटल पर रखने को तैयार हूं। इन पत्रों की एक प्रति प्रधान मंत्री को भी भेजी गई थी। सरकार ने यह कैसे और क्यों स्वीकार कर लिया कि यह एक विवादग्रस्त क्षेत्र है ?

श्री दिनेश सिंह : आपको ज्ञात होगा कि इस बारे में पहले ही सदन में विचार किया जा चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कुछ स्वीकार किया है। यह तो ऐसा मामला है जिस पर भारत और श्रीलंका सरकारों के मध्य स्वतन्त्रता से भी पहले से बातचीत चली आ रही है।

Shri Bhola Nath Master: This misunderstanding has cropped up since our Prime Minister has stated "that the Kachchativu Island issue has been settled between Ceylon and India."

But the Hon. Minister has just now stated that the talks in this connection are still going on. So what do you say about this contradiction. May I know whether this matter has been settled or it is still pending?

Shri Dinesh Singh: It has not yet been settled.

श्री क० लकप्पा : क्या मैं भारत के प्रधान मंत्री से एक सीधा और विशिष्ट प्रश्न पूछ सकता हूं ? कच्चाटीवू के बारे में विदेशी भी वक्तव्य दे रहे हैं। अभी हाल ही में जब पाकिस्तान के कानून मंत्री कच्चाटीवू से गुजरे तो उन्होंने भी यह कहा कि कच्चाटीवू श्रीलंका का है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि कुछ विदेशी एजेंसियां यह प्रयत्न कर रही हैं कि कच्चाटीवू द्वीप के बारे में श्रीलंका को ही वरीयता तथा अधिकार मिले ? सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? जब पाकिस्तानी कानून मंत्री ने कच्चाटीवू द्वीप पर श्रीलंका का हक बताया तो क्या सरकार ने इस बारे में विरोध प्रकट किया ? मैं जानना चाहूंगा कि जहां तक बातचीत का सम्बन्ध है, इस बारे में सरकार का क्या आशय है कि यह द्वीप भारत का है ?

श्री दिनेश सिंह : पाकिस्तानी मंत्री के वक्तव्य के बारे में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जिस विषय पर हम श्रीलंका से बातचीत कर रहे हैं उस बारे में कोई वक्तव्य देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इस बारे में हमने अभी हाल ही में विचार-विमर्श किया है। यह हमारी धारणा है और यही धारणा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से भी रही है कि यह भूभाग भारत का है। माननीय सदस्य ने भविष्य के बारे में बात की है। जब हम उस सरकार से बातचीत कर रहे हैं तो इस प्रश्न पर टिप्पणी करना मेरे लिये कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारापुर अणु बिजलीघर

*35. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनको तारापुर अणु बिजली घर के निर्माण में कुछ त्रुटियों के बारे में एक

संसद् सदस्य से व्याख्या-पत्र सहित एक नोट प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस नोट की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या निर्माण में इन त्रुटियों से तत्काल या बाद में सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि निर्माण फर्में करार के अनुसार सुरक्षा उपाय जल्दी से जल्दी पूरे करें ; और

(ङ) अणु बिजलीघर कब तक चालू हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर के कुछ घटकों में पाये गये दोषों की ओर इस नोट द्वारा ध्यान खींचा गया है । इसमें सुझाव दिया गया है कि प्लांट के प्रचालन के दौरान भारत सरकार के हितों को सुरक्षित रखने तथा प्लांट की सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए कदम उठाने के लिए समुचित समाश्वासन प्राप्त किया जाये ।

(ग) तथा (घ). आवश्यक मरम्मत सप्लायर के खर्च पर की गई है जो परमाणु ऊर्जा आयोग को उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीकी मशवरे के अनुरूप है । इस मरम्मत के लिए जो मानदंड अपनाया गया वह ऐसी ही अवस्था में अन्यत्र कहीं भी अपनाये जाने वाले मानदंड से कम कठोर नहीं था । कोई भी रिऐक्टर तभी चालू किया जाता है जब वह सुरक्षा के लिए आवश्यक कसौटी पर खरा उतरता हो ।

(ङ) बिजलीघर का पहला रिऐक्टर 1 फरवरी, 1969 को क्रिटिकल हुआ । आशा है कि 380 मैगावाट क्षमता की पूरी क्षमता से बिजलीघर में व्यावसायिक रूप से बिजली का उत्पादन इस वर्ष जुलाई मास में शुरू हो जायेगा ।

नेपाल में चीनियों द्वारा 'इण्डियन एक्सप्रेस' के मुख्य सम्पादक का रोका जाना

*36. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री श्रीधरन :
श्री रा० वें० नायक :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० सुशीला नैयर :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 में 'इण्डियन एक्सप्रेस' के मुख्य सम्पादक जब

नेपाल गये, तो उन्हें चीनी राष्ट्रजनों द्वारा रोक लिया गया था तथा अपमानित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हमारी सूचना के अनुसार नेपाल में काम करने वाले कुछ चीनी तकनीशियनों ने मुख्य सम्पादक महोदय को काठमांडू-कोडारी रोड पर रोक लिया था और उन्हें तंग किया था।

(ख) इस मामले को नेपाल अधिकारियों के साथ तुरन्त उठाया गया था।

नागा विराम-संधि की अवधि

*37. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा युद्ध-विराम की अवधि और आगे बढ़ा दी गई है और यदि हां, तो कब तक के लिये और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों में नागालैंड की शांतिपूर्ण स्थिति में और आगे कुछ सुधार हुआ है और यदि हां, तो कितना और स्थिति में और आगे सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). नागालैंड में कुल स्थिति का जायजा लेने के बाद, नागालैंड के राज्यपाल ने कार्यवाई बंद रखने की अवधि 28 फरवरी, 1969 तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य सरकार शत्रुतापूर्ण कार्यवाइयों का प्रतिकार करने के लिए और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कारगर कदम उठा रही है। पिछले कुछ महीनों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

चलचित्रों का निर्यात

*38. **की वि० ना० शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में अब तक कितने देशों को भारतीय चलचित्रों का निर्यात किया गया;

(ख) देशवार तथा वर्षवार कितने चलचित्रों का निर्यात किया गया; और

(ग) प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :

	वर्ष	देशों की कुल संख्या
(क)	1966-67	89
	1967-68	94
	1968-69 (अक्टूबर 1968 तक)	104

(ख) भारतीय फिल्मों का लगभग 100 देशों में निर्यात किया गया। 1966-67 में 621 फिल्में निर्यात की गईं। 1967-68 तथा 1968-69 के आंकड़े रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से एकत्र किये जा रहे हैं।

(ग)	वर्ष	कमाई गई विदेशी मुद्रा
	1966-67	1.35 करोड़ रुपये
	1967-68	3.89 करोड़ रुपये
	1968-69 (अक्टूबर 1968 तक)	1.55 करोड़ रुपये

Plan Outlay of Delhi

*39. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri M. L. Sondhi :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5014 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether the proposal of the Delhi Administration relating to the Plan have since been considered ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether any increase would be made in the plan-outlay in view of the special position of Delhi ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) Plan outlays have not yet been finalised.

(c) All relevant considerations will be kept in view.

पाकिस्तान के लिये रूस के 'मिग' विमान

*40. **श्री वेदव्रत बरुआ :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **डा० कर्णी सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा पाकिस्तान को 'मिग' विमान सप्लाई करने के प्रस्ताव की सरकार

को जानकारी है जैसा कि विभिन्न समाचारपत्रों में बताया गया है;

(ख) क्या इन दोनों देशों के बीच इस संबंध में करार भी हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या सरकार ने रूस सरकार के साथ इस बारे में बातचीत की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

निजी थैलियों के बारे में लार्ड माउन्टबैटन का पत्र

*41. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री किकर सिंह :
श्री गणेश घोष :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री उमानाथ :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लार्ड लूई माउंटबैटन ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें सुझाव दिया गया है कि भूतपूर्व राजाओं को निजी थैलियों के बारे में दिये गये आश्वासनों को पूरा किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या लार्ड लूई माउंटबैटन को उत्तर भेज दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों के बारे में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय लिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). डेढ़ वर्ष हुआ प्रधान मंत्री को लार्ड माउंटबैटन से राजाओं की निजी थैलियों के प्रश्न के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ था। लार्ड माउंटबैटन की इच्छानुसार यह उनका 'बिल्कुल निजी' पत्र है। इसलिए सदन यह मानेगा कि इस पत्र में लिखी बातों को बताना उचित न होगा।

इस प्रश्न पर सरकार ने नीति संबंधी जो निर्णय लिया है वह बिल्कुल उसके अपने विचार के आधार पर है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने सिद्धांत रूप से निर्णय लिया है कि राजाओं की निजी थैलियों को समाप्त किया जाए।

आकाशवाणी में करनाटक संगीतज्ञ

*42. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करनाटक संगीत के कुछ उच्च प्रभावशाली संगीतज्ञ अब भी आकाशवाणी में ख–उच्च श्रेणी में ठेके पर काम कर रहे हैं और उन्हें 65 रुपये रायल्टी मिलती है;

(ख) इस बात को देखते हुए कि वे अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं और उनकी सेवा से संगीत को बढ़ावा मिल रहा है उन संगीतज्ञों को कब से अधिक रायल्टी मिलनी शुरू हो जायेगी; और

(ग) क्या केन्द्र निदेशकों के दिल्ली में हाल में हुए सम्मेलन में इस सम्बन्ध में किन्हीं विशिष्ट विषयों पर बातचीत हुई थी ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसारणों के लिये संगीतज्ञों की दरें, उनकी कला प्रदर्शन के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। कलाकारों को कला प्रदर्शन की जांच के लिये आकाशवाणी के पास एक स्वर परीक्षा पद्धति है। यदि आर्टिस्ट चाहें तो अपने दर्जे को बढ़ाने के लिये पुनः स्वर परीक्षा देने के लिये आवेदन कर सकते हैं और यदि वह इस परीक्षा के आधार पर उच्च दर्जे के लिये खरे उतरते हैं तो उन्हें ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है और उनकी दरें भी तदनुसार बढ़ा दी जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

केरल के लिये केन्द्रीय सहायता

*43. **श्री एस्थोस :**

श्री सी० के० चक्रपाणि :

श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल को केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि का नियतन करने का विचार है;

(ख) 1969-70 की वार्षिक योजना के लिए केरल के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ग) क्या मुख्य मंत्री ने यह लिखा था कि चौथी योजना में केरल के लिए नियत की गई केन्द्रीय सहायता की राशि अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). धनराशियों के नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Creation of Mallapuram District in Kerala

*44. **Shri Jagannath Rao Joshi:** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a delegation from Kerala has drawn the attention of Government to the defence problems arising out of the proposed creation of Mallapuram District ; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). A few persons from Kerala, accompanied by a Member of Parliament, expressed to the Defence Minister their concern over the proposed creation of Mallapuram District. It was explained to them that the creation of this District may not have any serious implications at present purely from the defence point of view, but it may affect the law and order situation.

Negotiations with China

*45. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to start dialogue with China for the settlement of disputes between the two countries as mentioned by her in a Press Conference on the 1st January, 1969 ;

(b) if so, the basis on which dialogue would be started ; and

(c) the reaction of China thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). Government's position is clear. We are willing to talk with China on a basis consistent with India's territorial integrity, sovereignty and national honour. The Prime Minister once again reiterated this position at the Press Conference held on 1st January, 1969.

(c) There has been no response from China.

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय परिव्यय

*46. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री हीरेन मुकर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने चौथी योजना के लिये केन्द्रीय परिव्यय की कितनी राशि का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या यह सच है कि कई मुख्य मंत्रियों ने चौथी योजना के कुल परिव्यय में राज्यों के लिए अधिक हिस्से की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्रियों की मांगों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय परिव्यय में कमी करने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है । योजना का मसौदा शीघ्र ही राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने पेश किया जाने वाला है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कुल मिलाकर राष्ट्रीय योजना, सरकारी क्षेत्र की योजना, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के आकार का प्रश्न शीघ्र ही राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने निर्णय के लिए पेश किया जायेगा ।

आकाशवाणी से हिन्दी समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन के बारे में तमिलनाडू सरकार का विरोध

*47. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री जनार्दनन :
श्री नम्बियार :
श्री अनिरुद्धन :
श्री रमानी :
श्री सेझियान :
श्री देवराव पाटिल :
श्री इ० के० नायनार :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडू सरकार ने आकाशवाणी के प्रातःकाल के समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन किये जाने पर विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तमिलनाडू के मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में उनसे भेंट की थी; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ग). तमिलनाडू सरकार से कोई औपचारिक विरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, तमिलनाडू सरकार के स्वर्गीय मुख्य मंत्री तथा सूचना मंत्री ने इस बारे में अनौपचारिक रूप से उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री से बातचीत की थी जिन्होंने इस निर्णय की पृष्ठभूमि तथा इस बारे में भारत सरकार की नीति को स्पष्ट किया था ।

काश्मीर के बारे में मध्यस्थता करने के लिये ईरान के शाह का प्रस्ताव

*48. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान के शाह ने हाल ही की अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत तथा पाकिस्तान के बीच काश्मीर तथा अन्य प्रश्नों पर मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के लिये निगम

*49. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चन्दा समिति की आकाशवाणी को एक स्वायत निगम के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के संचालन के लिये एक प्रशासी बोर्ड गठित करने का है जिसके अधीन आकाशवाणी को अपने कार्य संचालन में इस समय से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और सरकार ने आकाशवाणी के संचालन के लिये किस आधार पर प्रशासी बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ग). इस बारे में चन्दा समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं और आकाशवाणी के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

ब्रिटेन में आप्रवासियों का प्रवेश

*50. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने 10 जनवरी, 1969 के लगभग राष्ट्र-मण्डल के देशों को चेतावनी दी है कि वह न केवल उन देशों से आप्रवासियों की संख्या सीमित करेगी बल्कि ब्रिटेन में आप्रवासियों के आने को रोकने के लिये कड़े उपाय भी लागू करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या विशिष्ट सूचना दी गई है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 10 जनवरी, 1969 को या उसके आस-पास यूनाइटेड किंगडम की सरकार की ओर से इस तरह की कोई चेतावनी या सूचना नहीं मिली थी। लेकिन, ब्रिटिश सरकार ने 29 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली स्थित अपने हाई कमीशन के जरिए हमें यह सूचना दी कि राष्ट्रमण्डल देशों के पतियों और पुरुष नागरिकों को अपनी पत्नियों और भावी पत्नियों के पास जाकर हमेशा के लिये बसने की जो रियायत दी जाती है, वह अब नहीं दी जायेगी। भारत सरकार ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार को अपनी इस आशंका से अवगत कराया था कि इस प्रतिबन्धात्मक उपाय से परिवारों में विछोह को जायेगा।

Supply of Russian Transmitters to Pakistan

*51. **Shri Bans Narain Singh:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of U. S. S. R. propose to supply high power transmitters to Pakistan ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Information, and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narain Sinha): (a) Yes, Sir. There have been press reports to this effect.

(b) Government is taking steps to improve All India Radio's services—both domestic and external.

Violations of Indian Territory by Pakistan and China

*52. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of times China and Pakistan have violated Indian territory by land, air and sea during the past three months ;

(b) the number of persons arrested by the Indian Security Force and Border Security Force for committing these violations during the same period ;

(c) whether any protest notes etc., were sent to the Governments concerned in this connection ;

(d) if so, the reaction of the Governments concerned thereto ; and

(e) the steps taken by the Government of India to check these violations ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Between 1st November 1968 and 31st January 1969, Pakistani armed personnel committed the following intrusions into our territory:—

Land Violations	Air Violations	Sea Violations
15	7	Nil

There were no intrusions by Chinese personnel during this period.

(b) No Pakistan armed personnel were apprehended on these occasions.

(c) and (d). Protests have been lodged with the Pakistan authorities at local and Central Government levels. Intrusions across the Cease-fire Line have been taken up with the U. N. Observers. No replies have been received from the Government of Pakistan on the protests lodged through diplomatic channels.

(e) Our Security Force continue to be vigilant on the border.

रोडेशिया के साथ व्यापार

*53. **डा० रानेन सेन :**

श्री जागेश्वर यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाये जाने के निर्णय के बावजूद वह अनेक देशों से व्यापार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय रोडेशिया के साथ मुख्यत: कौन-कौन देश व्यापार कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध लगाये गये प्रतिबन्धों का कठोरता से पालन कराने की दृष्टि से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दक्षिण रोडेशिया पर लगाये गये प्रतिबन्धों के अमल की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो समिति बनाई थी उसने रिपोर्ट दी है कि दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी रोडेशिया का प्रमुख व्यापारिक साझीदार बन गया है। इस समिति ने इस बात की भी टिप्पणी की है कि पुर्तगाल ने दक्षिण रोडेशिया से माल के बेरोकटोक आने-जाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर अमल किया है और इस बात पर समर्थन करती रही है कि दूसरे देश भी इस प्रस्ताव पर सख्ती से अमल करें।

एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी

*54. **श्री नंजा गौडर :**

श्री जि० मो० विस्वास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सेवामुक्त किये गये एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको केन्द्रीय सरकार की सहायता से वैकल्पिक सेवा मिल गई है ;

(ख) कितने अधिकारियों को अभी वैकल्पिक सेवा पर नियुक्त किया जाना शेष है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार ने उन अनेक अधिकारियों को होने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाया है जिनको अभी तक वैकल्पिक सेवा नहीं मिली है ; और

(घ) सेवामुक्त एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उपदान, पेंशन आदि के रूप में यदि कोई प्रतिकर दिया गया है तो, कितना ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). चिकित्सा तथा वैटेरिनरी अफसरों को छोड़कर कि जिनके पुनरावास की कोई समस्या नहीं है। आपात स्थिति के दौरान भर्ती किये गये आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की कुल संख्या 9087 थी। इस हिसाब से 76, कि जिन्हें अल्पकालीन कमीशनें दी गई थीं, 11, कि जो रिमाऊंट तथा वैटेरिनरी कोर में तबदील किये गये थे, और 150, कि जो मारे गये या अन्यथा निधन प्राप्त हुए, को छोड़कर 8850 ई० सी० ओज० के स्थायी कमीशन प्रदान किये जाने या पुनरावास के अन्य तरीकों के लिए, विचारे जाने की आवश्यकता थी। चूंकि ई० सी० ओज० की विमुक्ति दलों में हस्तगत की गई है, अब तक 5067 के सम्बन्ध में विचार किया गया है। इनके सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

संख्या जिसे पी० सी० प्रदान की गई	1821
अन्य सरकारी तथा राजकीय संस्थाओं में पुनरावासितों की संख्या	1728
आंकड़े	
यू० पी० एस० सी० परीक्षा के फलस्वरूप	73
आई० ए० एस० इत्यादि	—
एन० सी० सी०	416
प्रादेशिक सेना	13
बी० एस० एफ० और अन्य केन्द्रीय पुलिस दल	602
अन्य केन्द्रीय सरकारी सेवाएं और स्थान	84
राज्य सरकारी सेवाएं और स्थान	57
राजकीय क्षेत्र के उपकरण	78
निजी क्षेत्र	143
असैनिक स्थानों को वापस	213
निजी रोजगार	49
	1728

संख्या जिसे पुनरावास की आवश्यकता है	920 (70, को छोड़कर जो अनुशासनिक कारणोंवश विमुक्त किये गये, और उनको छोड़कर जिन्होंने त्याग-पत्र दिये, और नान आप्टी के तौर पर विमुक्त किये गये)

मुख्य मंत्रियों/राज्य के राज्यपालों/संघीय क्षेत्रों से हाल ही में प्रार्थना की गई है कि वह ई० सी० ओज० को अपने राज्यों में राज्य सेवाओं/पदों और उनके अधीन राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों में पदों पर खपाए। यथासम्भव अधिकतम विमुक्त ई० सी० ओज० को खपाने के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन राजकीय क्षेत्र के उपकरणों से सम्बन्धित संघीय मंत्रियों से भी प्रार्थना की गई है।

सरकार समस्या के प्रति सजग है, और इससे निपटने के लिये उसने विभिन्न पग उठाये हैं। समय-समय पर इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न उपायों की सदन में घोषणा की गई है।

(निर्योग्य, अवर श्रेणियों से कमीशन प्राप्त, और उनको छोड़कर जो स्थायी असैनिक सरकारी सेवा में हैं) विमुक्त किये गये आपाती कमीशन प्राप्त अफसर सेवा के प्रति सम्पूर्ण वर्ष के लिये 1,000 रुपये की दर से अन्तिम उपदान के अधिकारी हैं। अगर उनकी कुल सेवा सम्पूर्ण वर्षों से 6 मास या अधिक हो तो उस अवधि के लिए 500 रुपये का अतिरिक्त उपदान भी देय है। जो अवर श्रेणियों से कमीशन दिए गये हैं वह चयन कर सकते हैं या तो संगत नियमों के अन्तर्गत देय सेवा की पेन्शन, या अन्तिम उपदान का लाभ। वह ई० सी० ओज० जो कमीशन प्रदान किए जाने से पहले उन द्वारा धारण किए गए स्थान को वापस लौटते हैं, किसी प्रकार की सैनिक पेन्शन या उपदान के अधिकारी नहीं, परन्तु ई० सी० ओज० के तौर पर उनकी सेवा असैनिक पेन्शन के लिए गण्य होगी।

बेरुबाड़ी

*55. **श्री दे० अमात,**

श्री गु० च० नायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरुबाड़ी में सीमांकन कार्य पर विचार-विमर्श करने के लिये दिसम्बर, 1968 में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की कलकत्ता में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान क्षेत्र कार्य मौसम में सीमांकन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिये 27 और 28 दिसम्बर, 1968

को कलकत्ता में पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के भूअभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशकों की बैठक हुई थी। जहां तक बेरुबाड़ी संघ संख्या 12 का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के भूअभिलेख निदेशक ने इसमें सीमांकन के काम को शुरू करने में अपनी असमर्थता प्रकट की क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील पेश होने की वजह से यह मामला न्यायाधीन है।

Backwardness of Garhwal

*56. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether after her last tour of Garhwal, she had stated that the living standard of the people of the hilly areas was extremely low even twenty years after the Independence;

(b) if so, whether Government are thinking of formulating any concrete scheme to raise their living standard; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) The Prime Minister said that while a good deal of development had taken place, there was still much work to be done to develop the hilly regions and raise the living standards of the people there.

(b) Yes, Sir. The needs and potentialities of the areas are being kept in view by the State Government under the general guidance of the Planning Commission, while formulating the Fourth Plan schemes.

(c) Does not arise.

भूटान को वित्तीय सहायता

*57. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने 1968-69 में भूटान को कितनी वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है जिससे उसकी राजस्व स्थिति सुदृढ़ हो सके तथा उसका आर्थिक तथा औद्योगिक विकास हो सके और वहां पर हाल में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भूटान सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार निम्नलिखित राशि देने पर राजी हो गयी है :

(1) विकास कार्य के लिए आर्थिक सहायताएं—4 करोड़ 27 लाख रुपये।

(2) बाढ़-पीड़ितों की सहायता-कार्यों के लिये—20 लाख रुपये।

अखबारी कागज बनाने के कारखाने

*58. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में कुल कितनी संख्या में अखबारी कागज बनाने

के कारखाने स्थापित किये जायेंगे, उनके प्रस्तावित स्थान कहां-कहां होंगे और उनमें लगाई जाने वाली पूंजी, जिसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है, कितनी होगी ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य में कोई अखबारी कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) फिलहाल, केरल में सार्वजनिक क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक-एक अखबारी कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। केरल के कारखाने पर 21 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगाने का अनुमान है और हिमाचल प्रदेश के कारखाने पर कितनी पूंजी लगेगी, इसका अनुमान अभी गैर-सरकारी पार्टी ने तैयार करना है। केरल के कारखाने के लिये 10.54 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था है।

(ख) तथा (ग). इस मामले में केरल सरकार ने इस प्रकार का कोई औपचारिक अनुरोध तो नहीं किया है परन्तु उन्होंने पर्याप्त कच्चा माल, भूमि, जल, बिजली इत्यादि सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। योजना पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय

*59. **श्री प० मु० सईद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र मण्डल प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन में हाल ही में भाग लेने के लिए गई प्रधान मन्त्री से ब्रिटेन के गृह-मंत्री ने यह अनुरोध किया था कि वह ब्रिटेन में भारतीयों के जाने को रोकने में उनकी सहायता करें ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गयी है ;

(ग) इस सम्बन्ध में उन्होंने ब्रिटेन के गृह मंत्री से क्या प्रस्ताव किया था ;

(घ) इन प्रस्तावों के प्रति ब्रिटेन के गृह मंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी ;

(ङ) क्या ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित प्रतिबन्धों से उन भारतीयों पर, जो ब्रिटेन में रहते हैं, कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(च) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान जाने वाले यात्री

201. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों की जांच-पड़ताल के सिलसिले में उनको पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान को हथियारों की सहायता

202. **श्री बाबूराव पटेल** :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद अब तक भारत सरकार के पास नवीनतम उपलब्ध सूचना के आधार पर पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, ईरान, रूस तथा पश्चिम जर्मनी से देश-वार, किस प्रकार की कितनी और कितने मूल्य का सैनिक सामान सहायता के रूप में अथवा खरीद कर प्राप्त किया है;

(ख) इसके मुकाबले में इसी अवधि में अमरीका, पश्चिम जर्मनी, रूस तथा अन्य राष्ट्रों से राष्ट्र-वार हमें कितने मूल्य के सैनिक उपकरण मिले हैं; और

(ग) पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की जाने के कारण हमने विभिन्न देशों को जो विरोध-पत्र भेजे हैं उनका विवरण क्या है और क्या ये विरोध-पत्र प्रभावी सिद्ध हुए हैं और यदि हां तो किस सीमा तक और किन-किन देशों में प्रभावी रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विभिन्न आयुधों और साज-सामान की किस्में और राशिएं जो पाकिस्तान ने चीन से प्राप्त कीं, 13 नवम्बर, 1968 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर में सदन के ध्यान में लाई गई थीं । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने इलेक्ट्रानिकी साज-सामान, टैंक तोड़ मिजाईलों, गोली बारूद और फालतू पुर्जों की भारी राशिएं भी कई देशों से प्राप्त की थीं । पाकिस्तान द्वारा 1965 से लेकर प्राप्त किए गए सब सैनिक साज-सामान का कुल मूल्य 700 मिलियन डालर से कहीं अधिक होगा । अधिक विस्तार प्रकट करना वांछित न होगा ।

(ख) पाकिस्तान में आयुधों के जमाव से जनित संकट का सामना करने के लिए सरकार द्वारा जब आवश्यक हुआ उन मदों को आयात करके उचित उपाय किए गए हैं, कि जो देशीयत: निर्माण नहीं की जा सकती । इन सप्लाईयों के मूल्य और साधन प्रकट करना सुरक्षा के हित में नहीं होगा ।

(ग) पाकिस्तान को आयुधों की सप्लाईयों के विषय पर सरकार के विचार सभी मित्र देशों को ज्ञात कर दिए गए हैं । उन्हें बताया गया है कि पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति में जमाव भारत के साथ उसके संबंधों से साधारणीकरण की ओर उसके रवैये में उसे और दुराग्रही बना देगा, और उपमहाद्वीप में तनाव को बढ़ा देगा । कुछ हालतों में हमारे इन पगों के उचित परिणाम हुए हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन

203. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाह व्यय निरन्तर बढ़ते रहने के कारण सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की जिन्होंने हमारे देश के लिये युद्ध लड़े हैं पेंशन में समुचित वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन सैनिकों का पद-वार एवं ग्रुपवार ब्योरा क्या है जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी की थी;

(ग) सेवा पेंशन के लिए कितने ग्रुप हैं और प्रत्येक ग्रुप के अन्तर्गत किस-किस प्रकार के सैनिक आते हैं; और

(घ) उच्च अधिकारियों की पेंशन में समुचित वृद्धि न की जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 23/69]

विदेशी दूतावासों के लिये आवंटित भूमि

204. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी दूतावासों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली में अपने भवन बनाने के लिये भूमि आवंटित की गई है और कितनी भूमि आवंटित की गई है और कहां-कहां और प्रत्येक मामले में प्रति गज अथवा प्रति एकड़ भूमि का मूल्य या किराया कितना है;

(ख) क्या दिल्ली में भूमि के प्रचलित मूल्यों की अपेक्षा उनको कुछ रियायत की गयी है और यदि हां, तो प्रचलित मूल्य क्या हैं और उन दूतावासों के नाम क्या हैं, जिन्हें रियायत दी गयी है और इसके क्या कारण थे;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय दूतावासों को भूमि आवंटित की है तथा कितनी-कितनी और किस-किस मूल्य पर अथवा किन शर्तों पर;

(घ) क्या यह सच है कि 'होलीसी' भी एक राष्ट्र और दूतावास माना जाता है और उसे भी एक भूभाग दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्य किन-किन धार्मिक संस्थाओं को इसी प्रकार का स्थान दिया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चाणक्यपुरी में अपने भवनों का निर्माण करने के लिए, अब तक 34 राजनयिक मिशनों ने दिल्ली में प्लाट ले लिए हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :

मिशन का नाम	**क्षेत्रफल**
अफगानिस्तान	5.998 एकड़
आस्ट्रेलिया	11.88 ,,
बेल्जियम	5.48 ,,
बर्मा	5.98 ,,
कनाडा	8.859 ,,
श्रीलंका	3.917 ,,
चीन	30.595 ,,
चेकोस्लोवाकिया	8.443 ,,
इथोपिया	5.864 ,,
फिनलैंड	5.142 ,,
जर्मनी	5.995 ,,
घाना	5.404 ,,
होलीसी	3.777 ,,
हंगरी	4.346 ,,
इंडोनेशिया	4.22 ,,
इटली	9.637 ,,
जापान	11.988 ,,
मलेशिया	5.406 ,,
नीदरलैंड	5.998 ,,
नार्वे	4.323 ,,
न्यूजीलैंड	4.640 ,,
पाकिस्तान	11.95 ,,
फिलिपिन्स	4.00 ,,
पुर्तगाल	5.957 ,,
सूडान	5.980 ,,

मिशन का नाम	क्षेत्रफल
स्वीडेन	9.846 करोड़
स्वीट्जरलैंड	6.098 ,,
थाइलैंड	4.00 ,,
टर्की	4.556 ,,
सोवियत रूस	21.831 ,,
संयुक्त अरब गणराज्य	4.147 ,,
ब्रिटेन	24.11 ,,
संयुक्त राज्य अमरीका	27.972 ,,
यूगोस्लाविया	5.981 ,,

1950 से 30 जून, 1958 तक की अवधि में इन प्लाटों की कीमत उनके स्थानिक महत्व के अनुरूप 40,000 और 50,000 रुपये प्रति एकड़ के बीच ली गई थी। उसके बाद जनवरी 1964 तक उसकी कीमत 30 प्रतिशत बढ़ा दी गई।

इन कीमतों के अन्तर्गत वार्षिक भूमि किराया शामिल नहीं है, जो पहली अदा की गई किस्त का ढाई प्रतिशत था। लेकिन विदेशी मिशनों को इस बात की छूट दी गई थी कि अगर वे चाहें तो इन प्लाटों पर भूमि किराया कम करके 40,000 रुपये प्रति एकड़ की समान दर से, 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से नाममात्र रूप में वार्षिक भूमि किराया अदा कर दें।

(ख) जी हां। उपर्युक्त देशों के मिशनों को रियायती दरों पर प्लाट दिए गए थे, अर्थात् 'न मुनाफा न घाटा' के आधार पर दिए गए थे। भूमि के अधिग्रहण और विकास सम्बन्धी खर्च ही लिए गए थे। उस समय बाजार में भूमि की कीमत 1,01,000 रुपए प्रति एकड़ थी अर्थात् उस समय नीलामी में इतना दाम वसूल किया गया था।

25 विदेशी मिशनों ने, जुलाई 1958 के पहले ही जमीन खरीद ली थी और 9 मिशनों ने, अर्थात् फिलिपिन्स, घाना, नीदरलैंड, संयुक्त अरब गणराज्य, टर्की, न्यूजीलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और जापान ने जुलाई 1958 के बाद खरीदी थी।

(ग) देश का नाम	क्षेत्रफल	शर्त	कीमत
अदीस अबाबा (इथोपिया)	22,333 वर्ग मीटर	चाणक्यपुरी में इथोपिया राजदूतावास को जो प्लाट दिया गया था, उसके बदले 99 वर्ष के पट्टे पर यह प्लाट प्राप्त किया गया है।	पारस्परिक आदान-प्रदान से।

देश का नाम	क्षेत्रफल	शर्त	कीमत
इस्लामाबाद (पाकिस्तान)	51866.2 वर्ग गज	सर्वकालिक पट्टे पर	9.6 लाख रुपए (18.51 रु० प्रति वर्ग गज)
करांची (पाकिस्तान)	10470 वर्ग गज (क्लिफटन के प्लाट)	99 वर्ष के पट्टे पर	3,03,440 रुपये (28.95 रु० प्रति वर्ग गज)
काबुल (अफगानिस्तान)	10 जरिब	99 वर्ष के पट्टे पर	1,89,125.20 रु० (18.91 रु० प्रति वर्ग मीटर)
अंकारा (टर्की)	12015 वर्ग मीटर	फ्री होल्ड	3,48,822 रु० (29.03 रु० प्रति वर्ग मीटर)
बासिलिया (ब्राजिल)	25000 वर्ग मीटर	फ्री होल्ड	ब्राजिल सरकार से मुफ्त उपहार
त्रिनिडाड (पोर्ट-आफ-स्पेन)	24291 वर्ग फीट (2 प्लाट)	99 वर्ष के पट्टे पर	प्रारम्भिक किस्त 2880 ट्रिनिडाड डालर वार्षिक किस्त 2160 ट्रिनिडाड डालर (10827.07 रुपये और 8120.30 रुपये)

(घ) हां । यह स्थापित राजनयिक व्यवहार के अनुकूल है ।

(ङ) कोई नहीं । प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि होलीसी कोई धार्मिक संस्था नहीं है ।

'जनसत्ता' का अखबारी कागज का कोटा

206. **श्री द० रा० परमार :**

श्री रा० की० अमीन :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब जनसत्ता ने अपना सार्थ 'इण्डियन एक्सप्रेस' को बेचा था क्या तब उसे अपने

अखबारी कागज के कोटे को हस्तान्तरित करने की अनुमति नहीं दी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि 'जनसत्ता' समाचार-पत्र समूह 'इण्डियन एक्सप्रेस' समूह को बेच दिये गये हैं। इस समूह की यह प्रार्थना कि यदि समूह की बिक्री कर दी गई तो अखबारी कागज का कोटा एक्सप्रेस समूह को दे दिया जाए, स्वीकार नहीं की गई थी।

(ख) अखबारी कागज का आवंटन करने की नीति के अनुसार 'समान स्वामित्व एकक' के किसी भी नये पत्र के लिये अखबारी कागज का कोटा अलाट नहीं किया जाता। एक्सप्रेस समाचारपत्र 'समान स्वामित्व' एकक है और यदि जनसत्ता समूह से सम्बन्धित समाचारपत्र एक्सप्रेस समूह द्वारा ले लिये जाते हैं तो वे उनके लिये नये समाचारपत्र हो जायेंगे।

Commonwealth P. Ms'. Conference

208. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Hardayal Devguna :
Shri Bedabrata Barua :
Shri Yashpal Singh :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Samar Guha :
Shri Kameshwar Singh :
Shri D. N. Patodia :
Shri N. K. Sanghi :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri C. Janardanan :
Shri B. K. Daschowdhury :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri P. C. Adichan :
Shri Hem Barua :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri R. K. Sinha :
Shri S. C. Samanta :
Shri George Fernandes :
Shri A. Sreedharan :
Shri N. R. Laskar :
Shri R. Barua :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri K. Lakkappa :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ranjit Singh :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Himatsingka :
Shri Valmiki Choudhuri :
Shri S. Supakar :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Indrajit Gupta :
Shri S. S. Kothari :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Badrudduja :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri Y. A. Prasad :
Shri M. L. Sondhi :
Shri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that she participated in the commonwealth Prime Ministers' Conference held in London recently ;

(b) if so, the details regarding Indian interest raised by her in the aforesaid conference and the extent to which she has been successful in this regard ; and

(c) the other matters discussed in the conference and the outcome of the discussion ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . The discussions relating to the Conference are informal and confidential. It is not customary to publicise the details of discussion of the meeting.

Upgrading of A. I. R. Station, Raipur

209. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the Raipur Station of All India Radio is only a relaying station ;

(b) if so, whether Government have taken a decision to convert it into a full-fledged Radio Station ; and

(c) if so, when the work in this connection is likely to be taken in hand ?

The Minister of State in the Ministry of information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Raipur is an auxiliary station and it relays programmes originated from Bhopal station. It also originates programmes for 35 minutes every day.

(b) It is proposed to upgrade it to a full-fledged station during the Fourth Five Year Plan period.

(c) After the Plan has been finally approved.

Radio Station for Ranikhet

210. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of setting up new radio stations in the hilly areas ;

(b) if so, whether a decision has been taken to set up a radio station at Ranikhet (District Almora), Uttar Pradesh ; and

(c) if so, the time by which it is likely to be set up and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) All India Radio's expansion programme during the Fourth Plan period includes proposals for setting up radio stations, besides other parts of the country, in hilly areas also.

(b) Yes, Sir. It has been decided to set up a radio station in the Kumaon region of Uttar Pradesh.

(c) By 1971-72.

Inclusion of an Area in the List of "Specific Area"

211. **Shri Kushok Bakula :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the inclusion of an area in the list of the 'specified area' is done on the basis of the survey conducted by the Central Government or on the recommendations of the State Government ; and

(b) whether the area of Ladakh would be declared as specified area in view of its economic, social and educational backwardness, lack of industries and large scale unemployment?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Presumably the Hon'ble Member has in mind the Planning Commission's advice that States might identify specially under developed pockets as backward areas. The Jammu and Kashmir Government have pointed out that they do not have full data required for the purpose. However, the problems of Jammu and Kashmir, like those of Assam and Nagaland also, are specially kept in view by the Planning Commission.

(b) Does not arise.

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का विस्तार

212. **श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का विस्तार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां । भाभा कमेटी ने निर्धारित किया था कि देश में इलेक्ट्रानिकी मदों का वार्षिक उत्पादन, जो 1964-65 में लगभग 26.5 करोड़ रुपये था, 1957 तक बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये तक करना होगा । 1967-68 में उत्पादन 65 करोड़ रुपये था और 1968-69 में उसके 85 करोड़ रुपये होने की प्रत्याशा है । बढ़ती हुई आवश्यकताओं का सामना करने के लिए देश में इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विस्तार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

आयुध कारखानों में ए० एम० आई० ई० पास व्यक्ति

213. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री आयुध कारखानों में ए० एम० आई० ई० पास व्यक्तियों के बारे में 28 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6299 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अपेक्षित जानकारी कब तक एकत्रित की जाने और उस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना पहले ही इकट्ठी कर ली गई थी और विवरण के तौर पर 20-12-68 को सभा के पटल पर रख दी गई थी। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 24/69] तदनु 4-2-1969 को इस विषय के सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि रक्षा सेवाओं के अनुमानों से अदायगी किए गए ऐसे असैनिक कर्मचारी का वेतन, कि जिसने अराजपत्रित तकनीकी/वैज्ञानिक ग्रेड में सेवा करते हुए (ए० एम० आई० समेत) इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य अर्हता प्राप्त कर ली हो, उस तिथि से पुनः निर्धारित किया जाएगा कि जिस तिथि को उसने उपरोक्त अर्हता प्राप्त की हो; वह वेतन उस अवस्था पर नियत किया जाएगा कि उसे वेतन में तीन अग्रिम तरक्किएं प्राप्त हो पाएं। उन कर्मचारियों को भी कि जो ए० एम० आई० ई० के खण्ड 'क' में उत्तीर्णता प्राप्त कर लें एक अग्रिम तरक्की दी जाएगी। तदनु, खण्ड 'ख' में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने पर उन्हें दो और तरक्किएं दे दी जाएंगी। उपरोक्त निर्णय के अनुसार उन व्यक्तियों को 1-12-1968 से वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे, कि जिन्होंने पहले से ही ऐसी अर्हता प्राप्त कर ली थी, और उन व्यक्तियों को कि जिन्होंने 1-12-68 के पश्चात् वह अर्हता प्राप्त की हो, उस तिथि से वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे, कि जिस दिन संबंधित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हों।

शान्ति पर्यवेक्षक दल का मोजेमा दौरा

214. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शान्ति पर्यवेक्षक दल ने जिसने मोजेमा क्षेत्र का जहां 2 दिसम्बर, 1968 को भारतीय सुरक्षा सेना और भूमिगत नागाओं के बीच संघर्ष हुआ था, दौरा किया था, भारतीय सुरक्षा सेना और भूमिगत नागाओं से युद्ध-विराम समझौता भंग न करने की अपील की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने सुरक्षा सेना पर भी यह आरोप लगाया है कि वह युद्ध-विराम समझौते की शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उनका यह कथन कहां तक सच है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

नागालैंड में प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबन्धों को उदार बनाना

215. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री रा० बरुआ :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन प्रतिबन्धों को नर्म करने पर विचार कर रही है, जो भारत के अन्य भागों के लोगों के नागालैंड में प्रवेश करने पर लगे हुए हैं ;

(ख) क्या नागालैंड की सरकार से इस विषय में परामर्श किया गया है और यदि हां, तो नागालैंड सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार के निर्णय से विद्रोही नागाओं की गतिविधियों से उत्पन्न राज्य की वर्तमान समस्या और अधिक जटिल हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). भारत के अन्य भागों के लोगों के नागालैंड में प्रवेश पर प्रतिबंधों में नर्मी बरतने का प्रश्न भारत सरकार के विचारधीन है और अभी इसे नागालैंड की सरकार के साथ उठाया नहीं गया है ।

श्रीनगर केन्द्र के लिये हिन्दी समाचार बुलेटिन

216. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के श्रीनगर केन्द्र से हिन्दी समाचार बुलेटिन का प्रसारण बन्द करने का किसी मांग या प्रस्ताव पर वह विचार कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के प्रसारणों में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को बराबर का दर्जा

217. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी को आकाशवाणी के प्रसारणों में अंग्रेजी के बराबर का दर्जा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य प्रादेशिक भाषाओं को भी आकाशवाणी के प्रसारणों के अंग्रेजी के बराबर का दर्जा दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी के कार्यक्रमों के हिन्दी कार्यक्रमों को जो कुल समय दिया जाता है वह अंग्रेजी कार्यक्रमों की तुलना में बहुत अधिक है। अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि आकाशवाणी के प्रसारणों में हिन्दी का दर्जा अंग्रेजी के बनिस्बत कम है।

(ख) यही बात प्रादेशिक भाषाओं के साथ भी है। प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों को दिया जाने वाला समय अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रमों से कहीं अधिक होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

M. Ps. Delegation to Afro-Asian Countries

218. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri R. Barua :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri N. R. Laskar :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5006 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether a decision has since been taken to send delegations of Members of Parliament to the various African and Asian countries in 1969 ;

(b) if so, the details thereof and the purpose of their visit ;

(c) whether, at the time of fixing the number of Members for the delegation, all political parties will be given due representation in the delegations ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Not yet, Sir.

(b) to (d) Do not not arise.

Publications Brought out by the Ministry of Information and Broadcasting

219. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of publications brought out by the Ministry of Information and Broadcasting and its attached and subordinate offices in the years 1967 and 1968 ;

(b) the number of publications out of them which have been brought out in Hindi and English, separately ;

(c) whether Government propose to bring out all the publications originally in Hindi also ;

(d) if so, when ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) . Information regarding the number of

books, pamphlets and albums brought out during the years 1967 and 1968 is as follows:

	Total	In English	In Hindi
1967	295	75	47
1968	210	50	40

In addition, the Publications Division published 10 journals—4 in Hindi, one in Urdu and five in English during these two years. Besides, All India Radio publishes programmes journals.

(c) to (e). It is not feasible to bring out all the publications of the Publications Division originally in Hindi also. It is not possible to bring out publications meant largely for readership abroad such as INDIAN AND FOREIGN REVIEW, etc. in Hindi. Nor is it practicable to bring out originally in Hindi publications the source material for which is available only in English. Efforts are, however, being made to bring out more and more publications originally in Hindi. In pursuance of this objective, the Hindi Section of the Division has been strengthened by the appointment of a senior officer of the rank of Deputy Director. The Children's literature produced by the Division is brought out mostly in Hindi. This includes such titles as BHARAT KE GAURAV ; BHARAT KE AMAR CHARITRA ; GYAN SAROVAR ; BHARAT KI LOK KATHAIN ; SARAL PANCHTANTRA etc.

Out of the 3 magazines brought out by the Division on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, two, namely, AJKAL and the children's magazine BAL BHARTI, are brought out in Hindi.

Government Advertisements to Newspapers

220. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the amount involved in the advertisements given to English and Hindi newspapers separately by the Government of India during the year 1967-68 :

(b) whether Government are aware of the fact that the readers of Hindi newspapers are more in number than the readers of English newspapers and that several persons read only Hindi newspapers ;

(c) if so, whether Government propose to give advertisements to English and Hinni newspapers on the basis of the percentage of English and Hindi speaking people ; and

(d) if not, the reasons for giving encouragement to English papers and discriminating with Hindi papers ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a)

Value of advertisements issued during 1967-68 to—	Display Rs.	Classified Rs.
(i) English newspapers	11,14,481	27,36,073
(ii) Hindi newspapers	5,20,934	4,52,321

(b) As per data given in 'Press in India 1968' (Part I) Chapter III, Table No. 23, page 41, a copy of which was laid on the Table of the House on 28th August 1968, the circulation of English and Hindi dailies and periodicals was as follows :

	Circulation	
	1965	1966
English	61,92,000	61,18,000
Hindi	46,89,000	49,55,000

During 1966, English dailies had a total circulation of 16,77,000; the circulation of Hindi dailies was 9,71,000.

(c) and (d). Government advertisements are released keeping in view the following considerations;

(i) Effective circulation (Normally, papers having paid circulation below 1,000 are not used);

(ii) regularity in publication (a period of six months of uninterrupted publication is essential);

(iii) class of readerhip;

(iv) adherence to accepted standards of journalistic ethics;

(v) other factors such as production standards, the languages and areas intended to be covered within the available funds; and

(vi) advertisement rates which are considered suitable and acceptable for Government publicity requirements.

Newspapers published in Hindi are not discriminated against.

Talks with Pakistan

221. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Nanja Gowder :
Shri N. K. Sanghi :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri N. K. Somani :
Shri R. K. Amin :
Shri K. M. Koushik :
Shri N. Shivappa :
Shri M. L. Sondhi :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri H. N. Mukerjee :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Ishaq Sambhali :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shrimati Ila Palchoudhuri :
Shri Bhogendra Jha :
Shri P. C. Adhichan :
Shri Hem Berua :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Sita Ram Kesri :
Shri R. Barua :
Shri N. R. Laskar :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Ranjit Singh :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Hardayal Devgun
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri C. C. Desai :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri M. Sudarsnam :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Valmiki Choudhury :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri B. K. Daschowdhury :
Shri Y. A. Prasad :
Shri Ramachandra Verrappa :
Shri Bedabrata Barua :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri J. B. Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri Onkar Singh :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri J. Mohamed Imam :
Shri Narendra Kumar Salve :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri Himatsingka :
Shri K. P. Singh Deo :
Dr. Sushila Nayar :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have recently proposed to Pakistan setting up of a Joint

machinery for resolving the Indo-Pak. disputes and have renewed their offer of no-War Pact; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of the Government of Pakistan thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) and (b). Yes, Sir. The Government have proposed to Pakistan the creation of a bilateral joint machinery which could after the signing of the No-War Pact immediately start discussions for the normalisation of Indo-Pak relations and the solution of all difficulties between the two countries. It should be the objective of the Joint Body to bring about normalcy and to settle all differences between the two countries step by step. Setting up of a Joint Body would be in consonance with the provisions of the Tashkent Declaration.

The statements made by Pakistani spokesmen, so far, have not been encouraging.

Hindi News Agencies

222. **Shri Ram Charan:**
Shri Om Prakash Tyagi:
Shri Molahu Prasad

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the number of Hindi news agencies in the country at present;

(b) the special facilities provided by Government to the Press Trust of India and the United News of India which are English news agencies at their initial stages;

(c) whether Government propose to provide special facilities to the Hindi News Agencies also to enable them to stand on the same footing as English news agencies; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Government have no precise information regarding the number of Hindi news agencies in the country at present, for the present law does not require registration of news agencies. However, two Hindi news agencies, viz. Hindustan Samachar and Samachar Bharati have been granted accreditation facilities at the headquarters of Government.

(b) No special facilities were provided to the Press Trust of India and United News of India at their initial stages except accreditation facilities and tele-communications connections on payment of normal hire charges, in response to their applications. These fatilities are allowed to all news agencies as a matter of course.

(c) and (d). Similar facilities were also accorded to the two Hindi news agencies mentioned in part (a) of the question. In addition, Government have agreed to give a loan of Rs. 5 lakhs to the Samachar Bharati for purchase of teleprinters etc. subject to necessary safeguards. The loan will be interest-free and become repayable in 10 instalments, after five years from the date of drawal. The first instalment of Rs. 75,000 has already been advanced and their application for the second instalment is being processed. An application from the Hindustan Samachar for a loan of Rs. 2 lakhs is under consideration.

Order on Rustenburg Indians

223. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Ram Swarup Yidyarthi :
Shri M. L. Sondhi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri D. N. Patodia :
Shri R. K. Sinha :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Samar Guha :
Shri Surendranath Dwivedi :
Shri Dinkar Desai :
Shri K. Lakkappa :
Shri J. Ahmed :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Vishwanath Pandey :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the order issued by the Government of South Africa to 867 Indian Traders of Rustenburg to wind up their business within a period of one year and go elsewhere; and

(b) If so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). The Government of India have seen press reports to this effect. These reports, if true, provide yet another example of the relentless pursuit by the South Afrcian Government of its cruel and unjust policy of apartheid against which India, along with the vast majority of the members of the U. N., has been fighting.

Tashkent Declaration

224. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Sharda Nand :
Shri J. B. Singh :
Shri R. K. Amin :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shrimati Tara Sapre :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri K. P. Singh Deo :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which the provisions of the Taskhent Declaration implemented by India and Pakistan uptill now with a view to establish good relations between India and Pakistan ;

(b) the nature of provisions which both the countries could not implement ;

(c) the country which is hesitating in implementing those provisions ;

(d) whether any benefit accrue as a result of India following the agreement unlaterally ; and

(e) if so, the nature of benefit ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c). The statement giving the progress in implementation of the provisions of the Tashkent Declaration is laid on the Table, along with a copy of the Tashkent Declaration. **[Placed in Library. See No. LT-25/69.]**

(d) and (e). Adherence by India to the provisions of Tashkent Declaration is prompted by a desire to improve relations with Pakistan.

Talks on A. I. R.

225. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the persons invited to give talks on A. I. R., Delhi in the year 1968, and the fields in which the specialised and of which they were scholars ;

(b) the reasons for inviting certain persons more than once ; and

(c) the total amount of money paid in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Information, Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Newspaper Finance Corporation

226. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri M. L. Sondhi :
Shri Yogendra Sharma :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri George Fernandes :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri A. Sreedharan :
Shri Sitaram Kesri :
Shri R. K. Amin :
Shri D. R. Parmar :
Shri Valmiki Choudhury :
Shri N. R. Laskar :
Shri R. Barua :
Shri R. V. Naik :
Shri S. P. Ramamoorthy :
Shri D. N. Deb :
Shri K. M. Koushik :
Shri B. K. Daschowdhury :
Shri Bhgwan Das :
Shri D. N. Patodia :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri S. S. Kothari :
Shri R. R. Singh Deo :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government now propose to set up a Newspaper Finance Corporation for giving assistance to the small newspapers, facing lack of resources ;

(b) the salient features of the proposal ; and

(c) the time by which Government are likely to take a decision in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). In reply to a reference made to the Press Council sometime back, the Council advised the establishment of a Newspaper Finance Corporation with an independent Board with powers to help newspapers in financial difficulties. Accordingly, a reference has been made to the Council to advise Government on the details of the scheme of a Newspaper Finance Corporation, especially with regrad to the composition of

the Board of Directors, their method and manner of selection and the broad principles on which financial assistance to newspapers should be extended, keeping in view the need for preserving the freedom of the Press as guaranteed under the Constitution to serve as guidelines in this matter. The Council have replied that they would be able to convey their views by the end of February, 1969. The question will be considered further on receipt of the Council's reply.

Memorandum Submitted by Indians Residing in East African Countries

227. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri M. L. Sondhi :**
Shri P. M. Syeed :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state ;

(a) whether a deputation of Indians residing in the East-African countries or a deputation of Indians having British passports called on Government during the last session of the Lok Sabha ;

(b) whether they submitted any memorandum to Government pointing out the difficulties of Indians residing there and certain suggestions for finding a solution thereto ; and

(c) if so, the nature of the suggestions made and the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). Yes, Sir. A delegation of persons of Indian origin in Kenya holding British passports led by Dr. Sandhu visited India in November, 1968, and submitted a memorandum to the Government.

(c) The delegation suggested that (i) the existing visa system which is applicable to people of Indian origin holding British passports resident in Kenya be abolished and (ii) that persons who are not covered by Indo-British Agreement be also permitted to come to India for permanent settlement. After discussions, the delegation was satisfied that the continuance of the visa system was necessary. The Government of India however, assured the delegation that they will consider sympathetically the cases for resettlement in India of those persons of Indian origin who are not covered by the present Indo-British Agreement.

Immigration of Israeli Citizens to India

228. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government discourage the citizens of Israel to come to India ;

(b) if not, the number of Israeli officers, citizens and Ministers who applied for visas for coming to India and the number out of them, who were granted visas during the last five years ;

(c) Whether Government propose not to give their active support to Arabs against the Government of Israel in view of their non-alignment policy ; and

(d) if not, whether it is in the interest of India to give active support to Arabs inspite of the fact that Arab countries had openly supported Pakistan during the Indo-Pakistan conflict in 1965 ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) The information is being collected.

(c) and (d). India's support to Arabs is based on its firm belief that an aggressor should not be allowed to retain the fruits of aggression. This is not inconsistent with non-alignment and is in India's national interest.

External Broadcasts

229. **Shri Molahu Prasad**:
Shri Om Prakash Tyagi:
Shri Ramji Ram:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 820 on the 18th December, 1968 and state :

(a) the basis on which two hours thirty minutes are allotted for Hindi and one hour forty-five minutes are alloted for Tamil for broadcasts in External Service of the A. I. R.;

(b) the time allotted out of the said time for the music of Hindi films and that allotted for the music of Tamil film.

(c) whether Government propose to increase the time allotted for Hindi in view of large number of emigrants in Mauritins, British Guiana, America, Canada, Britain, etc. knowing Hindi more than Tamil ; and

(d) if so, from when, and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Bcoadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Allotment of time is based on the following considerations :

(i) Availability of transmitters ;
(ii) Relative priority ;
(iii) Listening interest.

(b) (1) Hindi film music — 27% of the Hindi service.
(2) Tamil film music — 25% of the Tamil service.

(c) There is no proposal at present.

(d) According to the priorities governing External Services of the All India Radio adequate services have to be provided for services in foreign languages in the first instance.

चौथी पंचवर्षीय योजना का तैयार किया जाना

230. श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ज० मुहम्मद इमाम
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

श्री मुत्तुस्वामी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री द० रा० परमार :
श्री सोमचन्द सोलंकी :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के आकार के बारे में नवीनतम अनुमान क्या है और गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के लिये कितना धन नियत किया गया है;

(ग) चौथी योजना कब तक आरम्भ हो जायेगी ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसको कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (घ). चौथी योजना का मसविदा तैयारी के अग्रिम चरण में है। यह शीघ्र ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा जायगा।

(ग) चौथी योजना अवधि अप्रैल, 1969 से शुरू होगी।

चीन द्वारा उद्जन बम का विस्फोट

231. श्री रा० कृ० सिंह :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हेमराज :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री द० रा० परमार :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री बलराज मधोक :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
डा० सुशीला नैयर :
श्री हेम बरुआ :
श्री सु० कु० तापड़िया
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री क० लकप्पा :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री समर गुह :
श्री वाल्मीकि चौधरी :
डा० कर्णी सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने दिसम्बर, 1968 में उद्जन बम का विस्फोट किया था और क्या वह हिन्द महासागर में अन्तर्देशीय प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने की तैयारी कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है कि हमारी प्रतिरक्षा पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव होगा ; और

(ग) क्या परमाणु अस्त्रों के निर्माण के बारे में सरकार का विचार अपनी नीति में पुनरीक्षण करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीन ने 27 दिसम्बर, 1968 को एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। यह भी ज्ञात है कि चीन अन्तर्महाद्वीप बालिस्टिक मीजाईलों के विकास में प्रवृत्त है, परन्तु ऐसे कोई इन्गित प्राप्य नहीं हैं कि ऐसे मीजाईल का कब और कहां परीक्षण किया जाएगा।

(ख) तथा (ग). हमारी सुरक्षा पर इन संवर्धनों का प्रभाव सरकार द्वारा निरन्तर निर्धारण का विषय है। नाभिकीय आयुधों के निर्माण के संबंध में सरकार की नीति पहले कई अवसरों पर सदन में स्पष्ट की जा चुकी है।

प्रधान मंत्री के साथ लन्दन गये अधिकारी

232. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में लन्दन आदि विदेशों के दौरे के समय प्रधान मंत्री के साथ कितने सरकारी/गैर-सरकारी अधिकारी गये ; और

(ख) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) लंदन के दौरे पर प्रधान मंत्री के साथ विदेश मंत्रालय में उस समय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री के सचिव, भारत सरकार के दो अधिकारी और उनके निजी अमले के चार सदस्य थे ।

(ख) 38,500/-रु० (अनुमानतः)

प्रतिरक्षा उपमंत्री द्वारा लक्कदीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह का दौरा

233. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रतिरक्षा उपमंत्री ने लक्कदीव तथा मिनिकाय के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) स्थानीय प्रशासकों से, विशेषकर वहां बसे लोगों के बारे में जो उन्होंने विचार-विमर्श किया है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या केरल के भूमिहीन किसानों को इन द्वीप समूहों पर पुनः बसाने के बारे में कोई बातचीत की गई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). कुछ सप्ताह हुए रक्षा उपमंत्री ने लकादीव और मिनिकाए द्वीपसमूह के कुछ द्वीपों का भ्रमण किया था । उन्होंने द्वीपसमूह के विकास और युवक के क्रियाकलाप के प्रोत्साहन के संबंध में प्रशासक से व्यापक विचार-विमर्श किया था । रक्षा उपमंत्री ने अमीनी द्वीप में आयोजित राष्ट्रीय छात्र दल के जूनियर डिवीजन के नौसैनिक लड़कों के शिविर का भी भ्रमण किया और एन० सी० सी० सम्मेलन को सम्बोधित भी किया ।

कोचीन नौसैनिक अड्डा

234. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन क्षेत्र की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए क्या कोचीन नौसैनिक अड्डे के विकास और उसमें सुधार करने के बारे में केरल सरकार से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Financial Help to Newspapers

236. **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri S. S. Kothari:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Suraj Bhan:
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the names of newspapers which have sought assistance from Government due to financial crisis and other difficulties during the current year so far;

(b) the policy of Government in this regard and the action taken so far; and

(c) the ground on which assistance has been given to some newspapers and the grounds on which assistance has not been given to others ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) A statement is attached.

(b) and (c). No financial assistance has been given to any newspaper so far. The Press Council does not approve of the grant of a loan directly by Government to newspapers. The question of a long-term policy in this regard is under consideration inconsultatiion with the Press Council.

Statement

List of applications received from newspapers and newspaper interests for grant of financial assistance during April, 1968 to January, 1969.

1. Agragami, Balanagar.
2. Tainadu, Bangalore.
3. Prabhat, Ahmedabad.
4. Karmaveer, Khandwa, Madhya Pradesh.
5. Indian Journal of Agricultural Chemists, Allahabad.
6. Gujarat State Small Newspaper Editors Association, Rajkot (for grant of loans to its member newspapers for purchase of printing presses).
7. The Prajatantra, Imphal.
8. Gandhi Memorial Co-operative Newspaper Society Ltd., Bangalore.
9. 'Jansatta', 'Loksatta' group of papers, Baroda/Ahmedabad.
10. Youth and International Journal, New Delhi.
11. Application from Captain D. N. Diwedi for starting a newspaper (title not mentioned).

आयुध कारखानों में उत्पादन

237. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 में आयुध कारखानों के उत्पादन में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 में कितनी कीमत का उत्पादन हुआ ; और

(ग) यह उत्पादन 1967 के आंकड़ों की तुलना में कितना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). 1966-67 से लेकर आर्डनेंस फैक्टरियों के उत्पादन से वितरणों का मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	वितरणों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1966-67	103.87
1967-68 (अस्थायी)	97.17
1968-69 (अनुमानित)	107.80

आंकड़े स्वत: स्पष्ट हैं ।

26 जनवरी, 1969 के लिये दिल्ली प्रशासन की झांकी

238. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री भारत सिंह चौहान** :
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द के बारे में 26 जनवरी को निकाली जाने वाली झांकी पर आपत्ति की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग नहीं लिया ; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनके भाग न लेने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). गणतन्त्र दिवस परेड 1969 में एक झांकी शामिल करने के दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव पर (सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के एक सचिव, गीत तथा नाटक निदेशालयों तथा रक्षा मंत्रालय इत्यादि के प्रतिनिधियों पर सम्मिलित) एक कमेटी द्वारा विचार किया गया था जो झांकियों और लोक नृत्यों के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बनाई गई थी । कमेटी ने इस प्रस्ताव को पसन्द नहीं किया था, उसका विचार था कि यदि दिल्ली प्रशासन नवीकरणों के नमूने और सुन्दर बनाने की योजनाओं इत्यादि से युक्त 'दिल्ली को बारौनक' बनाने के विषय संबंधी कोई झांकी प्रस्तुत करें तो वह अधिक प्रभावकारी होगी ।

(ग) तथा (घ). कई राज्य सरकारों/संघीय प्रशासनों ने अर्थात् अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, बिहार, दादरा तथा नगर हवेली, केरल, उड़ीसा और पांडीचेरी ने सूचित किया था कि वह गणतंत्र दिवस परेड 1969 के लिये कोई झांकी प्रस्तुत न कर पाएंगे । तदपि, उन्होंने कोई खास कारण नहीं बताए थे ।

तटस्थ देशों का सम्मेलन

239. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री दिनकर देसाई :
श्री क० लकप्पा
श्री समर गुह :
श्री स० कुन्दू :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान तटस्थ देशों का दूसरा सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव पर सम्बद्ध देशों से विचार-विमर्श पूरा हो गया है;

(ख) क्या सम्बद्ध सदस्य उक्त सम्मेलन के लिये सहमत हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक होने की सम्भावना है; और

(घ) उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). इथोपिया, भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया की सरकारों में परामर्श चल रहा है। अब ये चार देश, अन्य गुट निरपेक्ष राज्यों के साथ, प्रारम्भिक विचार-विनिमय आरम्भ करेंगे। जब व्यापक रूप से इस प्रकार का विचार-विनिमय समाप्त हो जायगा, तभी गुट निरपेक्ष राज्यों का मत स्पष्ट होगा।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड

240. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कब स्थापित किया गया था तथा इसके उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कारखानों की स्थापना के लक्ष्य तथा उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे हुए थे और यदि हां, तो कब और कैसे तथा यदि नहीं, तो क्यों;

(ग) क्या इस कम्पनी की स्थापना में विदेशी सहयोग लिया गया था और यदि हां, तो सहयोग करने वाले देशों के नाम क्या हैं; उनकी सहयोग की शर्तें क्या थीं तथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी;

(घ) इस समय कम्पनी किन वस्तुओं का कितना-कितना उत्पादन कर रही है तथा क्या ये वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं; गत तीन वर्षों के उत्पादन और विक्री के आंकड़े क्या हैं तथा उसमें से कितने सामान का निर्यात किया गया; और

(ङ) क्या इस कम्पनी को कोई कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड 1 अक्तूबर, 1964 को हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एयरोनाटिक्स इण्डिया लिमिटेड की परस्पर समाविष्टि पर अस्तित्व में आए। समाविष्टि का उद्देश्य था भारत में विमानों और एरो-इन्जनों के निर्माण के सीमित संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना।

(ख) इसके आरम्भ के पश्चात् हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा नासिक, हैदराबाद और कोरापुट में स्थापित की यूनिटों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। यद्यपि, मुख्यतः असैनिक निर्माण कार्यों की सम्पूर्ति और साजसामान की प्राप्ति में अधिक समय लग जाने के कारण कई शापों के कमीशन किए जाने में विलम्ब हुये हैं। अन्तिम निर्धारित किया गया शड्यूल को प्रायः बनाए रखा गया है।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड पूर्णतः एक सरकारी स्वामित्व सहित उपकरण के तौर पर स्थापित किया गया है। किसी भी विदेश की इसमें वित्तीय साझेदारी नहीं है।

(घ) (हैलिकाप्टरों समेत) विभिन्न प्रकार के विमान, एरो-इन्जन, इलेक्ट्रानिकी साजसामान और ग्लाईडर एच० ए० एल० द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। यह उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। पिछले तीन वर्षों में उत्पादन, क्रयों और निर्यातों का मूल्य इस प्रकार है :

	1965-66	1966-67 (लाख रुपयों में)	1967-68
(1) उत्पादन का मूल्य	1772.86	3492.38	4636.34
(2) क्रय	1646.33	2928.76	4137.54
(3) निर्यातों का मूल्य	.54	19.97	5.75

(ङ) विमानों के उत्पादन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और भारत में कि जहां उद्योग इतना प्रगत नहीं जैसे अन्य कई देशों में, सामने आने वाली समस्या और भी अधिक है। इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण उत्पादन, प्रायोजना, द्रव्यों की प्राप्ति और विमानों के बारे में तकनीकी समस्याओं से सम्बन्धित हैं। एच० ए० एस०

एच० ए० एल० ने इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए कई उपाय किए हैं, परन्तु निरन्तर सतर्कता आवश्यक है, और जैसे तथा जब ही कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनके हल ढूंढने पड़ते हैं। एच० ए० एल० को अधिक क्षमता से काम करने के योग्य बनाने के लिए सरकार ने उसके संगठन में कई परिवर्तन किए हैं।

Hill Development Board

241. **Shri Shri Gopal Saboo:**
Shri Bans Narain Singh:
Shri J. Sunder Lal:
Shri Onkar Singh:
Shri Sharda Nand:
Shri Shiv Charan Lal:
Shri Arjun Singh Bhadoria:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of meetings of the Hill Development Board held from the 1st August, 1968 to the 31st December, 1968 and the dates on which they were held;

(b) the subjects mainly discussed thereat;

(c) whether the Hill Development Board has decided to expeditiously repair the motorable roads of Pauri Garhwal district in view of their deplorable conditions; and

(d) if not, the reasons thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) No meeting of the Hill Development Board was held between 1st August, 1968 to 31st December, 1968.

(b) Does not arise.

(c) The Hill Development Board has recommended development of a number of roads in Pauri Garhwal District.

(d) Does not arise.

अधिक योजना परिव्यय के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा सुझाव

242. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री प० मु० सईद :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा गत दिसम्बर में जारी की गई पुस्तिका (पैम्फलट) की ओर दिलाया गया है जिसमें विकास कर में 5 प्रतिशत के लगभग व्यवहार्य वृद्धि को प्राप्त करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 18,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का सुझाव दिया गया है और अत्यधिक आशावादी योजना के विरुद्ध सावधानी बरतने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पुस्तिका में क्या विशिष्ट सुझाव दिये गये थे और उसमें से प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3274 दिनांक 4 दिसम्बर, 1968 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विभिन्न राज्यों के बारे में 1969-70 के लिये वार्षिक योजना परिव्यय

243. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अदिचन :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री वाल्मीकी चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में विभिन्न राज्यों के लिये कितना योजना परिव्यय नियत किया गया है ;

(ख) अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी विभिन्न सामाजिक सेवाओं हेतु इस परिव्यय का कितना-कितना भाग व्यय किया जायेगा ;

(ग) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में वृद्धि की कितनी दर प्राप्त हो गई है और 1969-70 में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(घ) कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और क्या 1969-70 में योजना के अन्तर्गत 1967-68 और 1968-69 से वार्षिक आय तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). इन्हें अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ). राज्यों की इन वर्षों की आय के तुलनात्मक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

मिग-विमान

244. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी ० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री अदिचन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट और नासिक मिग वर्कशाप में अलग-अलग प्रथम मिग विमान जोड़

लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और प्रथम विमान कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ;

(ग) यदि विमान का निर्माण किया जा चुका है तो क्या इसकी परीक्षा उड़ान की जा चुकी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यह विमान भारतीय परिस्थितियों में और भारतीय वायु बल की आवश्यकताओं के लिये किस हद तक उपयुक्त पाया गया है ; और

(घ) 1969 में मिग विमानों अथवा इसके पुर्जों का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पहला मिग विमान एच० ए० एल० को नासिक डिवीजन में संयोजित किया गया है। कोरापुट की फैक्टरी मिग विमानों के लिए केवल एरो-इंजनों का निर्माण करती है और उन्होंने पहला इंजन एच० ए० एल० नासिक डिवीजन को वितरित कर दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्माण किए गए विमानों का, वितरण करने से पहले वायु सेना के लिए पूर्णतः संतोषप्रद परीक्षण कर लिया जाता है।

(घ) खाम पदार्थों से मिग विमानों का निर्माण, जो उत्पादन कार्यक्रम में अन्तिम प्रावस्था में है 1969 में आरम्भ हो जाएगा।

बर्मा द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

245. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा की सरकार ने देश में समाजवादी आर्थिक प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से हाल ही में कुछ उद्योगों तथा कम्पनियों, जिनमें ऐसे उद्योग और कम्पनियां भी शामिल हैं जिनका स्वामित्व भारतीयों के हाथ में है, का राष्ट्रीयकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1968 के पश्चात् किन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी भारतीय कम्पनियों पर प्रभाव पड़ा था और उन कम्पनियों की आस्तियां कितनी थीं ; और

(घ) सरकार ने उन कम्पनियों के भारतीय मालिकों और स्वामियों, जिनकी आस्तियां बर्मा सरकार ने ले ली हैं, को पूरा मुआवजा देने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपनी आस्तियों को देश में लाने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सिनेमा, लकड़ी चीरने की मिलें, सूती कपड़े की मिलें, इंजीनियरी कारखाने, रासायनिक कारखाने तथा दूसरे सामान्य उद्योग जिनकी संख्या करीब 170 है ।

(ग) इनमें करीब 10-15 उद्योग भारतीय राष्ट्रिकी के हैं। लेकिन यह नहीं मालूम कि उसकी आस्तियां कितनी थीं ।

(घ) रंगून स्थित भारतीय राजदूतावास राजनयिक सूत्रों के जरिए इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है कि उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा मिल जाए और उनकी आस्तियों सहित उन्हें देशप्रत्यावर्तित किया जा सके ।

अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन

246. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ए० श्रीधरण :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष दिसम्बर के चौथे सप्ताह में बंगलौर में अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादकों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन ने अनुचित प्रतिबन्ध लगाने के तरीकों को तथा समाचारपत्रों के संसाधनों पर आधारित उग्र प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये किन्हीं उपायों का सुझाव दिया था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट सुझाव दिये गये थे ;

(ग) क्या इन सुझावों को दृष्टि में रखते हुए इन तरीकों को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है और यदि नहीं तो इन सुझावों के अनुसार और क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) इस सम्मेलन में और क्या-क्या सुझाव दिये गये थे तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा दिए गए विशिष्ट सुझाव और उन पर जो कार्रवाई की गई है या करने का विचार है, वे इस प्रकार हैं :

विशिष्ट सुझाव	की गई या की जाने वाली कार्रवाई
(1) समाचार-पत्रों पर लागू डाक की दरों को कम करना ।	डाक व तार विभाग के साथ विचाराधीन है ।

विशिष्ट सुझाव	की गई या की जाने वाली कार्रवाई
(2) सरकार को किसी भी समाचार-पत्र उद्यम में शेअर नहीं खरीदने चाहिए न ही किसी भी समाचार-पत्र या पत्रिका को अस्थायी कठिनाई पर काबू पाने के लिए सीधी सहायता, अनुदान या ऋण का प्रस्ताव करना चाहिए ।	नोट कर लिया गया है । सरकार का इस समय ऐसा कोई इरादा नहीं है ।
(3) सरकार को ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे समाचार-पत्रों में एकाधिकार की ताकतों को बल मिले ।	समाचार-पत्रों में एकाधिकार की प्रवृतियों के बढ़ावे को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, वे तारांकित प्रश्न संख्या 33 तारीख 19 फरवरी, 1969 के उत्तर में दिए गए हैं। मोनोप्लीज एंड रेसट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज बिल भी संसद के सामने है ।
(4) जो समाचार-पत्र और पत्रिकाएं कठिनाई में हों, उन्हें बिना किसी शर्त के पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार को एक स्वायतशासी वित्तीय संस्थान स्थापित करना चाहिए । प्रस्तावित समाचार-पत्र वित्त संगठन सरकारी प्रभाव, हस्तक्षेप या नियंत्रण से बिल्कुल युक्त होना चाहिए और उसका प्रबन्ध उन गैर-सरकारी व्यक्तियों को सौंपना चाहिए जो समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की कार्यप्रणाली से विज्ञ हों ।	समाचार-पत्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए दीर्घकालीन नीति का प्रश्न प्रेस परिषद के परामर्श से विचाराधीन है । यदि समाचार-पत्रों को धन देने के लिए कोई संस्थान स्थापित किया गया तो इन सुझावों पर विचार किया जाएगा ।

(घ) प्रस्ताव संख्या 2 में हिंसा को रोकने तथा बदअमनी को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा किये गये किसी भी उचित उपाय के लिए समाचार-पत्रों के सहयोग की पेशकश की गई है। प्रस्ताव संख्या 3 में सुझाव दिया गया है कि विधेयक को उचित रूप से दोबारा तरतीब दी जाए ताकि हतक के कानून को संहिता बनाई जाए ताकि हतक की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया जाए और उन धाराओं को निकाल दिया जाए जो न्याय की आधुनिक धारणाओं के विरुद्ध जाती हों ।

करांची में शिखर सम्मेलन

247. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री अदिचन : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काश्मीर, फरक्का बांध तथा भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य मामलों के बारे में गत दिसम्बर में करांची में पाकिस्तान, ईरान तथा तुर्की के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त विज्ञप्ति क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). इस विज्ञप्ति का मूलपाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-26/69]**

(ग) सरकार का मत है कि सभी भारत-पाक प्रश्नों को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए।

कड़पा और विशाखापटनम के आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

248. **डा० रानेन सेन :** **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री अदिचन :**
श्री पी० नरसिम्हा राव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंच-वर्षीय योजना में आंध प्रदेश में विशाखापटनम तथा कड़पा में आकाशवाणी के रिलेइंग स्टेशन को पूरा स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रस्ताव पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

249. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को इसकी स्थापना से लेकर अब तक अनियमितताओं, चोरी, भण्डार में कमी के कारण हुई हानि का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) सरकार ने कार्यप्रणाली में सुधार करने तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के आरम्भ से निम्न कारणोंवश उस द्वारा वहन की गई क्षतियों के विस्तार इस प्रकार हैं :

(1) बेजाबतिएं	86,093 रुपये
(2) चोरिएं	15,267 रुपये
(3) भण्डारों में कमिएं	84,870 रुपये

(ख) बेजाबतियों, चोरियों और कमियों के सभी मामलों की वी० ई० एल० द्वारा पूरी पूरी जांच की गई है, और कम्पनी द्वारा ऐसी बेजाबतियों की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए आवश्यक पग उठाए गए हैं । चोरी या धोकादेही के बड़े मामलों की पुलिस को रिपोर्ट भी की गई है ।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को सामने रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड

250. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों में रेयर अर्थ लिमिटेड के कार्यसंचालन के बारे में कोई सामान्य अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में किस प्रकार की अनियमिततायें पाई गई हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की ओर से वाणिज्य लेखा परीक्षा के निदेशक द्वारा कम्पनी के कार्यसंचालन पर एक समीक्षा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है, जिसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है । वार्षिक रिपोर्ट तथा उसकी सरकारी समीक्षा संसद् के दोनों सदनों में प्रतिवर्ष पेश की जाती है। इन रिपोर्टों से कोई ऐसी अनियमितता सामने नहीं आई जिस पर कोई सरकारी कार्यवाही जारी हो ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

251. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की कार्य-प्रणाली के बारे में अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में किस प्रकार की अनियमिततायें पाई गई हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० के बंगलौर डिवीजन के कृत्य का हाल ही में विस्तृत निरीक्षण किया गया था, और उसके कृत्य का सुधार करने के लिये कई उपाय किए गए हैं । ऐसा पता चला है कि उत्पादन, विशेषकर 1967-68 के दौरान, तकनीकी तथा उत्पादन समस्याओं और अनिवार्य सप्लाइयों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण प्रभावित हुआ है, न किन्हीं बेजाबतियों के कारण, प्रतिकारी उपाय के तौर पर उत्पादन प्रायोजन विभाग को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज हैदराबाद, से एक दल की सहायता से पुन: संगठित किया जा रहा है । हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में एरोनाटिक्स कमेटी ने भी सिफारिशें की हैं, और इन सिफारिशों के आधार पर कम्पनी के संगठनात्मक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं । हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० के कृत्य में सुधार के लिये कम्पनी द्वारा और सिफारिशें किये जाने की प्रत्याशा है ।

मंत्रालय में अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाना

252. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में वर्ष 1968 में 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होने वाले

प्रथम श्रेणी के कितने प्राधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाई गई अथवा उनकी पुनः नियुक्ति की गई ;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनकी सेवा अवधि बढ़ाने अथवा पुनः नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) एक

(ख) श्री एस० एम० मजूमदार ।

(ग) आकाशवाणी महानिदेशालय में वाणिज्यिक प्रसारण में कार्यक्रमों के निदेशक, श्री मजूमदार की सेवा अवधि सेवा निवृत होने के बाद 13 नवम्बर, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक 4 महीने के लिये बढ़ाई गई थी, क्योंकि वाणिज्यिक प्रसारण एक नया क्षेत्र था और इस सेवा को दिल्ली तथा मद्रास केन्द्रों से भी चालू करने का प्रस्ताव था तथा उनके स्थान पर तुरन्त उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं था; अतः यह आवश्यक हो गया कि वे कुछ समय तक इस कार्य को बराबर करते रहें ।

Broadcast by A. I. R. Re: Garhwalis

253. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a memorandum relating to the demonstrations staged by the "Garhwal Navjagram Samiti" was submitted to the Prime Minister on the 28th August, 1968 regarding the broadcast by A. I. R. showing disrespect to the Garhwalis ;

(b) if so, the action taken thereon ; and

(c) if not action has been taken, the rersons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information, Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir. A memorandum on the subject was submitted to the Prime Minister on 23rd August, 1968.

(b) and (c). No disrespect was intended or shown to Garhwali community in any broadeast from All India Radio. The question of taking action does not, therefore, arise.

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना

254. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें 1968 में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होना था, सेवा की अवधि बढ़ाई गई है अथवा पुनः नियुक्ति की गई है ;

(ख) ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनकी सेवा में विस्तार अथवा पुनः नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). प्रथम श्रेणी के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा अवधि उनके नामों के आगे दी गई अवधि के लिए, बढ़ा दी गई है या जब तक के लिये पुनर्नियुक्ति की गई है :

श्री आर० जी० रजवाड़े सेवा अवधि बढ़ाई गई	4-6-68 से 30-11-68
श्री सी० एस० झा सेवा अवधि बढ़ाई गई	13-11-68 से 24-12-68
श्री एम० के० किदवई पुनर्नियोजित	6-2-68 से 21-3-69
श्री आर० के० टंडन पुनर्नियोजित	10-2-68 से 4-8-68

(ग) सार्वजनिक हित में

उगांडा से भारतीयों का निकाला जाना

255. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा से भारत मूलक बहुत से एशियाई व्यक्तियों को निकाला जा रहा है ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उनके भारत में शरणार्थियों के रूप में आने की सम्भावना है ;

(घ) उनके निष्कासन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या इस मामले पर हाल में हुए राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में विचार किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). उगांडा में रहने वाले एशियाई समुदाय के लोगों को अभी निष्कासन की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है हालांकि उगांडा की सरकार कुछ ऐसे उपाय बरतने की बात सोच रही है जिनसे देश के कुछ भागों में व्यापार के कतिपय क्षेत्रों में तथा कुछ नौकरियों में वे सिर्फ अपने ही नागरिकों को रखेंगे। अनुमान लगाया जाता है कि उगांडा में एशियाई मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्तियों की संख्या लगभग 30,000 है। प्रभावित व्यक्ति चूंकि ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए वे यूनाइटेड किंगडम जाने के योग्य ही ठहरेंगे।

(ङ) प्रवासन सम्बन्धी कतिपय समस्याओं से सम्बद्ध मामलों पर सम्मेलन के बाहर राष्ट्रमंडल के कुछ देशों में अनौपचारिक रूप से बातचीत हुई थी। राष्ट्रमंडल सचिवालय के महासचिव से और आगे अध्ययन करने को कहा गया है।

Talks on Swami Dayanandji from Jammu Radio Station

257. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1281 on the 17th April, 1968 and state :

(a) whether Government have issued orders to the Officers of Jammu Radio Station to broadcast talks in respeet of Swami Dayanand and his teachings in future ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) A talk about the life and teachings of Swami Dayanand was broadcast on 15th February, 1969 on the occasion of his birth Anniversary.

Cantonment Boards

258. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the circular sent to the Cantonment Boards on the 23rd March, 1968, people have been asked to secure a new lease in place of an old one in case a new room has been constructed in their houses ;

(b) if so, whether Government have received representations from the Cantonment Boards opposing the said circular ; and

(c) if so, the action being taken by Government thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) It is correct that a letter was issued on 23rd March, 1968 consolidating various previous communications relating to the regulation of construction on "Old Grant" sites. This letter requires the licencees of Government land to take out leases before putting up additional constructions.

(b) Representations have been received from some of the Cantonment Boards.

(c) As the implementation of the communication will assist in orderly development and also ensure a proper return to Consolidated/Cantt Fund it is not proposed to modify it.

Pork Dehydrating Factory

259. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to set up a pork dehydrating factory to meet the requirements of the army ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Tundla Factory

260. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the profit likely to accrue to Tundla Factory in the current year as a result of sheep and goats being available on cheap rates consequent to the famine in Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : The processed products of the Factory are not sold but are issued to Armed Forces Personnel deployed at high altitudes, as free issues.

There can thus be no question of any profit accruing to the Accelerated Freeze Drying Factory due to availability of sheep and goats at cheap rates.

फिजी की स्वतन्त्रता

261. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की विशेष समिति की सिफारिश के अनुसार फिजी की स्वतन्त्रता के प्रश्न पर ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ उनके भारत के पिछले दौरे के दौरान बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ जो विचार-विमर्श हुआ उसमें फिजी की स्वतन्त्रता का प्रश्न भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्रसंघ की विशिष्ट समिति ने 1969 में इस प्रश्न पर विचार जारी रखने का निश्चय किया है।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त में कर्मचारियों में कमी के कारण हुई मितव्ययता

262. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4113 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों में कमी के बाद 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में कुल कितनी मितव्ययता की गई ;

(ख) क्या सरकार ने 1969-70 तथा 1970-71 के लिये व्यय में कमी करने के लिये कोई और योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत के हाई कमीशन, लंदन में अमले को कम करने के बाद 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में जो अनुमानित बचत हुई वह नीचे दिखाई गई है :

वर्ष	अनुमानित बचत पौंड स्टर्लिंग
1966-67	29,741 या 5,83,956 रुपये
1967-68	62,500* या 15,42,187 रुपये
1968-69 (31-1-69 तक)	22,000 या 3,96,000 रुपये

*"नवम्बर 1968 की घोषणा के आधार पर, 1967-68 में 76 पदों के कम किए जाने की उम्मीद थी। लेकिन असल में सिर्फ 61 पद कम किए गए। उसके परिणामस्वरूप 62,500 पौंड की बचत हुई जब कि नवम्बर 1968 की अनुमानित बचत 93,621 डालर है।"

(ख) और (ग). जी हां। और कितनी किफायत की जा सकती है, इस बात का अनुमान लगाने के लिए इस वर्ष विदेश सेवा निरीक्षकों को मिशनों में भेजने का विचार है; उनकी सिफारिश के आधार पर खर्च को और कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

263. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से निकलने वाले सेनाछात्रों को डिग्रियां देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना लागू की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). डा० जी० सी० महाजनी उपकुलपति उदयपुर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में अन्य बातों सहित इस विषय सहित एक कमेटी स्थापित की गई है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की त्रिवार्षिक पाठ्यचर्या में संशोधन किया जाय ताकि छात्र अकादमी में पूर्ण अध्ययन पाठयक्रम की सम्पूर्ति पर विज्ञान या ह्यूमैनिटीज में डिग्री के समतुल्य शिक्षा का स्तर प्राप्त कर सकें। कमेटी की रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

विदेश जाने वाले केन्द्रीय मंत्री

264 **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय मंत्रियों के बारे में कोई सिद्धांत निर्धारित किये हैं कि उनके विदेशी दौरों के दौरान वे कब केन्द्रीय मंत्रियों की हैसियत में होंगे तथा कब अपनी निजी तथा गैर-सरकारी हैसियत में होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). स्थिति सबको अच्छी तरह मालूम है और इस विषय में कोई खास नियम बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

प्रतिरक्षा लोक-सम्पर्क विभाग

265. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 27 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा लोक सम्पर्क विभाग तथा केन्द्रीय सूचना सेवा के पत्रकार कर्मचारियों के एकीकरण का प्रस्ताव इस बीच में क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

भारत का राष्ट्रमंडल को छोड़ना

266. **श्री रा० वें० नायक** :
श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत के राष्ट्रमंडल छोड़ने के बारे में कुछ बातें कही थीं ;

(ख) क्या उनके शब्दों से ब्रिटिश सरकार में कुछ चिन्ता पैदा हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं । प्रधान मंत्री ने केवल इतना ही कहा था कि राष्ट्रमंडल सदस्य तभी तक इस संगठन में रहेंगे जब तक कि यह उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Nefa and Ladakh as Parts of China

267. **Shri Kanwar Lal Gupta** :
Shri Hem Raj :
Shri Samar Guha :
Shri Mahadeva Prasad :
Shri Mrityunjay Prasad :
Shri S. Supakar :
Shri P. K. Deo :
Shri R. K. Amin :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri V. Narasimha Rao :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Russia has shown NEFA and Ladakh as parts of China in

some of their new atlases ;

(b) if so, the dates on which Government sent notes to Russia in this connection and the reply received from them hereto ;

(c) whether it is also a fact that Russia had shown some parts of India in other countries in their atlases previously also ; and

(d) if so, the reasons for Russia repeating this mistake time and again ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have raised the matter through diplomatic channels and have sought correction of the erroneous depiction.

(c) Yes, Sir.

(d) The Soviet authorities have promised to look into the matter.

Protest notes sent to China and Pakistan

268. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of protest notes sent by India to China and Pakistan up till now and the number of those replied to by both the countries ;

(b) the number of the protest notes accepted by both the countries and the number of those which were not accepted ; and

(c) the number of cases where some other steps were also taken by the Government of India in addition to sending the protest notes ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c). As far as correspondence with China is concerned, these have been included in 14 White Papers which have been tabled in Parliament from time to time. Hundreds of notes have been exchanged with the Pakistan Government. Apart from sending protest notes, the Government of India have taken appropriate action as warranted in the circumstances of each case.

मार्क्सवादी कार्यकर्ता को चीनी दूतावास का पत्र

269. **श्री हेमराज :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री हेम बरुआ : **श्री समर गुह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मार्क्सवादी कार्यकर्ता श्री बुला कृष्णन को चीनी दूतावास द्वारा भेजे गये पत्र की प्रामाणिकता के बारे में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि ये पत्र चीनी दूतावास द्वारा लिखे गए हैं।

सामुदायिक विकास विभाग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

270. **श्री हेमराज** : क्या **प्रधान मंत्री** 20 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सामुदायिक विकास तथा सहकारिता सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग ने सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है। तथापि भारत सरकार की कार्य-व्यवस्था तथा उसके कार्य करने की प्रक्रिया सम्बन्धी उसके प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि वर्तमान दो पृथक विभागों के स्थान पर सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के लिए केवल एक छोटा तथा संयुक्त विभाग होना चाहिए। प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रिपरिषद सचिवालय का विस्तार

271. **श्री सुदर्शनम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण मामलों पर केन्द्र तथा राज्यों के बीच उचित सम्पर्क बनाये रखने के लिये मंत्रिपरिषद सचिवालय का विस्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा और इस विस्तार का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को तुर्की द्वारा अमरीकी टैंकों की सप्लाई

272. **श्री म० सुदर्शनम :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री इशहाक साम्भली :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री क० लकप्पा :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री प० मु० सईद :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री अदिचन :

श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री भोला नाथ मास्टर :**

श्री ए० श्रीधरन : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टर्की पाकिस्तान को अमरीकी पैटन टैंक देने को सहमत हो गया है अथवा दे चुका है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने टर्की से इस बारे में विरोध प्रकट किया था ;

(ग) यदि हां, तो उस सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि टर्की ने विरोध नामंजूर कर दिया है तो सरकार ने अमरीका सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). हमारी सूचना के अनुसार, अभी तक तुर्की ने पाकिस्तान को टैंक देने के किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। पाकिस्तान को हथियार देने के सम्बन्ध में भारत सरकार के विचारों से तुर्की, संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य मित्र देशों की सरकारों को एक से अधिक बार अवगत कराया जा चुका है।

सैनिक समाचार

273. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना का समाचारपत्र "सैनिक समाचार" सात भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होता है ;

(ख) यदि हां, तो उन भाषाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक भाषा में "सैनिक समाचार" की कितनी प्रतियां प्रकाशित होती हैं ;

(ग) क्या बंगाली भी एक ऐसी भाषा है जिसमें यह समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होता ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय सेना में कार्य कर रहे बंगाली कर्मचारी सामान्यतया बंगाली भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा नहीं जानते, सरकार उक्त समाचारपत्र को बंगाली भाषा में भी मुद्रित करने पर विचार करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) सशस्त्र सेनाओं का चित्रित साप्ताहिक सैनिक समाचार इसे 9 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।

(ख) भाषाओं के नाम और उनमें छापी गई प्रतियों की संख्या इस प्रकार है :

क्रम-संख्या	भाषा	16-2-69 के मुद्रण आर्डर के अनुसार प्रतियों की संख्या
1	अंग्रेजी	4332
2	हिन्दी	9669
3	गोरखावली	483
4	मराठी	1773
5	पंजाबी	3797
6	उर्दू	819
7	तिलेगु	504
8	तामिल	1061
9	मलयालम	2484

(ग) से (ङ). पत्रिका को बंगाली और अन्य कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का प्रश्न, कि जिनमें इस समय इसे छापा जाता, विचाराधीन है ।

अखनकाडु स्थित कोरडाइट फैक्टरी

274. **श्री के० रमानी :** **श्री नम्बियार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री उमानाथ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीलगिरी स्थित अखनकाडु कोरडाइट फैक्टरी के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से हटा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से हटाये गये कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार को उनके मामलों पर पुनर्विचार के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). किसी कार्मिक को डिस्मिस नहीं किया गया । तदपि, 134 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार समाप्त की गई थीं ।

(ग) जी हां । कई कर्मचारियों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) अभिवेदन विचाराधीन हैं ।

पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों के बारे में प्रधानमंत्री का बी० बी० सी० से इन्टरव्यू

275. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मंत्री ने बी० बी० सी० के साथ अपने टी०वी० इन्टरव्यू में कहा है कि वह नहीं जानतीं कि पूर्वी अफ्रीका से जबरदस्ती निकाले गये भारतमूलक ब्रिटिश नागरिकों का भारत में स्वागत किया जायेगा अथवा नहीं ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री के उक्त वक्तव्य का अर्थ यह है कि भारत ऐसे प्रवासियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं करना चाहेगा उनको इंग्लैंड में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाय ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रधान मंत्री के उक्त वक्तव्य का क्या तात्पर्य है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार ने अखबारों में ऐसी खबरें देखी हैं। प्रधान मंत्री ने बी० बी० सी० टेलीविजन की भेंट में यह बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक का प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कठिनाइयों के प्रति उन्हें पूरी सहानुभूति है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान और चीन से नागाओं को सहायता

276. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री बलराज मधोक :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके आश्वासनों के बावजूद विद्रोही नागा नेताओं को पाकिस्तान तथा चीन से बराबर हथियार प्राप्त हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्रोही नागा अब भी प्रशिक्षण के लिये इन देशों को बराबर जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विद्रोही नागाओं के साथ समझौते की नीति जारी रखना वांछनीय समझती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विद्रोही नागाओं के प्रति सरकारी नीतियों में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). छिपे नागाओं ने चीन और पाकिस्तान से हथियारों की सहायता और प्रशिक्षण लेने की अपनी कोशिशें अभी छोड़ी नहीं हैं वे इस उद्देश्य से इन देशों को अपने दल भी भेजते रहे है, हालांकि हाल के महीनों में हमारी सुरक्षा सेनाओं ने इस दिशा में उनके प्रयत्न विफल कर दिए हैं।

(ग) और (घ). छिपे नागाओं की समस्या कानून और व्यवस्था की समस्या है; नागा राज्य सरकार और उस क्षेत्र में काम करने वाली सुरक्षा सेनाएं शांति चाहने वाले नागाओं को छिपे नागाओं की लूटपाट से बचाने के लिए हर सम्भव कदम उठा रही हैं। छिपे नागाओं की सभी गैर-कानूनी गतिविधियों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। नागा लोगों ने निर्वाचन द्वारा उस पार्टी को सत्ता सौंपी है जो 1960 में नागा नेताओं के साथ हुए समझौते का पूरा समर्थन करते हैं जिसके अनुसार नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी।

दिल्ली में हनोई के वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी द्वारा एक भारतीय लड़की का अपहरण

278. **डा० महादेव प्रसाद** :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री रा० वें० नायक :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हनोई वाणिज्य दूतावास के एक कर्मचारी ने हाल ही में एक भारतीय लड़की का अपहरण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र

279. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के बारे में स्वीकृति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) ट्रांसमीटर के लगाने के लिए स्थान अधिग्रहण कर लिया गया है और निर्माण-कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है । स्टूडियो के निर्माण के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए कार्यवाही चल रही है ।

समाचारपत्रों में साम्प्रदायिक लेख

280. **श्री न० कु० सांघी** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक लेखों के लिये समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं की जांच करने के हेतु कोई उपयुक्त व्यवस्था करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में छपने वाले साम्प्रदायिक लेखों की जांच पहले ही पत्रसूचना कार्यालय और मुख्य प्रेस सलाहकार के कार्यालय द्वारा की जा रही है ।

तकनीशनों तथा अधिस्नातकों की बेरोजगारी की समस्या

281. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में तकनीशनों तथा अधिस्नातकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(ग) क्या पिछले नवम्बर में योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा अपने एक भाषण में जिन "प्रौद्योगिकीय द्विविधा (टैक्नोलाजिकल डिलेमा) और जापानी तरीकों (जापानीज वे)" का उल्लेख किया था । उनके प्रभावों का अध्ययन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) पांचवीं योजना में शामिल की जाने वाली स्कीमें विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ). इनका अध्ययन किया जा रहा है । भारत में मध्यवर्ती ढंग की टेक्नालाजी अपनाने का क्षेत्र विद्यमान है पर इसे रूपानुकूल करने के लिये पर्याप्त मात्रा में अनुसन्धान करना होगा ।

Broadcast of Talk 'Under Twenty-Five'

282. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a talk 'Under Twenty-Five' was broadcast from 'Delhi B' Station of All India Radio in January, 1969;

(b) if so, whether it is a fact that the two youngmen who participated in the aforesaid talk were more than twenty-five years of age; and

(c) if so, why the said youngmen were allowed to participate in the talk?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Two programmes entitled "Under Twenty-Five" and not a talk were broadcast from the Delhi Station during January, 1969.

(b) All participants in these two programmes, except the moderators, were students and are believed to have been below 25 years in age. The information about exact ages of different participants is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) Does not arise for the present.

केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक परियोजनाएं

283. **श्री अदिचन** :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं को छोड़कर सभी नयी औद्योगिक परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस निर्णय के अन्तर्गत किन-किन बड़ी परियोजनाओं को रद्द अथवा स्थगित कर दिया गया है;

(ग) चौथी योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनाओं समेत किन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायगा अथवा करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चौथी योजना के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

जाम्बिया से भारतमूलक निवासियों का निकाला जाना

284. **श्री बलराज मधोक :**
श्री समर गुह :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री दिनकर देसाई :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री क० लकप्पा :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री स० कुन्दू :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाम्बिया ने भी कीनिया की तरह भारत तथा एशिया मूलक निवासियों को निकालना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार ने वहां पर भारत मूलक निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जाम्बिया सरकार की अप्रैल 1968 में घोषित आर्थिक सुधार की नीति के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1968 के बाद कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में और विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर और किसी भी गैर-जाम्बियाई के लिए व्यापार लाइसेंस पुनर्नवीकृत नहीं किये जाने थे ।

(ख) हमारे हाई कमीशन से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इसका करीब 700 परिवार प्रमुखों पर असर होगा, जो सभी ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं ।

(ग) चूंकि करीब सभी व्यक्ति जो इससे प्रभावित हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं; उनके लाभों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मूलरूप से यूनाइटेड किंग्डम की सरकार पर है ।

भारतीय मिशनों के अध्यक्षों के रूप में राजनीतिज्ञ

285. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रा० की० अमीन :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में मिशनों के अध्यक्षों के रूप में राजनीतिज्ञों को नियुक्त करने की नीति के कारण भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों में काफी असंतोष है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। ऐसे किसी असंतोष के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Film Finance Corporation

286. **Shri Deven Sen**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the funds of Film Finance Corporation are being utilised for raising the standard of art or for earning money and the number of films to which grants have been given by the said Corporation so far ;

(b) whether it is a fact that the films to which funds were allotted have neither shown additional income nor raised the standard of art ; and

(c) if so, the reasons for which Government are conducting the business which is running at a loss and the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Brodcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The funds of Film Finance Corporation are being utilised for financing the production of purposeful films of good standard and quality, with a view to raising the standard of films, in accordance with the objects and reasons enunciated in the Memorandum of Association of the Corporation. While granting a loan, reasonable prospects of return of loan with interest are also taken into account. From its inception in March, 1960 to 31st January, 1969 the Corporation had given loans for 63 films.

(b) It is not correct that films financed by the Corporation have neither shown additional income nor raised the standard of art. Loans have been fully recovered with interest from about 50 per cent of the total number of the released films and about 50 percent of the released films have won awards, prizes, certificates of merits, national/international recognition or were granted exemption from entertainment tax on account of their thematic value and artistic merit.

(c) The role of the Corporation cannot be viewed from the investment angle alone. Its promotional role is more important which is significant inspite of the initial losses due to several reasons. However, efforts are being made to get incomplete films completed and to facilitate full exploitation of composed films in the open territories and to recover debts by suitable legal steps, wherever possible.

कोरापुट स्थित कारखाने से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति

287. **श्री देवेन सेन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरापुट स्थित कारखाने से उच्च अर्हता प्राप्त कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने किन-किन पदों से त्यागपत्र दिये हैं;

(ग) त्यागपत्र देने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें त्यागपत्र देने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों में कोरापुट डिवीजन से त्यागपत्रों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

तकनीकी	1966	1967	1968
300-600 रुपये	1	2	2
500-860 रुपये	2	1	—
700-1,200 रुपये	1	—	1
1,600-2000 रुपये	—	—	1
प्रबंधक			
350-600	2	4	2
700-1,250	—	1	—
कुल	6	8	6

एक त्यागपत्र का कारण था स्वास्थ्य, और दूसरे व्यक्तिगत कारणोंवश ।

(घ) चूंकि त्यागपत्र बड़े पैमाने पर न थे, किसी विशेष पग की आवश्यकता नहीं है ।

Aeroplane Manufacturing Factory, Kanpur

288. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the extent of foreign components in the aeroplanes being manufactured at Kanpur ;

(b) whether Government import cent per cent parts of these aeroplanes and only assemble them but the people are told that these aeroplanes have been manufactured in India ; and

(c) the number of parts manufactured at Bangalore and utilized by the aeroplane manufacturing factories of Kanpur and the number of those exported ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). It is not correct that cent per cent parts of HS 748 aircraft are imported and these are only assembled at Kanpur. The manufacture of airframe of HS 748 aircraft at Kanpur has been undertaken in phases. The first phase, in which all parts were imported, has already been completed. The manufacture of certain parts at Kanpur has been undertaken in the second phase and a few aircraft manufactured in this phase have already been delivered. The percentage of imported items to the total value of aircraft in this phase is 54%.

(c) HS 748 aircraft manufactured at Kanpur are fitted with Dart RDA 7 engines which are manufactured and supplied by the Bangalore Division of HAL. No other parts for this aircraft are manufactured at Bangalore. Bangalore Division has so far exported engines and engine parts of the value of £ 119,000.

केनिया के भारतीयों को भारत में बसाना

289. **श्री देवेन सेन :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री श्रीचंद गोयल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनिया के जिन भारतीयों के पास ब्रिटिश पारपत्र हैं, उन्होंने सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें उन्होंने भारत में बसने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि केनिया के कानूनों के कारण जो भारतीय विस्थापित हो गये हैं उन्हें ब्रिटेन के स्थान पर भारत जाने की अनुमति दी जाये;

(घ) यदि हां, तो केनिया के भारतीयों के इस अनुरोध के बारे में ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार का क्या रवैया है; और

(ङ) ऐसे केनियावासियों की संख्या कितनी है जिनके पास ब्रिटिश पारपत्र हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां। कीनिया में रहने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारी ऐसे व्यक्तियों को फिर से बसाने के विषय में ब्रिटेन की सरकार के साथ पहले ही प्रबंध कर दिए गए हैं जिन्हें कीनिया छोड़ने के लिए मजबूर किया जाय और जो भारत आना चाहते हों।

(ग) इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार कुछ और ब्योरों का इन्तजार कर रही है जिसके आने पर वह इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

(घ) भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कीनिया में एशियाई मूल के ब्रिटिश पासपोर्ट-धारियों की संख्या 60 और 80 हजार के बीच है।

फाजिलका क्षेत्र में "टावरों का" गिराया जाना

290. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री बाबूराव पटेल :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्रीमती इलापाल चौधरी:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1961 में पाकिस्तान के साथ एक करार हुआ था जिसके

अनुसार फाजिलका क्षेत्र में निर्मित पर्यवेक्षक 'टावर' तथा 'पीकेट' तोड़े जाने थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने अब तक ये 'टावर' और 'पीकेट' नहीं तोड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन "टावरों" और "पीकेटों" को तुड़वाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस करार के अंतर्गत पाकिस्तान को पंजाब-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा की 150 गज दूरी में आने वाले पांच बुर्जों को तोड़ना था । उनमें से उन्होंने केवल दो ही तोड़े हैं ।

1962 और 1963 के दौरान पाकिस्तान सरकार को जो विरोधपत्र भेजे गए थे उनका विषय इस करार को क्रियान्वित करने में पाकिस्तान की असफलता ही थी । 1965 की लड़ाई में इनमें से दो और बुर्जे गिरा दीं—एक बुर्ज अब भी खड़ी है ।

अपोलो 8 के संकेत प्राप्त करना

291. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत की अन्तरिक्ष वेधशाला, अपोलो 8 द्वारा भेजे गये संकेतों को प्राप्त कर सकी थी; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागालैंड में चीनियों द्वारा घुसपैठ

292. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागाओं के साथ कुछ चीनी नागरिक भारत में घुस आये हैं और नागालैंड और आसाम में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन घुसपैठियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्रमिकों से सम्बन्धित समाचार-पत्र

293. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रकाशित होने वाले ऐसे समाचारपत्रों/साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिकाओं की संख्या कितनी है जो श्रमिकों तथा उनके हितों से सम्बन्धित है;

(ख) वे किन मजदूर संघों से सम्बन्धित हैं;

(ग) वे किन राज्यों से प्रकाशित किये जाते हैं;

(घ) क्या सरकार को उनकी श्रम विरोधी नीति तथा उनके द्वारा विश्व के सामने भारतीय श्रमिकों के बारे में गलत स्थिति रखने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जैसा कि भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के रिकार्डों में उपलब्ध है, अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

साप्ताहिक	—	23
पाक्षिक	—	41
मासिक	—	111
अन्य	—	14
	योग ...	189

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

नागाओं के साथ बातचीत

294. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री बालमीकि चौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री अदिचन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मीठालाल मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री धी० ना० देव :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे नागाओं के किसी गुट ने सरकार के साथ पुनः बातचीत आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से किस गुट ने और इनके नेताओं की हैसियत क्या है; और

(ग) बातचीत करने के उनके अनुरोध के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जैसा की सदन को याद होगा अगस्त 1968 में नागाजन सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास करके यह सुझाव दिया गया था कि जनता के भरोसे के नेताओं को साथ लेकर भारत सरकार और नागा राष्ट्रीय परिषद के बीच बातचीत फिर शुरू की जाए।

छिपे नागाओं के जुंगती गुट के नेताओं से हाल ही में सरकार को एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने बातचीत फिर शुरू करने के लिये कहा है।

(ग) सरकार का मत यह है कि 1960 में नागा नेताओं से नागा समस्या के बारे में फैसला हो गया था और अब वर्तमान स्थिति में आगे बातचीत करने की गुंजाइश नहीं है। भारत सरकार का विचार नागालैंड में कानून के अनुसार बनाई गई सरकार का पूरा-पूरा समर्थन करने का है और वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने का है।

विमान उद्योग

295. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विमान उद्योग में लड़ाकू विमानों का विकास करने के लिये कोई योजनायें बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन विदेशी निर्माताओं के साथ सहयोग अथवा तकनीकी जानकारी संबंधी करार किये गये हैं अथवा इनके बारे में बातचीत की जा रही है; और

(ग) क्या इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये विमान उद्योग के सभी प्रभागों को एक ही एकक के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) देश में लड़ाका विमान के विकास के लिए योजनाएं हैं।

(ख) इस विमान के विकास के लिए किसी प्रकार के विदेशी सहयोग की मांग का विचार नहीं है।

(ग) इस विमान के अभिकल्पन और विकास में इस समय देश में प्रवत्त यूनिट, केवल हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० बंगलौर है। समाविष्टि का कोई प्रश्न नहीं उठता, यद्यपि देश में प्राप्य सभी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा।

सरकारी प्रचार का केन्द्रीकरण

296. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री पी० सी० अदिचन :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्यों में सरकारी प्रचार के केन्द्रीकरण की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). राज्यों के सूचना मन्त्रियों की हाल ही के सारे क्षेत्रीय सम्मेलनों में यह विचार प्रगट किया गया था कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सारे प्रचार कार्य का सम्बन्धित प्रचार विभागों में केन्द्रीकरण हो जाना चाहिए ताकि खर्चे में बचत हो और अलग-अलग यत्न न करने पड़ें। इस सिफारिश पर केन्द्रीय और राज्य सरकारें यथासमय कार्यवाई करेंगी।

चिलका में नौसैनिक प्रशिक्षण संस्था

297. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 20 नवम्बर 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में चिल्का झील में एक नौसैनिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने के बारे में नौसैनिक बोर्ड के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) प्रस्तावित प्रशिक्षण संस्था को किस तारीख तक स्थापित करने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस प्रावस्था पर तिथि बताना संभव नहीं है।

सरकारी सामान

298. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फीरोजपुर में एम० ई० एस० के कुछ अधिकारी सरकारी सामान तथा सम्पत्ति निजी कार्यों के लिये इस्तेमाल में लाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि एम० ई० एस० फिरोजपुर के कुछ अफसर सरकारी सामान और सम्पत्ति का निजी उद्देश्यों के लिये प्रयोग कर रहे हैं। तदपि, 31 दिसम्बर, 1968 को एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ है, और उसकी जांच की जा रही है।

पारपत्र फार्म

299. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली कार्यालय में पारपत्र फार्म उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को ये फार्म उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। दिल्ली पारपत्र कार्यालय में भारत-पाकिस्तान पारपत्र के लिए आवेदन-पत्रों का अभाव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग में इलेक्ट्रोनिक संगणक

300. **श्री शशिभूषण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के संगणक केन्द्र में लगाये गये इलेक्ट्रोनिक संगणक का जिसके चलाने पर प्रति वर्ष कुछ लाख रुपयों का खर्च आता है, प्रयोग उसकी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो बहुत जल्दी आंकड़े तैयार करने वाले इस उपकरण का पूरा लाभ उठाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या

301. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री को० सूर्यनारायण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या का अध्ययन करने के लिये दो सरकारी कार्यकारी दल नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या इन कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) ये रिपोर्टें शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

(ग) इस सम्बन्ध में आगे की जाने वाली कार्यवाही पर रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद विचार किया जायेगा।

श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति

302. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक : **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से भारत लौटने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो यहां पर अब तक पहुंच चुके हैं ;

(ख) क्या उनके प्रत्यावर्तन के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) उन्हें बसाने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अक्तूबर, 1968 के अन्त तक श्रीलंका से भारत आने वाले देश प्रत्यावर्तियों की संख्या करीब 6,500 है।

(ख) श्रीलंका से भारतीय राष्ट्रिकों के देश प्रत्यावर्तन का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

(ग) सदन की मेज पर श्रीलंका से आने वाले देश प्रत्यावर्तियों के लिये पुनर्वास विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्वास सहायता का एक ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(1) अधिकतम 5000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से व्यापार और व्यवसाय के लिये ऋण दिया जायेगा ।

(2) श्रीलंका से देश प्रत्यावर्तित होने वाले लोगों को रोजगार दफ्तरों के माध्यमों से केन्द्र सरकार के अन्तर्गत होने वाली नियुक्तियों में प्राथमिकता दी गई है ।

(3) रोजगार दफ्तरों के माध्यम से केन्द्र सरकार की नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक कर दी गई है (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 50 वर्ष)

(4) संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में भी अधिकतम आयुसीमा 3 वर्ष बढ़ा दी गई है और फीस में भी रियायत की गई है ।

(5) मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों ने भी अपने राज्यों के पदों और फीस की रियायतें प्रदान की हैं । दूसरी राज्य सरकारों से भी इसी तरह की कार्रवाई करने के लिये कहा गया है ।

(6) विशाखापटनम और मद्रास में नियुक्त विशेष नियोजन संपर्क अधिकारी देश प्रत्यावर्तियों को नियोजन सम्बन्धी सहायता देंगे ।

(7) कृषेतर और कृषि सम्बन्धी व्यवसायों में लगे देश प्रत्यावर्तियों को प्लाट खरीदने और मकान बनाने के लिये ऋण की सहायता दी जायेगी, जैसाकि नीचे बताया गया है :

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	रु०	रु०
(क) प्लाट की कीमत	600 (ऋण)	200 (ऋण)
(ख) मकान बनाने की लागत	2,000 (ऋण)	1,250 (ऋण)
(ग) भूमि विकास	1,500 (ऋण)	600 (अनुदान)
(घ) व्यापार की जगह के लिए	500 (ऋण)	200 (ऋण)
	4,600	2,250

(8) देश प्रत्यावर्तियों के स्कूल और कालेज में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें खरीदने के लिये 5 रु० से लेकर 100 रु० वार्षिक के हिसाब से पुस्तक अनुदान दिया जायेगा। हाई स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 40 रु० से लेकर 60 रु० प्रति माह की शिक्षावृत्ति भी दी जा सकती है बशर्ते कि वे छात्र अपने माता-पिता से अलग होस्टल में रहता हो और उसके माता-पिता की आमदनी 250 प्रति माह से कम हो; इसकी एक शर्त छात्रों द्वारा इम्तेहान में एक निश्चित संख्या से अधिक नम्बर पाना भी होगी।

(9) जिन खेतीहर देश प्रत्यावर्तियों को जमीन दी गई है उन्हें बैल, बीज, उर्वरक खरीदने के लिये ऋण दिया जा सकता है, जैसाकि नीचे बताया गया है :

मद		किसी एक परिवार को दी जाने वाली अधिकतम राशि
(क)	(1) बैल जोड़ी के लिये	550
	(2) बीज और उर्वरक के लिये	125
	(3) कृषि उपकरणों के लिये	175
		850

(ख) अगर देश प्रत्यावर्ती को दी गई जमीन में नाइट्रोजन, फासफेट्स और पोटास की कमी हो तो ऐसे मामलों में 165 रु० का अतिरिक्त ऋण भी उर्वरक के लिये दिया जा सकता है।

(10) पुनर्वास विभाग ने निम्नलिखित योजनाएं स्वीकार की हैं।

राज्य	योजना का नाम	लागत (रु० लाखों में)
तमिलनाडु	नीलगिरि चाय बागान योजना	92.71
	नारियल बागान योजना	3.60
मैसूर	सुलिया रबर बागान योजना	275.13
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कच्छल द्वीप में रबड़ बागान	450.00

प्रथम प्रतिरक्षा योजना

303. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम प्रतिरक्षा योजना (1964—68) में कितनी सफलता मिली है इस बारे में कोई पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) प्रतिरक्षा के मामले में देश कहां तक आत्म-निर्भर हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। 1964—69 रक्षा योजना के अन्तर्गत कृत्य का समय-समय पर पुनरीक्षण किया गया है।

(ख) सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण और पुनस्सज्जन एक निरन्तर प्रक्रिया है, और प्राय: योजना के अनुसार ही चलती है।

(ग) हमारा लक्ष्य है आत्म निर्भर उत्पादन बेस। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है, और देशीय विकास और उत्पादन के लिये अधिक और अधिक मदें बढ़ाई गई हैं। तकनीकी मार्ग प्रदर्शन करके और द्रव्यों की उपलब्धि में विशेष सहायता देकर असैनिक उद्योगों में भी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है। तदपि, नानफेरस धातुओं, कुछ विशिष्ट फौलादों और अलायों, तथा इलेक्ट्रानिक्स, एरोनाटिक्स और औजार बनाने में हमें अभी विदेशी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है ; और देश में विकासित हो रहे औद्योगिक बेस की सहायता से इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

संयुक्त अरब गणराज्य स्थित भारतीय दूतावास में विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारी

304. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य स्थित भारतीय दूतावास में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनमें से कितने कर्मचारी अरबी अथवा फ्रांसीसी अथवा दोनों भाषायें जानते हैं; और

(ख) उपयुक्त दूतावास में कितने प्रेस सहचारी काम कर रहे हैं तथा उनमें से कितने व्यक्ति उपर्युक्त दोनों अथवा एक भाषा जानते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग का प्रचार अनुभाग

305. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये प्रधान मंत्री जब हाल में ब्रिटेन गई थीं और उन्होंने वहां पर भारतीय विद्यार्थियों को भाषण दिया था तो भारतीय विद्यार्थियों ने उस समय भारत की प्रगति के बारे में असहमति प्रकट की थी क्योंकि उनको विदेशी सूचना साधनों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में देश की प्रगति की निराशाजनक जानकारी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धारणा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विदेशी प्रचार साधनों द्वारा गलत चित्रण का खण्डन करने के लिये भारतीय उच्चायोग क्रियाशील नहीं है; और

(ग) भारतीय उच्चायोग के प्रचार अनुभाग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अब क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि वह देश का सही चित्रण देने के मामले में कारगर रूप से काम करे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

ब्रिटेन में भारतीय उत्प्रवासियों का व्यवहार

306. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि समय-समय पर भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों के अभद्र और असभ्य व्यवहार के कारण देश की तस्वीर मैली हो गई है और इससे देश का सम्मान गिरा है;

(ख) क्या लंदन स्थित हमारे उच्चायोग ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) उन उत्प्रवासियों पर उच्चायोग का क्या नियंत्रण रक्खा जाता है जिससे ऐसा दुर्व्यवहार पुनः न हो; और

(घ) ऐसे कितने उत्प्रवासियों को उनके दुराचरण के कारण गत चार वर्षों में वहां से निकाला गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि सारे अथवा अधिकांश भारत आप्रवासी अभद्र और असभ्य व्यवहार करते हैं;

(ख) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) हमारा हाईकमीशन उन पर जबर्दस्ती कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता । लेकिन उन्हें उचित सलाह देने की कोशिश जरूर करता है ।

(घ) 1968 में बुरे व्यवहार की वजह से किसी व्यक्ति को भारत वापस भेजने का एक मामला हुआ था ।

दिल्ली में जन संचार संस्था

307. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित जन संचार संस्था ने लोगों को निश्चित परिणाम और लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कहां तक कारगर काम किये हैं;

(ख) उसे विदेशी प्रतिष्ठान और भारत सरकार से कितना अनुदान मिलता है; और

(ग) जब से यह संस्था बनी है तब से लेकर अब तक इसने अनुदानों का कहां तक कारगर प्रयोग किया है तथा कर्मचारियों, प्रचार, इमारतों, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्तों तथा अन्य मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय का पृथक्-पृथक् ब्योरा बताया जाये ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 27/69]

भारतीय लड़के द्वारा लड़की के वेश में लंदन में प्रवेश करने का प्रयास

308. **श्री मयावन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4983 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लड़के द्वारा लड़की के वस्त्र पहन कर लंदन में प्रवेश करने के प्रयास सम्बन्धी मामले की इस बीच जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या सरकार को ब्रिटेन की सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सरकारी पत्र मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). इस बारे में जांच-पड़ताल अभी चल रही है और इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

टेलीविजन बनाने वाली लाइसेंस शुदा फर्में

309. **श्री मयावन :**

श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन बनाने के लिये कितनी फर्मों को लाइसेंस दिया गया है;

(ख) उन फर्मों की वार्षिक क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) भारत में बने टेलीविजन सेट बाजार में कब तक मिलने की सम्भावना है; और

(घ) इन टेलीविजन सेटों का लगभग कितना मूल्य होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). बड़े पैमाने की दो फर्मों को प्रतिवर्ष दस दस हजार टी० वी० सेट निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिए गए हैं। छोटे पैमाने की फर्मों की

दो कन्जोर्टियां प्रतिवर्ष पांच-पांच हजार सेट निर्माण करने के लिए क्षमता स्थापित कर रही हैं। बड़े पैमाने की दो फर्मों में से एक ने उत्पादन आरंभ कर दिया है, और उनके सेट बाज़ार में आ गए हैं। इन चार यूनिटों के अतिरिक्त सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी रिसर्च इन्स्टीच्यूट (सी० ई० ई० आर० आई०) पिलानी पाईलाट संयंत्र के तौर पर 1000 टी० वी० सेटों का निर्माण कर रहा है।

(घ) सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी ने अपने 23 इंच पर्दे वाले सेट की लागत 1500 रुपये नियत की है, और 19 इंच पर्दे वाले सेट की 1350 रुपये। जिस फर्म ने उत्पादन शुरू कर दिया है उसने 23 इंच पर्दे वाले सेट की लागत 1900 रुपये घोषित की है।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा बेरोजगारी के बारे में योजना आयोग को दिये गये सुझाव

311. **श्री शशिभूषण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगारी दूर करने के लिये स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 1957 में योजना आयोग को कई सुझाव दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने उन सुझावों पर फिर से विचार किया है और स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा सुझाये गये उपचारात्मक उपाय अख्तियार किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) योजना आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने समय-समय पर विविध सुझाव दिये थे जिनमें रोजगार की समस्या से संबंधित सुझाव भी शामिल थे। इनको उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के प्रलेखों में समाविष्ट कर लिया गया है।

(ख) और (ग). सरकार रोजगार की स्थिति पर सावधानी से निगाह रखती रही है और समय-समय पर उपयुक्त उपचारात्मक उपाय अपनाती रही है।

योजना आयोग का पुनर्गठन

312. **श्री शशिभूषण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्तरिक पुनर्गठन समिति ने, जिसे योजना आयोग के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये स्थापित किया गया था, अभी तक अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है; और

(ख) इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार का विचार कब तक अन्तिम कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) योजना आयोग के कार्यालय की कार्यपद्धति और आवश्यक कर्मचारी वर्ग की समीक्षा करने के लिये और योजना तन्त्र के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन और दीर्घकालीन पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करने के लिए योजना आयोग में एक आन्तरिक पुनर्गठन समिति गठित की गई थी। समिति ने गत वर्ष अपनी अन्तर्कालीन रिपोर्ट दे दी थी और इसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) योजना आयोग के गठन और उसके कर्मचारी वर्ग के बारे में की गई प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ सिफारिशों पर, पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, अन्य सिफारिशों पर, जिनकी कि जांच आन्तरिक पुनर्गठन समिति द्वारा की जा रही है, समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जायेगी।

कीनिया तथा मलावी में भारतीय व्यापारियों को लाइसेंस देने से इन्कार करना

313. **श्री समर गुह** :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री दिनकर देसाई :
श्री क० लकप्पा :
श्री स० कुन्डू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कीनिया तथा मलावी में भारतीय व्यापारिक समुदाय को उन देशों में व्यापार करने के लिये लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिस्थिति का सामना करने तथा भारतीय व्यापारिक समुदाय की सहायता करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जहां तक कीनिया का संबंध है, कीनिया सरकार ने 31 दिसम्बर, 1968 को उन लोगों से व्यापार लाइसेंस वापस ले लेने की घोषणा की, जो कीनिया के नागरिक नहीं हैं। इस घोषणा के अनुसार, 1969 के पूर्वार्द्ध में, लगभग 3,000 लाइसेंसदारों पर असर पड़ेगा। इस तरह के 700 लाइसेंसदारों को नोटिस मिल चुके हैं। मलावी सरकार ने अब तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है।

(ख) और (ग). कीनिया में जिन व्यक्तियों पर इसका असर पड़ेगा वे चूंकि ब्रिटिश नागरिक हैं अत: उनके लिये ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी है। जहां तक कीनिया में भारतीय मूल के ब्रिटेन के नागरिकों का संबंध है, उन लोगों के पुनर्वासन के संबंध में भारत सरकार और ब्रिटेन के बीच प्रबन्ध किए जा चुके हैं जिन्हें कीनिया छोड़ने पर वाध्य किया जाए जो भारत आना चाहते हैं।

अपोलो-8 के जमीन पर उतरने के बारे में समाचार

314. **श्री समर गुह :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री स० कुन्डू :**
श्री दिनकर देसाई :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने अपोलो-8 के पृथ्वी पर उतरने के बारे में ठीक समय पर समाचार नहीं दिया; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिड़ला की इथोपिया यात्रा

315. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री ज० अहमद :**
श्री क० लकप्पा : **श्री स० कुन्डू :**
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वश्री जी० डी० बिड़ला, बी० के० बिड़ला और ए० वी० बिड़ला हाल में इथोपिया गये थे और उन्होंने इथोपिया की सरकार के मंत्रियों के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विचार-विमर्श करने तथा इथोपियन सरकार को आर्थिक सहायता का आश्वासन देने का अधिकार प्रदान किया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) बिड़ला परिवार इथोपिया में सम्मिलित रूप से कुछ उद्योग चला रहा है । सरकार को सूचना दी गई थी कि इथोपिया की शाही सरकार के निमंत्रण पर सर्वश्री जी० डी० बिड़ला, बी० के० बिड़ला और ए० वी० बिड़ला हाल ही में इथोपिया गये थे और यह भी कि इथोपिया में उन्होंने अपनी-अपनी निजी हैसियत में औद्योगिक क्षेत्र में और सहयोग करने की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Demonstration before Marlborough House

316. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demonstration was staged in front of the Marlborough House when the Prime Minister reached there during her visit to England in January, 1969; and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). There were small groups of demonstrators outside Malborough House during the Commonwealth Prime Ministers Conference. The demonstrations which were peaceful, were by different groups and on a varied assortment of issues ranging from support for Biafra to call for the banning of germ warfare. A few demonstrators had placards demanding a plebescite in Kashmir. No action by the Government of India is called for.

Indian Property Damaged in China and Tibet

317. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the value of Indian property damaged as a result of demonstrations, gheroas and other violent incidents in China and Tibet by the Chinese citizens during the last five years ;

(b) the total number of incidents during the said period involving damage to Indian property ; and

(c) the amount of compensation claimed by the Government of India from China for the said loss and the amount actually paid by them ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). After the withdrawal of our Consulates-General in Lhasa and Shanghai and the trade agencies in Tibet in 1962, we have no means of obtaining accurate and precise information regarding the number of incidents and the damage to Indian property in China outside Peking. In Peking there was one incident in June, 1967 and the damage caused to the Indian Embassy as a result of it was estimated at Rs. 18,200/-.

(c) Chinese authorities have arbitrarily taken over Government properties in Peking, Shanghai and Tibet as well as Sikh and Parsi religious institutions in Shanghai and Tientsin. The Chinese Government have however, offered to pay compensation for properties of the Government of India taken over by them in China. We have protested against the arbitrary and illegal action of the Chinese authorities and have reserved our right to take further action to safeguard our interests.

Film Finance Corporation

318. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total amount of loan given by the Film Finance Corporation to the Film Pro-

ducers since the 1st January, 1962 and the number of film producers who were given these loans;

(b) the number of applications for loan received and the total amount of loan asked for since the aforesaid date; and

(c) the total amount earned by the Corporation by way of interest since the aforesaid date as also the amount of loan yet to be recovered?

The Minister of State in the Ministry of Information, Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Loans amounting to Rs. 39,21,087 were disbursed by the Film Finance Corporation to producers of 60 films during the period 1st January, 1962 to 31st December, 1968.

(b) Two hundered and forty-two applications for loans amounting to Rs. 7,03,54,154 were received during the above period.

(c) Total interest earned by the Corporation during the above period amounted to Rs. 20,47,148 and loan including interest since inception yet to be recovered on 31st December, 1968, was Rs. 76,07,795 excluding bad debt of Rs. 12,66,089 already written off.

Circulation of Mao Publicity Literature by Chinese Embassy

319. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of propaganda books on Maoism and other publicity material relating to it circulated by the Chinese Embassy since the 18th January, 1966;

(b) whether it is a fact that the Chinese Embassy adopts different technique of propaganda from time to time in violation of the diplomatic rules; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No figures are maintained by Government of the quantum of publicity material etc. circulated by various Diplomatic Missions including the Chinese Embassy.

(b) and (c). Whenever Chinese Embassy have failed to conform to the instructions laid down for the diplomatic missions in respect of circulation of publicity material, Government have drawn their attention in an appropriate manner.

Indo-China Ambassadors' Talk

320. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that talks were held between the ambassadors of India and China in France in November and December 1968; and

(b) if so, the subject-matter of the talks?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

321. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स द्वारा जो पहला मिग इंजिन 2 जनवरी 1969 को दिया जाना था उसका निर्माण वास्तव में रूस में किया गया और फिर उसका आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोरपुट कारखाना देश में इनके निर्माण तथा उत्पादन के अपने लक्ष्य से कार्यक्रम में पीछे है ; और

(ग) इसके छोटे निर्माण एककों में कब तक पूरा उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पहले मिग इंजन को, कि जो संयोजित अवस्था में परन्तु परीक्षण किए बिना यू० एस० एस० आर० से प्राप्त किया गया था विघटित करके उसका निरीक्षण करने के पश्चात एच० ए० एल० कोरापुट डिवीजन द्वारा पुनः संयोजित करके वितरित किया गया था ।

(ख) प्रगति प्रायः शड्यूल के अनुसार है ।

(ग) 1969 के दौरान ।

पाकिस्तान द्वारा प्रचार

322. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति अयूब द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 डिवीजनों की भारतीय सेना एक सप्ताह के अन्दर पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रचार भारत के विरुद्ध इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के लोगों का ध्यान उस देश में प्रजातंत्र को फिर से लाने के लिये किये जाने वाले आन्दोलन की ओर से हटाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार विशेष उद्देश्य से किये गये प्रचार के खिलाफ सरकार ने कोई विरोध प्रकट किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के अखबारों में इस आशय के समाचार देखें हैं ।

(ख) इस प्रकार के गलत बयानों का क्या कारण हो सकता है, यह अनुमान लगाना तो हमारे लिए कठिन है, लेकिन इस तरह के प्रचार का एक कारण यह हो सकता है कि विदेशी सरकारों को प्रभावित करके पाकिस्तान के लिए उनसे ज्यादा हथियार लिए जाएं ।

(ग) जी नहीं । यह आवश्यक नहीं समझा गया कि जब कभी ऐसे आरोप लगाए जाएं तो हर बार उनके खिलाफ विरोध प्रकट किया जाए ।

यू० ए० आर० ई० 300 इंजनों के उड़ान परीक्षण

323. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 27 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2300 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० ए० आर० ई० 300 इंजनों के उड़ान परीक्षण अब तक पूरे हो चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ई-300 इंजन यू० ए० आर० सरकार द्वारा विकासित किया जा रहा है । इस प्रकार के इंजन का विकास काफी समय लेता है । ई-300 इंजनों के उड़ान परीक्षणों की पहली दो प्रावस्थाएं सम्पूर्ण हो चुकी हैं । रिहीट सिस्टम सहित उड़ान परीक्षणों की तीसरी प्रावस्था प्रगतिशील है ।

पाकिस्तानी वायुसेना में वृद्धि

324. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने अपनी वायु सेना काफी बढ़ा ली है ;

(ख) यदि हां तो उसकी अनुमानित शक्ति तथा स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका सामना करने की दृष्टि से भारतीय वायु सेना को भी बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां । पाकिस्तान ने अपने लड़ाका विमानों की संख्या लगभग, दुगनी कर ली है ।

(ख) सरकार को पाकिस्तान की तैयारी का ध्यान है, वह भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिये उपयुक्त पग उठाती रही है ।

Migration of Jews from Arab Countries

325. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **External Affairs** be plased to state :

(a) whether Israel had proposed to India to act as a mediator in securing migration of all jews living at present in Arab countries ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र 'स्टेट्समैन' की बिक्री

326. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'स्टेट्समैन' नामक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र की बिक्री हाल ही में घट गयी है ;

(ख) यदि हां तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या इसकी बिक्री में हुई कमी को दृष्टिगत रखते हुए इस समाचारपत्र के लिए नियत अखबारी कागज के कोटे में भी उसी अनुपात में कमी की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). पत्र की प्रचार संख्या के बारे में सूचना समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक विवरण प्राप्त होने पर उपलब्ध होगी। विवरण भेजने की अन्तिम तारीख 28 फरवरी, 1969 है।

(ग) तथा (घ). अभी प्रश्न नहीं उठता। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि नियमों तथा सरकार द्वारा जारी आम नोटिस में बताई गई शर्तों के अनुसार किसी पत्र को अखबारी कागज का आवंटन किये जाने पर यदि पत्र द्वारा उसका किसी वर्ष में पूरा उपयोग नहीं किया जाता तो बचे हुए अखबारी कागज को उसके अगले वर्ष के कोटे में संमजित कर दिया जाता है।

आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के एक भाग का स्थानान्तरण

327. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की नागरिकों की समन्वय समिति ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हाल ही में भेजे गये अपने ज्ञापन में यह अनुरोध किया है कि वह आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के एक भाग को कलकत्ता से कानपुर को स्थानान्तरित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या कहा गया है ; और

(ग) इस ज्ञापन पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) स्मरणपत्र में ऐसा कहा गया है कि आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रियों के दल को डारेक्टोरेट जनरल आफ आर्डनेंस फैक्ट्रीज के मुख्य कार्यालय से अलग करने में न तो सरकार को कोई लाभ होगा न देश को ही। पश्चिम बंगाल की वर्तमान वित्तीय और सामाजिक स्थितियों को

देखते हुए कार्यालय को अन्यत्र ले जाना बुद्धिमत्ता न होगी। इसलिए इस बात पर बल दिया गया है कि कार्यालय को कानपुर ले जाने का निर्णय रद्द कर दिया जाए, अन्यथा उसके विरुद्ध हलचल पैदा की जाएगी।

(ग) कार्यालय को कानपुर ले जाने का निर्णय सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार करने के पश्चात और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक जनकल्याण को सामने रखते हुए किया गया था। ऐसा भी महसूस किया जाता है कि कार्यालय के एक छोटे से अंश को वहां से स्थानान्तरित करने से पश्चिमी बंगाल राज्य की आर्थिक स्थिति पर या उस राज्य में रहने वालों के रोजगार संबंधी अवसरों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इन परिस्थितियों में निर्णय किया गया है कि सावधानी से विचार करने के पश्चात लिए गए पहले निर्णय को बहाल रखा जाए।

बलिया तथा देवरिया जिलों में प्रति व्यक्ति आय

328. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बलिया तथा देवरिया जिलों में 1960, 1967 तथा 1968 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ; और

(ख) 1960 तथा 1968 में राष्ट्रीय आय की तुलना में यह आय कितनी है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). प्रत्येक राज्य के सांख्यिकीय ब्यूरो समूचे राज्य के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्राक्कलन तैयार करते हैं और जिलेवार आंकड़े नहीं तैयार किये जाते हैं। अतएव उल्लिखित दो जिलों की प्रति व्यक्ति आय की राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से तुलना करना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

329. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को कृषि योग्य भूमि देकर उत्तर प्रदेश में उनके पुनर्वास की कोई योजना है और यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) भूमि के आवंटन के लिए भूतपूर्व सैनिकों से राज्य सरकार को कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) उनमें से कितने आवेदनकर्ता 15 अगस्त, 1947 से पहले ही सेवा निवृत्त हो गये थे;

(घ) चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमणों में घायल हुए सैनिकों से तथा इन आक्रमणों में मारे गये सैनिकों के आश्रितों से अलग-अलग कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ङ) इस बीच कितने आवेदनकर्ताओं को भूमि दी जा चुकी है तथा कितने आवेदनकर्ताओं को भूमि नहीं दी गई है तथा इन लोगों को कब तक भूमि दे दी जायेगी ; और

(च) इन मामलों में वर्ग-वार क्या प्राथमिकता नियत की गई है तथा उनमें भूमि का वितरण किस अनुपात से किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (च). सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है, और जभी प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

निजामापटनम में गश्ती जहाज का धँस जाना

331. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 मई, 1968 को अथवा इसके लगभग निजामापटनम में नौसेना का एक गश्ती जहाज फँस गया था ;

(ख) क्या इसे निकाल लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जहाज कितने मूल्य का था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आई० एन० एस० सुकन्या जिसके लिये रख रखाव और नाविक व्यवस्था नौसेना द्वारा की जाती है और जो एकसाईज और कस्टम्ज के केन्द्रीय बोर्ड के लिए चलाया जा रहा एक कस्टम्ज पोत है, 13-5-1968 को निजामापतनम के पास धरती में धँस गया था ।

(ख) इसके धँस जाने के शीघ्र ही पश्चात पोत को साल्वेज करने का हर प्रयास किया गया, परन्तु निरन्तर खराब मौसम, तूफान पर आए समुद्र भारी लहरों और अप्राप्यता के कारण संक्रियाओं में भारी रुकावट आई, इसलिए उसे साल्वेज करने की सक्रियाएं निलम्बित कर देना पड़ीं । वर्षा ऋतु के पश्चात पता चला कि पोत पूर्णत: रेत में दब गया है, और इस संवर्धन ने पोत को साल्वेज करने के अवसरों पर बहुत बुरा असर डाला है ।

(ग) जब पोत धरती में धँसा था उसकी लागत लगभग 13 लाख रुपये थी । तब से पोत पर से चल सामानों समेत सभी चल मदें निकाली गई हैं ।

नये ट्रांसमीटर

332. **श्री सीताराम केसरी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में और अधिक ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो जिन केन्द्रों में और ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) नये ट्रांसमीटरों को लगाने पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी, हां । वर्तमान ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त पणजी, जोधपुर, शिमला, कलकत्ता तथा राजकोट में और ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है ।

(ग) लगभग 634 लाख रुपये ।

टेलीविजन सेट

333. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों में भारत की टेलीविजन सेटों संबंधी आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या अन्य देशों से टेलीविजन सेटों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अगले 5 वर्षों के दौरान टेलीविजन सेटों की आवश्यकता का निर्धारण देश में अधिक टेलीविजन स्टेशन स्थापित किये जाने की प्रगति पर आधारित होगा ।

(ख) तथा (ग). टेलीविजन सेटों का निर्माण देशीय जानकारी के आधार पर किया जा रहा है, और इसलिए अन्य देशों से सेट आयात करने का विचार नहीं है ।

Smuggling by Foreign Embassy Staff

334. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees of foreign embassies arrested while indulging in smuggling during the last year ; and

(b) the efforts being made to check such smuggling ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). The information is being collected.

Knowledge of Commerce and Trade for Ambassador

335. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the knowledge of commerce and trade is essential for appointment as ambassadors abroad in accordance with Prime Minister's orders and whether those orders are being complied with ;

(b) the date since which these orders have been enforced ;

(c) whether arrangements have been made for some training course for this purpose ; and

(d) the reasons which necessitated the issue of such orders ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) . Government consider that, among other things, knowledge of commercial and economic matters is essential for Heads of Indian Missions abroad. Heads of Missions are briefed in the Ministries of External Affairs and concerned Economic Ministries on commercial and economic matters and on the broad lines of our economic policy objectives. At the instance of the Prime Minister, instructions were issued on 23.3.1968 reiterating that all Heads of Missions should take a keen and personal interest in the development of India's economic relations with foreign countries.

भारत तिब्बत सीमा के साथ-साथ चीनियों के सैनिक प्रतिष्ठान

336. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री क० लकप्पा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत तिब्बत सीमा के साथ-साथ चीनियों द्वारा सैनिक प्रतिष्ठान स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश के हितों की रक्षा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अपने भूक्षेत्र पर किसी प्रकार के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी संक्रियात्मक योजनाओं से संगत उपयुक्त गोलीबारूद और सुविधाओं सहित उचित तौर पर सुसज्जित सेनाएं अपनी तरफ नियुक्त की गई हैं ।

केनिया निवासी भारतीयों के सुझाव

337. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनिया की बहुत मूलक एशियाई जनता का एक प्रतिनिधि मंडल श्री संघू की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1968 में भारत आया था तथा उसने केनिया सरकार के हाल ही के निर्णय से तथा उनके व्यापार लाइसेंसों को रद्द किये जाने के कारण प्रभावित हुए केनिया में बसे भारतीयों की कठिनाइयों को कम करने के लिये कुछ सुझाव सरकार को दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो केनिया में उत्पन्न हो रही इस नई स्थिति को देखते हुए उन सुझावों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां। कीनिया में रहने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल डा० मांदू के नेतृत्व में नवम्बर 1967 में भारत आया था और उसने भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था। इस प्रतिनिधि मंडल ने यह सुझाव दिया था कि (i) कीनिया में रहने वाले ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतमूलक लोगों पर जो बीजा व्यवस्था लागू होती है वह खतम होनी चाहिए और (ii) जो लोग भारत ब्रिटिश करार के अन्तर्गत नहीं भी आते उन्हें भी स्थायी रूप से बसने के लिए भारत आने की इजाजत दी जानी चाहिए। विचार विनिमय के बाद यह प्रतिनिधिमंडल इस बात से संतुष्ट हो गया कि बीजा व्यवस्था जारी रहना आवश्यक है। बहरहाल, भारत सरकार ने इस प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह भारत में फिर से बसने के लिए उन व्यक्तियों के मामलों पर सहानुभूति पूर्ण विचार करेगी, जिन पर मौजूदा भारत-ब्रिटिश करार लागू नहीं होता।

अवाडी में टैंक निर्माण कारखाना

338. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवाडी का टैंक निर्माण कारखाना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है ; और

(ख) निम्नलिखित कामों के संबंध में निर्धारित तिथियां तथा काम पूरा होने की वास्तविक तिथियां क्या हैं :—

(एक) प्रथम चरण की पूर्णता ;

(दो) सम्पूर्ण कारखाना तैयार होना ;

(तीन) पहले टैंक का पूर्ण निर्माण ;

(चार) पूरी क्षमता से निर्माण आरम्भ होना ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) (1) फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय 1961 में किया गया था, और पहली प्रावस्था 1963 में सम्पूर्ण हो गई थी, कि जब फैक्टरी के टूलरूम को कमीशन किया गया था।

(2) असैनिक कार्यों का निर्माण, जो जून 1962 में शुरू हुआ था, प्रावस्थाओं में दिसम्बर, 1962 तक सम्पूर्ण हो गया था।

(3) जैसे कि आशा थी पहला टैंक 1965 वर्ष के अन्त तक निकाला गया था।

(4) प्राप्त हुए अनुभव को सामने रखते हुए, अधिकाधिक उत्पादन उपलब्ध करने के उद्देश्य से, फैक्टरी का उत्पादन कार्यक्रम निरन्तर पुनरीक्षण अधीन रहता है। अब तक की निष्पतिएं सन्तोषजनक रही हैं।

पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक-अड्डा

339. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान स्थित अमरीकी वायु-सेना का अड्डा बन्द हो चुका है; और

(ख) इस बारे में भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तान में संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत ने नवम्बर, 1968 के एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पेशावर के पास से अमरीकी वायु-सैनिक अड्डे को हटाने का कार्य जनवरी, 1969 से शुरू हो जायेगा और 17 जुलाई, 1969 तक पूरा हो जायेगा ।

War Material Captured by Pakistan During Indo-Pak Conflict

341. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the extent of India's war-material yet to be returned by Pakistan which was captured by her during the last Indo-Pakistan conflict ;

(b) the efforts made by Government so far to recover the same ;

(c) the extent of such material yet to be returned by India to Pakistan ; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) According to the universally accepted practice, war materials such as weapons, tanks etc. captured by either side during operations are not returned.

(b) to (d) . Do not arise.

Arms Supply to Pakistan

342. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the countries, apart from Soviet Union and United States, from whom Pakistan is getting or is likely to get arms supplies ;

(b) the steps taken by Government to lodge protests with these countries ; and

(c) the nature of replies received from them ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Pakistan has been acquiring arms from various other countries, especially China.

(b) and (c). The views of the Government of India on the question of arms supplies to Pakistan are well known and have been made amply clear to all friendly countries.

सशस्त्र सेनाओं के राशन में कटौती

343. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के राशन में कटौती किये जाने के क्या कारण हैं और कितने प्रतिशत

कटौती की गई है; और

(ख) कम राशन कब से दिया जा रहा है और पूरा राशन कब दिया जाने लगेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. सैनिकों को आटे का राशन फील्ड क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 680 ग्राम है और शान्ति स्थानों में 600 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन । 21 फरवरी, 1966 से उच्च स्थानों पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर फील्ड क्षेत्र के सैनिकों के आटा राशन में सेना मुख्यालयों द्वारा 60 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की परीक्षणात्मक स्वैच्छिक कटौती की गई थी । ऐसा देश में उस समय अन्न स्थिति की कठिनाई को समक्ष रखते हुये स्वैच्छिक तौर पर किया गया था । यह कटौती अभी तक जारी है और इसे जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष सेना मुख्यालयों द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है । इसका सैनिकों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा । न ही सैनिकों से इसके प्रति कोई उल्टा प्रतिकार ही हुआ है ।

2. 1 सितम्बर, 1968 से यथासम्भव अधिकाधिक अन्तर भेद दूर करने के विचार से तीनों सेवाओं के शान्तिकालीन राशन मानों में कुछ समंजन किए गए हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि संशोधित मान रक्षा सेवाओं की पौष्टिक आवश्यकताओं को जुटाने के लिए काफी है, और वह उनकी क्षमता को किसी प्रकार कुप्रभावित नहीं करते । संशोधित मान चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह मन्त्रण से बनाए गए हैं ।

3. 1968 के दौरान सैनिकों के फील्ड राशन मान में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं । किए गए अध्ययनों से पता चला कि दाल का अधिकृत राशन आवश्यकता से अधिक था और उसकी पूरी राशि प्रायः इस्तेमाल नहीं की जाती थी । दूसरी और चीनी का राशन कम पाया गया था । इसलिए दाल का राशन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए 130 ग्राम से घटाकर 90 ग्राम कर दिया गया था और चीनी का राशन बढ़ाकर 60 ग्राम से 90 ग्राम ।

4. चूंकि चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह से मानों में उन्हें युक्तिसंगत बनाने और पौष्टिक आवश्यकताओं का सामना करने के विचार से, परिवर्तन-समंजन किए गए हैं, पहले के मानों को फिर से अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तदपि, स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और आवश्यक समझी गई तबदीलियां कर दी जाती हैं ।

अन्तरिक्ष सम्बन्धी समझौता

345. **श्री शिव चन्द्र झा :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्तरिक्ष समझौते के सम्बन्ध में किसी

प्रस्ताव का प्रायोजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा अन्य राष्ट्रों की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जेनेवा में, जून, 1968 में संयुक्त राष्ट्र को वाह्य अन्तरिक्ष विधि उपसमिति के सातवें अधिवेशन में भारत सरकार ने वाह्य अन्तरिक्ष में यान छोड़ने से होने वाली क्षति की जिम्मेवारी के बारे में एक करार का मसौदा पेश किया था । भारत के इस प्रस्ताव पर इस विधि उपसमिति के दूसरे सदस्यों की प्रतिक्रिया बहुत सहानुभूतिपूर्ण थी ।

हमारे विदेशस्थ मिशनों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों की सहायता

346. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्य कर रहे हमारे मिशन उन भारतीय राष्ट्रजनों की सूची रखते हैं जो कि उन मिशनों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले देश में रहते हैं;

(ख) भारतीय मिशनों द्वारा स्वप्रेरणा से भारतीय राष्ट्रजनों को उनके आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के सम्बन्ध में की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप क्या है; और

(ग) अगर उनकी कोई सेवाएं नहीं की जातीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां, विदेशों में भारतीय मिशन/पोस्ट अपने-अपने प्रत्यायन के देशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की पंजी रखते हैं ।

(ख) और (ग). विदेश में, भारतीय राष्ट्रिकों की समस्याएं, एक दूसरे देश से भिन्न हैं, और जहां तक व्यवहार्य है उनके आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में प्रत्येक सम्भव सहायता दी जाती है ।

श्रम तथा पूंजी की अप्रयुक्तता

348. **श्री लोबो प्रभु : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने श्रम तथा पूंजी की अप्रयुक्तता को हमारी उत्पादन लागत में वृद्धि का कारण माना है जो कि कम मजदूरी होने के बावजूद विश्व भर में सबसे अधिक है;

(ख) क्या योजना आयोग ने भूमि, श्रम, पूंजी और ऋण की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग उठाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). चौथी योजना के विकास कार्य-क्रमों को तैयार करते समय ध्यान रखा जा रहा है कि मानवीय और भौतिक साधनों का अधिक पूर्ण उपयोग किया जाये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के दूसरे कारखाने का स्थान

349. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनीताल और बंगलौर में भारत इलेक्ट्रानिक्स का दूसरा कारखाना स्थापित करने में कितना-कितना धन व्यय होने का अनुमान है;

(ख) प्रतिरक्षा की दृष्टि से बंगलौर की उत्तम स्थिति को देखते हुए उसको समुचित महत्व न दिये जाने के क्या कारण हैं, जबकि देश की विद्रोहात्मक सीमाएं केवल उत्तर में ही हैं;

(ग) नैनीताल में रेलवे लाइन न होने के कारण उत्पादन लागत कितनी अधिक हो जायेगी; और

(घ) नैनीताल में ऐसी कौन-सी सुविधाएं हैं जो बंगलौर में उपलब्ध नहीं हैं, और क्या नैनीताल पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण औद्योगिक उत्पादन के योग्य नहीं है, जिसके लिए बहुत-सी सहायक सुविधाओं की आवश्यकता होती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). प्रश्न इस कल्पना पर आधारित है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की दूसरी यूनिट नैनीताल में स्थापित करना प्रस्तावित है । परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यापारियों का दमन

350. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यापारियों और अन्य लोगों के दमन के सम्बन्ध में समाचार मिले हैं, उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या दमन के कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया गया है, ताकि स्थानीय न्यायालय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामले को ले जा सके; और

(ग) क्या श्रीलंका के साथ किये गये समझौते के समान समझौता करने का प्रस्ताव इन देशों को पेश किया गया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). इन कार्रवाइयों का जिन लोगों पर असर पड़ा है या जिन पर पड़ने की सम्भावना है वे प्रायः सभी एशियाई मूल के ब्रिटिश नागरिक

हैं। इस तरह उनके हितों की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम की सरकार पर है।

चूंकि प्रभावित व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक हैं, अतः इन राष्ट्रों के साथ उस तरह का समझौता करने का प्रश्न नहीं उठता जैसा कि श्रीलंका के साथ किया गया है।

नई काचार सड़क

351. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1968 से सीमा सड़क संस्था द्वारा निर्माण-कार्य अपने हाथ में लिए जाने के बाद से, नई काचार सड़क के निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि क्या है; और

(ग) उपरोक्त कार्य पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मार्ग रेखा के दोनों ओर से टोह और सर्वेक्षण सम्पूर्ति की प्रावस्थाओं में है। 204 किलोमीटर और 237 किलोमीटर के बीच की सड़क का सुधार दिसम्बर 1968 में शुरू किया गया था और निर्माण-कार्य प्रगतिशील हैं।

(ख) सभी मौसमों के लिए एक 3-टन सड़क अस्थायी पुलों समेत मार्च, 1971 तक सम्पूर्ण करने की योजना है।

(ग) अगर आवश्यक संख्या में असैनिक श्रम प्राप्य हो जाए तो निर्धारित किया गया है कि सभी मौसमों के लिए 3-टन सड़क की अस्थायी पुलों समेत कुल लागत लगभग 720 लाख रुपये होगी। 45 लाख की एक राशि 1968-69 में व्यय होना प्रत्याशित है, और शेष चतुर्थ योजना अवधि के दौरान।

Election Broadcasts

352. **Shri Ram Avtar Shastri** : **Kumari Kamla Kumari** :
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Narain Swarup Sharma** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri D. N. Patodia** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government had held talks with the representatives of recognised political parties in regard to carrying on the election propaganda work over A. I. R. by them during the Mid-term Elections ;

(b) if so, the conclusions arrived at ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No proposal in the matter was received from any of the political parties.

पाकिस्तान के साथ पुनः व्यापार आदि आरम्भ करना

356. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः व्यापार आरम्भ करने, असैनिक विमान सेवाओं को चलाने तथा एयरलाइन्स सीमा चौकियों को खोलने और 1965 के संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के सामने बार-बार ये प्रस्ताव रखे हैं कि दोनों देशों के बीच सिविल वायुयान की उड़ाने और व्यापार का काम दोबारा शुरू हों, सभी पड़ताल चौकियां खोल दी जाएं और 1965 के युद्ध के समय और उसके बाद जिन सम्पत्तियों या आस्तियों को एक-दूसरे देश ने जब्त किया है, उनकी वापसी के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जाये जैसी कि ताशकन्द घोषणा में व्यवस्था है, जिस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किये हैं। अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से इनमें से किसी भी प्रस्ताव का उत्तर नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Criticism of Indian Ministers by Radio Moscow

357. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various political parties, their leaders as also some Central Ministers were criticised over Radio Moscow in December, 1968, and January and February, 1969 ;

(b) whether such criticism tantamounts to interference into the internal affairs of India ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

Indian Nationals in Pakistan Jail

358. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri R. K. Sinha:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the daily 'Hindustan' dated the 31st January, 1969 to the effect that about 250 Indian nationals are detained in the camp jail in Lahore; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and measure taken to secure their release?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) and (b). Yes, Sir. According to information available with the Government, at the end of 1968, there were 213 internees in the Lahore Internment Camp awaiting repatriation to India. Out of these, about 45 are being repatriated this month and 60 persons are either deaf and dumb or demented and Government is finding difficulty in verifying their national status. Their photographs along with whatever personal particulars could be gathered have been circulated to the State Governments concerned. The Lahore Internment Camp is being visited periodically by officers of our High Commission in Pakistan, who obtain particulars of the new internees added to the camp. These particulars are immediately sent to the State Governments concerned for verification of their national status and the persons are repatriated as soon as their Indian nationality is established.

टेलीविजन सेटों का निर्माण

359. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णतया भारतीय तकनीकी ज्ञान तथा पुर्जों से टेलीविजन सेट बनाना संभव हो सका है;

(ख) यदि हां, तो वे सेट किस कम्पनी ने बनाए हैं और उनकी क्या विशेषता है तथा उन पर कितनी लागत आई है; और

(ग) निर्माण कारखाने इस समय कितने टेलीविजन सेट बना रहे हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सेंट्रल इलेक्ट्रानिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट (सी० ई० ई० आर० आई०) पिलानी ने टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए देशीय जानकारी का विकास किया है। प्रति सेट के लिए आयात संघटकों का मूल्य लगभग 250 रुपये है।

(ख) तथा (ग). सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी पर आधारित बड़े पैमाने के क्षेत्र की दो फर्मों को प्रतिवर्ष दस-दस हजार टी० वी० सेट निर्माण करने के लिए लाइसेन्स दे दिए गए हैं और छोटे पैमाने की फर्मों को दो कान्जर्टिय प्रति वर्ष 5000 टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए क्षमता स्थापित कर रही हैं।

बड़े पैमाने की दोनों यूनिटों में से एक ने उत्पादन शुरू कर दिया है, और उनके सेट बाजार में आ चुके हैं। 23 इंच के पर्दे के सेट की उन्होंने 1,900 रुपये लागत घोषित की है। दूसरी फर्मों की भी चालू वर्ष में उत्पादन शुरू कर देने की संभाव्यता है।

सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी भी पाइलाट संयंत्र के तौर पर 1000 टी० वी० सेटों का निर्माण कर रही है। उनके 23 इंच और 19 इंच नाले पर्दों के सेटों की क्रमशः लागत 1500 रुपये और 1,350 रुपये है।

Meeting Called by Governor of Bihar to Draft Fourth Plan for the State

360. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether is it a fact that the Governor of Bihar called a joint meeting of the Members of parliament from Bihar and the Members of Legislative council in Patna on the 18th January last to consider the draft Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the number of Members and the names of other persons who attended the meeting ;

(c) whether it is also a fact that immediately after the commencement of the meeting, most of the Members boycotted the meeting and staged a walkout ; and

(d) if so, the names of the persons who boycotted and the reasons of boycott ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). Information is awaited from the State Government.

11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4196 के उत्तर में शुद्धि

Correction of the Answer to the Unstarred Question No. 4196 dated 11 December, 1968

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4196 के भाग (ख) के उत्तर में यह कहा गया था कि 'चारुलता', 'साते पकै बान्धा', 'मझली दीदी', तथा 'पंचेस्वर' फिल्मों को फिल्म वित्त निगम, बम्बई ने ऋण दिया था। फिल्म वित्त निगम, बम्बई ने हिन्दी फिल्म 'देवर' को भी ऋण दिया था। सदन को जो असुविधा हुई है, उसका खेद है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मास्को "पीस एण्ड प्रोग्रेस" रेडियो द्वारा भारत के कुछ राजनीतिक दलों के विरुद्ध प्रचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I draw the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Propaganda by Radio 'Peace and Progress' against certain political parties in India, amounting to interference in the internal affairs of the country."

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में स्थित 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रैस' ने अपने प्रसारणों में समय-समय पर भारतीय राजनीतिक दलों और व्यक्तियों की आलोचना की है। भारत सरकार ने 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रैस' की इस प्रकार की बातों की ओर सोवियत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सोवियत सरकार का कहना यह है कि यह रेडियो स्टेशन सरकारी संस्था नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र संगठन है। उन्होंने भारत में प्रकाशित ऐसे बहुत से वक्तव्यों और प्रकाशनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिनमें सोवियत नेताओं और सोवियत नीतियों की आलोचना की गई है; उन्होंने यह भी कहा है कि उनका सरकारी रेडियो स्टेशन और अखबार हमारी सरकार की आलोचना नहीं करते और न ही कोई ऐसी बात कहते हैं जिस पर सरकार को कोई आपत्ति हो।

सरकार ने यह देखा है कि भारत की आलोचना में 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रैस' भारतीय समाचारपत्रों के उद्धरणों का काफी प्रयोग करते हैं।

हाल ही के चुनावों के दौरान 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रैस' के कुछ आलोचनात्मक प्रसारणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस मामले की ओर सोवियत प्राधिकारियों का ध्यान फिर आकर्षित किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Do the Government agree with the contention of the Soviet Government that the Radio Peace and Progress is an independent institution and is not under their control ? Everybody familiar with the Soviet system of Government knows that everything there is controlled by the Government. Are the Government of India ignorant of this fact and if not, why they have not sent any letter of protest to them instead of only inviting their attention towards this matter ?

We have friendship with Russia and are eager to strengthen that friendship further. But we cannot tolerate their interference in our internal affairs. If the Government do not protest against this interference, they will be proving themselves a henchman of Russia.

In their pre-mid-term election broadcasts the Radio Peace and Progress has not only criticised the Jana Sangh but also the Congress President. On previous occasions they criticised Shri S. K. Patil and Shri Morarji Desai also. This is known to everybody. They have charged the Jana Sangh and the Congress President with reversing the foreign policy of India.

Why do the Government not protest against this interference in our internal affairs and tell them that this will harm our relations with them ?

Secondly, have these broadcasts come to the notice of the Government of India ?

Shri Dinesh Singh : I agree with him that a country should not interfere in the internal affairs of another country. But so far as expression of views is concerned, it is a different matter; though they may not be to our liking. In such matters, we have to act within a certain frame work. When the Soviet Government say that they have no control on a certain institution, how can we tell them : No ; you have control over them ?

श्री रंगा (श्री काकुलम) : क्या वहां पर ऐसे समाचारपत्र हैं जो अपनी सरकार की आलोचना करते हैं जैसा कि हमारे यहां है ?

श्री दिनेश सिंह : हम रूसी शासन पद्धति या भारतीय शासन पद्धति पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम एक सरकार के वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या सरकार चीन के इस कथन को भी स्वीकार करती है कि उन्होंने अपने क्षेत्र पर कब्जा किया है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्यों के विचार अच्छी तरह व्यक्त किये जा चुके हैं और प्रत्येक का उस ओर ध्यान जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question has been evaded. I am not ready to accept that the Soviet Government have not control over the Radio Peace and Progress. But what has the Hon. Minister to say about the Moscow Radio broadcast ? We cannot tolerate other Governments abusing us.

श्री दिनेश सिंह : यह प्रस्ताव 'शांति तथा प्रगति रेडियो, के बारे में है और मैंने उस सन्दर्भ में उत्तर दिया है। जहां तक मास्को रेडियो का सम्बन्ध है रूस सरकार ने कहा है कि उनका रेडियो अन्य सरकारों की आलोचना नहीं करता परन्तु वह अपने विचार व्यक्त करने के लिये स्वतंत्र है। फिर भी हमने इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है कि चुनावों के समय ऐसा नहीं किया जाना चाहिये जब कि विभिन्न दल चुनाव लड़ रहे होते हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : "शांति तथा प्रगति रेडियो" पिछले दो वर्ष से भारतीयों की भावनाओं के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। इस सभा में भी यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है।

7 दिसम्बर, 1967 को गृह-मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि "इस रेडियो प्रसारण के बारे में रूस सरकार से लिखापढ़ी की गई है और उन्होंने कहा है कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं। इसलिये मेरे लिये इस समय कोई निष्कर्ष निकालना—कि आया यह एक मित्रतापूर्ण कार्य है अथवा अमित्रतापूर्ण कार्य है—उचित नहीं होगा।"

अन्य अवसर पर 20 दिसम्बर, 1967 को भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री के० के० शाह ने कहा था :

"रूस में जो कुछ होता है क्या कोई यह कह सकता है कि उसके लिये रूस सरकार उत्तरदायी नहीं है ? संक्षेप में ठीक स्थिति यही है। रूस में विद्यमान राजनीतिक प्रणाली के अन्तर्गत वहां पर सब कुछ रूस सरकार के इशारे पर हुआ समझा जाता है।"

और अब माननीय मंत्री कह रहे हैं कि रूस भारत की भावनाओं तथा राष्ट्रीय हितों के साथ खेल सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दो वर्ष तक निरन्तर प्रयास करने के बाद सरकार इस कार्य को मित्रतापूर्ण समझती है अथवा अमित्रतापूर्ण या इसके बारे में निर्णय करने में अभी और दस वर्ष लगेंगे ? क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि वे हमारी राष्ट्रीय

भावनाओं के विरुद्ध प्रचार बन्द नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रधान मंत्री रूस के प्रधान मंत्री को निजी पत्र लिखेंगी जिसमें भारतीयों की भावना व्यक्त की गई हो और उन्हें बताया गया हो कि यदि वे इसे बन्द नहीं करेंगे तो इसे भारत के विरुद्ध एक अमित्रतापूर्ण कार्य समझा जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य के इस सुझाव के लिये मैं उनका आभारी हूं। मेरे सहयोगी श्री के० के० शाह ने जो यह कहा है कि रूस में जो कुछ होता है, उसके लिये रूस सरकार उत्तरदायी है बिल्कुल सही है, ठीक उसी तरह जैसे यहां पर जो कुछ होता है उसके लिये हम उत्तरदायी हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इस देश का शासन हमारे जिम्मे है। यह अलग बात है कि हमारी सरकार किस चीज पर नियन्त्रण रखना चाहती है और किस पर नहीं। हमारे यहां समाचारपत्रों आदि पर कोई नियंत्रण नहीं है। रूस सरकार ने कहा है कि "रेडियो शांति तथा प्रगति" पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है और उन्होंने अपने ही विचार व्यक्त किये हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री शाह ने कहा है कि वहां पर सभी कुछ रूस सरकार के इशारे पर हुआ समझा जाता है। इसलिये रूस सरकार ने ही "रेडियो शांति तथा प्रगति" स्थापित किया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार इसे अमित्रतापूर्ण कार्य समझती है और क्या प्रधान मंत्री पत्र लिखेंगी ?

श्री दिनेश सिंह : उन्होंने इसे स्थापित किया हो परन्तु वे कहते हैं कि उनका इस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखने का कोई इरादा नहीं है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

राजनयिक भाषा में किसी कार्य को अमित्रतापूर्ण कार्य समझने का एक खास अर्थ होता है। इस अवस्था में मैं यह नहीं कहूंगा कि यह एक अमित्रतापूर्ण कार्य है। हमने इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है और उन्होंने जो कुछ कहा है बता दिया है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is very sad that the Hon. Minister has tried to oversimplify the entire issue. I understand that the Hon. Minister is using such a language because of the resentment of Russia. The type of political set up that exists there, it is something impossible to talk of autonomy under such a system. Nobody can agree with it that the Russian Government have no control over the Radio Peace and Progress, especially when they have control even over radios of other countries as for example the Prague Radio.

It is not a party question but it is a question of principle. Do the Government of India want to keep their mouth shut under pressure of aid from Russia or for any other reasons ? Is this country going to be governed by Russia and America or the Government of this country ? It should be governed by the Government of this country. I have three pointed questions to ask in this connection. Do Government consider this act— whether it is the

Moscow Radio or the Radio Peace and Progress—an interference in our internal affairs ? Are Government satisfied with their explanation that they have no control over the Radio Peace and Progress and if not, do Government propose to send a letter of protest to them expressing their disapproval of these broadcasts by the Radio Peace and Progress ?

Shri Dinesh Singh : This country is governed by the Government elected by its people. I am surprised as to why the Hon. Member is trying to create misunderstanding. We are not guided by any outside agency.

So far as this act of the Radio Peace and Progress is concerned, whether it is an interference in the internal affairs of our country I want to say that this kind of propaganda waged by any country against our institutions, social and political, is something which we do not like and whenever such an occassion arose, we have taken up this matter with them. Any country is free to run its institutions in any way it likes. As we do not like any interference in the way institutions are run in our country, similarly they also do not like any interference.

So far as the question of sending a letter of protest is concerned, we have taken up this matter at a very high level and told them that such propaganda does not benefit either of the two countries. Whether the Soviet Government have control over the Radio Peace and Progress or not, without taking up this issue we want them to stop such type of propaganda.

Shri Kanwar Lal Gupta : He has not answered my questions. I wanted to know whether Government are satisfied with their explanation and whether Government considers it as an interference in our internal affairs ?

Shri Dinesh Singh : Had we been satisfied, what was the necessity of taking it up again ? So far as the question of interference is concerned, they express their views there and we do not like that.

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : The Radio Peace and Progress started this tirade against us 2-3 years back. When Russian army invaded Czechoslovakia, our leaders voiced their strong protest over those happenings. Enraged over this protest, the Radio Peace and Progress started criticising our leaders. They openly criticised persons like Shri Hem Barua, Shri C. C. Desai and Shri Manohar Lal Sondhi, MPs. At the time of the general elections of 1967 also they had criticised the policies and programmes of various political parties in India and thus interfered in our internal affairs. Congress Members should not view it from the angle of criticism of the Jana Sangh.

I want to cite some extracts in this connection. On the 17th July, 1967 the "States man" reported :

"A broadcast by Radio Peace and Progress from Tashkent stated that lawlessness in the Naxalbari area was an agrarian movement."

Similarly, in the "Hindustan Times" of 1 December, 1967 it was reported :

"Radio Peace and Progress in its latest broadcast has openly abused the Govetnment of India for dismissal of the Communist Dominated West Bengal Government."

The "Current" of 9 December 1967 reported thus :

"What is worrying Mrs. Gandhi most is not the situation in West Bengal but the Soviet reaction to it. She recently told one of her confidants that the dismissal in Bengal had caused dismay in Moscow."

For the last two years this story is being repeated. The former Minister of Information and Broadcasting Shri K. K. Shah had admitted that this was an interference in our internal affairs. In this connection we can refer to his speech in the House on 6th March, 1968.

If any foreign country criticises any Indian citizen or any Indian party it amounts to inteference in our internal affairs. So the propaganda being made by the Radio Peace and Progress is an interference in our internal affairs. The Government has argued that the Radio Peace and Progress is an autonomous corporation and as such U. S. S. R. Government has no control over it. I want to say that the U. S. S. R. Government have knowingly and purposefully made it an antonomous Corporation so that it may interfere in the internal affairs of other countries. I want to know whether India is so weak and timid that she is unable to express her protest when an interference is being made in her internal affairs. After all there is a limit to our friendly relation with Russia. If we have friendship with them, does it mean we are not going to offend them, even when they are interfering in our internal affairs ? I want to know what steps have been taken by Government in this regard. I want to know in which language, in which words and by which department protest has been expressed against that inteference.

Shri Dinesh Singh : So far as the question of language is concerned, I understand English language was used. So far as the words are concerned I do not know as to exactly which words were used by the Minister of State, but so far as their meanings are concerned I have already informed the House.

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
64वां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं शिक्षा मंत्रालय-दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के 82वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में प्राक्कलन समिति का 64वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
69वां तथा 42वां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं शिक्षा, वाणिज्य, निर्माण, आवास तथा सम्भरण (निर्माण तथा आवास विभाग) मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल), 1966-67 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 पर लोक लेखा समिति का 39वां प्रतिवेदन पेश करता

मैं परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय सम्बन्धी विनियोग लेख (सिविल), 1966-67 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 पर लोक लेखा समिति का 42वां प्रतिवेदन भी पेश करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

23वां प्रतिवेदन

श्री गु० सिं० ढिल्लो (तरनतारन) : मैं नीवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (तीसरी लोक-सभा) के 24वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 23वां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION Re : TWENTY-EIGHTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से, जो 18 फरवरी, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत हो ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से, जो 18 फरवरी, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : On a point of order, Sir, two murders have been Committed in U. P. during mid-term elections. I have given a Calling Attention Notice in this regard, which has not been admitted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं । इस समय उनका व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुना जा सकता । हम इस समय रेलवे आय-व्ययक को लेंगे । मैं उनकी बात बाद में सुनूंगा और उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है, मैं उसे गृह मंत्री अथवा सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दूंगा ।

रेलवे आय व्ययक, 1969-70
RAILWAY BUDGET, 1969-70

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं 1969-70 का रेलवे बजट पेश करने के लिए खड़ा हूं ।

एक वर्ष पहले आज के दिन 1967-68 का जो संशोधित अनुमान पेश किया गया था, उसमें आशा व्यक्त की गयी थी कि कुल संचालन व्यय पूरा कर लेने और मूल्यह्रास के लिए 95 करोड़ रुपये तथा पेंशन निधि के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर लेने के बाद 118.49 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व बचेगा जो सामान्य राजस्व को दिये जाने वाले लाभांश से 22.59 करोड़ रुपये कम होगा । इस वर्ष के लेखे जब बन्द किये गये, तब शुद्ध राजस्व घटकर 110 करोड़ रुपये रह गया । संचालन-व्यय तथा विविध-व्यय दोनों में कमी के बावजूद स्थिति में यह गिरावट मुख्य रूप से यातायात से होने वाली प्राप्तियों में कुछ कमी के कारण हुई । सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला लाभांश 45 लाख रुपये बढ़ गया था । शुद्ध राजस्व और देय लाभांश के बीच 31.53 करोड़ रुपये का अन्तर था, जो राजस्व आरक्षित निधि से पूरा किया गया ।

2. मुझे सदन को यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि चालू वर्ष में स्थिति कुछ बेहतर है । विगत दो वर्षों में औद्योगिक उत्पादन प्रायः गतिहीन रहा । लेकिन 1968 से इसमें कुछ सक्रियता दिखाई पड़ रही है । 1967 की अपेक्षा 1968 के पहले आठ महीनों में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचक अंक (आधार 1960=100) की औसत में 5.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है । जून, 1968 में जो फसली वर्ष समाप्त हुआ, उसमें अनाज, तेलहन और दूसरी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । फलस्वरूप रेल परिवहन की जो मांग बढ़ी, उससे अर्थ व्यवस्था में सुधार परिलक्षित होता है और चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 55 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त राजस्व उपार्जक माल ढोया गया है और आशा है कि इस वर्ष राजस्व उपार्जक यातायात 1705 लाख मीटरिक टन होगा, अर्थात् इसमें 70 लाख मीटरिक टन नहीं, जैसा कि बजट में अनुमान लगाया गया था, बल्कि 80 लाख मीटरिक टन से कुछ अधिक वृद्धि होगी । कोयले की भाड़ा-दर को तर्क संगत बनाने के लिए पिछले नवम्बर से उसमें जो समंजन किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में माल यातायात की आमदनी बजट अनुमान के 545 करोड़ रुपये से 21 करोड़ रुपये अधिक होने की आशा है । यह सन्तोष की बात है कि यद्यपि वर्ष के दौरान बहुत से कारणों से कई क्षेत्रों में परिचालन के काम में बाधा पड़ी, फिर भी रेलें कुल अतिरिक्त यातायात ढोने में सफल रही हैं । बाढ़ के कारण कई स्थानों में रेल-संचार, असामान्य रूप से, लम्बे अर्से तक अवरुद्ध रहा—राजस्थान में जुलाई में तीन हफ्ते, पश्चिम रेलवे के बलसाड़-बड़ौदा खण्ड पर अगस्त में चार हफ्ते, आसाम को जाने वाली मीटर लाइन पर अक्टूबर में लगभग

एक महीने और बड़ी लाइन पर तीन महीने से अधिक और दक्षिण-पूर्व रेलवे के पूर्वी समुद्र की लाइन के एक टुकड़े पर यातायात पूर्ण रूप से रुका रहा और लाइन की मरम्मत करने में लगभग चार महीने लग गये। इसके अलावा कुछ अन्य कठिनाइयां भी सामने आयीं, जैसे जुलाई में दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों के फायरमैनों की हड़ताल और सितम्बर में पूर्व रेलवे के कुछ रनिंग कर्मचारियों ने धीमी गति से काम करने का रवैया अपनाया। मैं इन घटनाओं के ब्योरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में परिवहन की एक विशेष कठिनाई का उल्लेख करना चाहूंगा। पंजाब और हरियाणा में रबी की पिछली फसल बहुत ही अच्छी थी और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में रेलों से अनाज ढोने के लिए कहा गया। मई से जुलाई तक तीन महीनों में पंजाब और हरियाणा से देश के विभिन्न भागों में 17 लाख मीटरिक टन गेहूं रेल से भेजा गया, जो एक बहुत बड़ी सफलता है। पंजाब और हरियाणा से गेहूं की ढुलाई और पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व रेलों में लाइनों में टूट-फूट के कारण वर्ष के पहले छः महीनों में कोयले की ढुलाई में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं। लेकिन यहां भी विशेष प्रयास करके रेलों ने इस वर्ष दिसम्बर तक, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, लगभग 6 प्रतिशत अधिक कोयला ढोया। माल की ढुलाई में जो तेजी लायी गयी है, उसे इस पूरे व्यस्त मौसम में कायम रखा जायेगा और निस्सन्देह अगले वर्ष और बाद के वर्षों में, चौथी पंचवर्षीय योजना की गति में वृद्धि के साथ-साथ, रेलें अपने तथा देश की समग्र अर्थ व्यवस्था के हित में, इससे भी अधिक माल ढोयेंगी।

3. जहां माल यातायात में रेलों ने इस वर्ष अच्छा काम किया है, वहां यात्री यातायात निराशाजनक रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के चार महीनों में यातायात गिर गया है। ऐसा जान पड़ता है कि बरसात कुछ पहले शुरू हो जाने और बाढ़ तथा लाइन में टूट-फूट के कारण, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, यातायात में यह गिरावट आयी है। उपनगरीय यातायात में एक ओर की यात्रा के टिकट लेने के बदले सीजन टिकट लेने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। प्रकटतः इसका कारण यह है कि वर्ष के शुरू में किराये में जो वृद्धि हुई, वह एक ओर की यात्रा के किराये की तुलना में सीजन टिकटों में बहुत कम थी। इसके अलावा सम्भवतः कम दूरी वाला कुछ यातायात रेल से न होकर सड़क से होने लगा है, क्योंकि हमने रेल का न्यूनतम किराया 15 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे कर दिया है। मैं स्पष्टतः कहना चाहता हूं कि इन बातों का मुझे कोई दुःख नहीं है क्योंकि सीजन टिकटों का अनुपात बढ़ जाने से टिकट खिड़कियों पर काम का भार कुछ कम हो जाता है और कम दूरी वाला यातायात सड़क के रास्ते होने से रेल गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने में सहायता मिलती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम दूरी वाले यातायात के लिए जो किराया लिया जाता है उससे पूरी लागत नहीं निकलती। अगस्त से यात्री यातायात में क्रमिक वृद्धि के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की आशा

नहीं है कि चालू वर्ष में यात्री यातायात बजट अनुमान के स्तर तक पहुंच सकेगा जो 278 करोड़ रुपये है। इसका संशोधित अनुमान 12 करोड़ रुपये कम, अर्थात् 266 करोड़ रुपये रखा गया है। चालू वर्ष में यातायात से कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 902·15 करोड़ रुपये रखा गया है, जो बजट अनुमान से 9.65 करोड़ रुपये अधिक है।

4. साधारण संचालन-व्यय में लगभग 26 करोड़ रुपये की वृद्धि है। अधिकांश वृद्धि कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। कर्मचारियों के खर्च में वृद्धि उन कारणों से हुई है : पिछली बार सितम्बर, 1968 से मंहगाई भत्ते में संशोधन के कारण 6.91 करोड़ रुपये, 1 मार्च 1968 से यात्रा और रनिंग भत्तों की संशोधित दरों के कारण 3.92 करोड़ रुपये और दिसम्बर, 1968 से मंहगाई भत्ते के एक अंश को वेतन में मिला दिये जाने के कारण 4.92 करोड़ रुपये। कुल मिलाकर ये वृद्धियां 15.75 करोड़ रुपये आती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम खर्च में कुछ किफायत कर सके हैं और इस तरह कर्मचारियों पर होने वाले खर्चे में शुद्ध वृद्धि 11.25 करोड़ रुपये आती है। साधारण संचालन-व्यय में वृद्धियों का और अधिक ब्योरा देकर मैं माननीय सदस्यों को थकाना नहीं चाहता। मैं केवल कुछ ही मदों की चर्चा करना चाहता हूं जहां खर्च में वृद्धि अधिक हुई है : मरम्मत और अनुरक्षण पर 6.09 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जिसमें 3·29 करोड़ रुपये बाढ़ से होने वाली क्षति की मरम्मत के हैं। डाक और तार विभाग की दूर-संचार सुविधाओं के भाड़े में 1.50 करोड़ रुपये की वृद्धि है, जिसमें कुछ अतिरिक्त बकाया भुगतान भी शामिल है। मुख्यतः कोयले की कीमतों, डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क और बिजली की दरों में वृद्धि के कारण ईंधन का खर्च 4.79 करोड़ रुपये बढ़ गया है। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि साधारण संचार-व्यय में कुल वृद्धि बजट के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण है, जिन पर रेलवे का कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तव में इन वृद्धियों का कुल योग साधारण संचालन-व्यय के संशोधित अनुमान में वास्तविक वृद्धि से कहीं अधिक है और मुझे सदन को यह बताने में प्रसन्नता है कि खर्च में किफायत करने के लिए रेलों ने जो प्रयास किये हैं, उनका कुछ वांछित प्रभाव प्रकट होने लगा है। 1967–68 में कर्मचारियों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है और मैं आशा करता हूं कि चालू वर्ष में भी कर्मचारियों की संख्या में, यातायात में 80 लाख मीटरिक टन की प्रत्याशित वृद्धि के अनुपात से कम वृद्धि होगी। यह एक उत्साहवर्द्धक बात है क्योंकि संचालन-व्यय का लगभग दो-तिहाई अंश कर्मचारियों पर खर्च होता है। मैं रेल प्रशासनों से बराबर कहता रहूंगा कि वे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास जारी रखें।

5. मूल्यह्रास आरक्षित निधि से किये जाने वाले खर्च के अनुमान में लगभग 6 करोड़ रुपये की कमी है। इसे देखते हुए इस निधि में अंशदान की रकम 5 करोड़ रुपये घटा दी गयी है, अर्थात् 100 करोड़ के बजट अनुमान से घटाकर इसे 95 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

6. अब संशोधित अनुमान की स्थिति यह है कि कुल संचालन-व्यय को पूरा कर लेने और मूल्यह्रास खाते में 95 करोड़ रुपये और पेंशन निधि में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर लेने के बाद, शुद्ध राजस्व 141.32 करोड़ रुपये बच रहेगा, जो 151.33 करोड़ रुपये की लाभांश सम्बन्धी हमारी दायिता से केवल 10.01 करोड़ रुपये कम होगा। यह कमी राजस्व आरक्षित निधि से पूरी की जायेगी। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि बजट पेश करने के बाद रेलों पर जो दायिताएं आयीं, उन्हें देखते हुए, वे इससे कुछ अधिक अच्छा नहीं कर सकती थीं।

7. चालू वर्ष में निर्माण कार्यक्रम के लिए 272 करोड़ रुपये शुद्ध व्यय की बजट व्यवस्था थी। इसका संशोधित अनुमान 15 करोड़ रुपये कम है। चल-स्टाक के अन्तर्गत 9 करोड़ रुपये, भण्डार उचंत के अन्तर्गत लगभग 3 करोड़ रुपये और निर्माण और विविध अग्रिम उचंत के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये की कमी हुई है। अन्य जमाखातों के अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण शुद्ध व्यय कुछ और कम हो गया है। लेकिन विद्युतीकरण और कुछ अन्य शीर्षकों में फुटकर वृद्धि के कारण खर्च लगभग $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये बढ़ गया। इस बात की बहुत कम सम्भावना है कि निजी क्षेत्र से 14,500 से अधिक माल-डिब्बे मिल सकेंगे, जबकि बजट में 16,800 माल डिब्बों की व्यवस्था है। इस प्रकार इस मद में 1.85 करोड़ रुपये की बचत होगी।

8. निर्माण कार्यक्रम का जिक्र करते समय मैं उन प्रमुख निर्माण कार्यों की संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा जो इस वर्ष पूरे हो गये हैं या जिन पर काम हो रहा है। दक्षिण रेलवे की सेलम-बेंगलूरु लाइन का धर्मपुरी से बेंगलूरु तक का बाकी हिस्सा, पश्चिम रेलवे की झुंड-कांडला बड़ी लाइन का ध्रांगध्रा-हलवद खण्ड और दक्षिण रेलवे की रेनिगुन्टा से तिरुपति तक की बड़ी लाइन यातायात के लिये खोल दी गयी है। उत्तर रेलवे की दिल्ली परिहार लाइन अभी हाल में यातायात के लिए खोली गयी है। दूसरे निर्माण कार्यों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है। दक्षिण-मध्य रेलवे के मीरज-कोल्हापुर खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। आशा है 300 किलोमीटर नयी दोहरी लाइन यातायात के लिए चालू वर्ष में खोल दी जायगी और 850 किलोमीटर लाइन पर काम प्रगति के विभिन्न चरणों में है। सिगलन-व्यवस्था में आधुनिक सुधार करने के कार्यक्रम में प्रगति जारी है। महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों पर माइक्रोवेव प्रणाली का विस्तार, चालू और आगामी दोनों वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल है। यह काम गाड़ियों के परिचालन में सुधार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मध्य रेलवे के नन्दगांव-भुसावल खण्ड पर विद्युतीकरण का काम इस वर्ष और पूर्व रेलवे की आंदुल-कलकत्ता कार्ड लाइन पर अगले वर्ष पूरा हो जाने की आशा है। उत्तर रेलवे के कानपुर-टूंडला और दक्षिण पूर्व रेलवे के राउरकेला-दुर्ग खण्डों पर विद्युतीकरण का काम प्रगति पर है और आशा है पश्चिम रेलवे के 'विरार-साबरमती खण्ड पर क्षेत्रकार्य शीघ्र ही आरम्भ होगा।

9. अब मैं 1969-70 के बजट का उल्लेखन करूंगा। चालू वर्ष के अनुभव के आधार पर और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में रेल यातायात में संभावित वृद्धि के बारे में इस समय हमने जो निकटतम अनुमान लगाया है, उसके आधार पर हमें आशा है कि अगले वर्ष रेलें लगभग 90 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त राजस्व उपार्जक माल ढोयेंगी। मुझे यह भी आशा है कि यात्री यातायात में वृद्धि जारी रहेगी और अगले वर्ष यात्री यातायात लगभग 3 प्रतिशत बढ़ेगा। माल यातायात से 600 करोड़ रुपये, यात्री यातायात से 273 करोड़ रुपये, अन्य कोचिंग यातायात से 47.5 करोड़ रुपये और फुटकर मद में 30.5 करोड़ रुपये आमदनी होने की सम्भावना है। अप्राप्त आमदनी में लगभग 4.2 करोड़ रुपये की वृद्धि का ध्यान रखते हुए, अगले वर्ष के लिए यातायात से कुल प्राप्तियों का बजट अनुमान 946.8 करोड़ रुपये रखा गया है, जो इस वर्ष की तुलना में लगभग 45 करोड़ रुपये अधिक है। साधारण संचालन-व्यय का अनुमान 665.35 करोड़ रुपये रखा गया है, जो इस वर्ष की तुलना में लगभग 25 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 22.65 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। कर्मचारियों की लागत में वृद्धि उन्हीं कारणों से है जिनसे चालू वर्ष में इस मद का खर्च बढ़ा है, अर्थात् मंहगाई भत्ते में वृद्धि, मंहगाई भत्ते के एक अंश को वेतन में मिला दिया जाना और रनिंग तथा यात्रा भत्तों में वृद्धि हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक वेतन वृद्धियों के कारण कर्मचारियों की लागत बढ़ेगी। ईंधन पर 4.28 करोड़ रुपये अधिक खर्च आयेगा। ईंधन के खर्च में यह वृद्धि दो कारणों से है : एक तो यह कि कोयले की कीमत बढ़ गयी है और दूसरे यह कि प्रत्याशित अतिरिक्त माल की ढुलाई के लिए व्यवस्था की गयी है।

10. मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में चालू वर्ष के ही स्तर पर अर्थात् क्रमश: 95 करोड़ और 10 करोड़ रुपये विनियोग करने का प्रस्ताव है। बजट अनुमान के अनुसार 160.92 करोड़ रुपये के शुद्ध राजस्व की आशा है। लाभांश सम्बन्धी हमारी अनुमानित दायिता 159.01 करोड़ रुपये है जो परसाल के मुकाबले लगभग 8 करोड़ रुपये अधिक है। इस दायिता को पूरा कर लेने के बाद 2 करोड़ रुपये से कुछ कम अधिशेष बच रहेगा। बजट अनुमान तैयार करने में बहुत सावधानी बरती गयी है। यदि रेलों के काबू से परे किन्हीं कारणों से लागतें बढ़ न जायें, तो मैं आशा करता हूं कि प्रत्याशित अधिशेष वस्तुतः प्राप्त कर लिया जायेगा।

11. अगले वर्ष निर्माण कार्यक्रम पर 255 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है, जिसमें से 132.6 करोड़ रुपये पूंजीखाते, 95 करोड़ रुपये मूल्यह्रास आरक्षित निधि, 19 करोड़ रुपये विकास निधि और 8.4 करोड़ रुपये राजस्व खाते के खर्च के हैं। इसमें से चल-स्टाक और मशीनों पर लगभग 118 करोड़ रुपये, जिसमें सामान के लिए निर्माताओं को दिये जाने वाला अग्रिम भी शामिल है, और निर्माण कार्यों पर 134 करोड़ रुपये, के शुद्ध व्यय का अनुमान है। 'भंडार-सूची' के अन्तर्गत खर्च में लगभग 4 करोड़ रुपये की कमी होने की आशा है। निर्माण कार्यक्रम यथोचित निम्नतम स्तर पर रखा गया है।

12. निर्माण कार्यक्रम में जो नये काम शामिल किये गये हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं : मध्य रेलवे में आगरा और बीना के बीच और दक्षिण-मध्य रेलवे में काजीपेट और बल्हारशाह के बीच ग्रैंड ट्रंक मार्ग के कुछ और टुकड़ों पर दोहरी लाइन, दक्षिण रेलवे में जोलारपेटै और कोच्चिन के बीच और पश्चिम रेलवे में अलनिया और कोटा के बीच कुछ टुकड़ों पर दोहरी लाइन। पूर्वोत्तर रेलवे में भप्तियाही और थुरभिटा के बीच लाइन को फिर से चालू करने और बोकारो इस्पात कारखाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजावेड़ा-बोकारो स्टील सिटी मुरी-हाटिया खंडों पर दोहरी लाइन बिछाने के काम भी निर्माण कार्यक्रम में शामिल हैं।

13. चौथी पंचवर्षीय योजना शीघ्र ही आरम्भ होने वाली है। योजना आयोग और सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से यातायात में वृद्धि का हम जो निकटतम अनुमान लगा सके हैं, उससे यह मालूम होता है कि चालू वर्ष के मुकाबले चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 620 लाख मीटरिक टन अधिक यातायात होगा। इस वृद्धि में आधे से अधिक भाग इस्पात कारखानों को भेजे जाने वाले कच्चे माल, जिसमें कोयला भी शामिल है, अन्य उपभोक्ताओं के लिए कोयला और निर्यात के लिए लौह अयस्क का है; शेष वृद्धि अन्य प्रकार के माल यातायात में होगी जिसमें इस्पात कारखानों से 30 लाख मीटरिक टन तैयार माल और 30 लाख मीटरिक टन सीमेंट भी शामिल है। तीसरी योजना में कच्चे माल के परियोजित भारी यातायात और इस्पात कारखानों के तैयार माल और देश के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में भेजे जाने वाले कोयले के यातायात में प्रत्याशित भारी वृद्धि को संभालने के लिए जो क्षमता निर्मित की गयी थी, उसका केवल आंशिक उपयोग किया गया और रेलवे की वित्तीय स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इस्पात कारखानों के लिए कच्चे माल और कोयले के यातायात में वृद्धि के जो आशापूर्ण लक्षण दिखायी दे रहे हैं, उनसे हम यह आशा कर सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा बशत, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, वेतन और मूल्यों में वृद्धि के कारण स्थिति पर प्रभाव न पड़े, जैसा कि हाल के वर्षों में हुआ है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम विकास की जिस नीति का अनुसरण करना चाहते हैं, उसका लक्ष्य यह है कि लाइन क्षमता, अथवा, सुधरे ढंग की मार्शलिंग सुविधाओं और कर्षण के आधुनिकीकरण, सिगनलिंग और कारखाने की सुविधाओं अथवा चल-स्टाक के रूप में जो परिसम्पत्तियां निर्मित या अर्जित की जा चुकी हैं, उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाये। इन परिसम्पत्तियों का अधिक अच्छा उपयोग करके हम कर्मचारियों से भी अधिक काम ले सकेंगे। हमें आशा है कि इन दोनों बातों से खर्च में उसी प्रकार किफायत होगी जिस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में साल-ब-साल और तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में हुई थी जब यातायात क्रमश: बढ़ रहा था। पिछले तीन वर्षों में जब यातायात में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो यह प्रक्रिया रुक गयी। यद्यपि आगामी वर्षों के बारे में हम आशावादी हैं, लेकिन पूंजीगत खर्च हमें बहुत सोच-समझ कर करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के

दौरान बढ़ते हुए यातायात के लिए रेल क्षमता का अभाव न हो, लेकिन किसी काम में समय से पहले या अलाभकर कार्यों में पैसा लगाने से हमें बचना होगा। जिन नये कामों पर पैसा लगाया जायेगा, उनसे शीघ्र अधिकतम स्थूल और वित्तीय लाभ पाने के लिए उनकी अग्रताएं बहुत सोच-समझ कर निर्धारित की जायेंगी। इस लक्ष्य को सामने रखकर लाइन की क्षमता बढ़ाने, मार्शलिंग सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने, नयी रेलवे लाइनों के निर्माण और मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कई प्रस्तावों के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। अगले वर्ष कुछ और सर्वेक्षण भी किये जायेंगे। सावधानी के साथ किये जा रहे इन इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों तथा निवेश प्रस्तावों के आर्थिक लाभ और वित्तीय प्रतिफल की पूरी जांच से यह निर्णय करने का पर्याप्त आधार मिल जायेगा कि इनमें से किन प्रस्तावों पर अमल किया जा सकता है।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के महानगरों में उपनगरीय यातायात बढ़ रहा है और उपनगरीय रेल सेवाओं पर इसका बोझ भी बढ़ता रहा है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इस समस्या के लिए अधिक आमूल समाधान अपेक्षित है। कलकत्ता और बम्बई की समस्याओं को प्रथम अग्रता देने की आवश्यकता है। योजना आयोग के परामर्श से यह तय किया गया है कि रेल प्रशासन कलकत्ता में उपनगरीय डिसपर्सल लाइन का अन्तिम मार्ग निर्धारण, सर्वेक्षण और उसकी सविस्तार योजना, बम्बई में बलार्ड स्टेट में एक तीसरे टर्मिनल का सर्वेक्षण और कलकत्ता में एक द्रुतगामी परिवहन प्रणाली की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में उसके तकनीकी और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करे। मध्य रेलवे में कुर्ला-मानखुर्द खण्ड पर 'बाई-पास' के लिए सर्वेक्षण किया भी जा चुका है। इस सम्बन्ध में रेलवे पर कितना वित्तीय और परिचालन-संबंधी उत्तरदायित्व आना चाहिए, इस बात की आगे और जांच की जायेगी।

14. सामान्य राजस्व के प्रति रेलवे की 159 करोड़ रुपये की लाभांश सम्बन्धी अनुमानित दायिता को पूरा कर लेने के बाद अगले वर्ष के लिए मैं लगभग 2 करोड़ रुपये के अल्प अधिशेष का बजट अनुमान सदन में पेश कर सका हूं। मैं रेल का किराया और भाड़ा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं। लेकिन मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि रेलवे की लगातार तीन साल से गिरी हुई वित्तीय स्थिति के बाद बजट में यह थोड़ा सा सुधार हुआ है। इन तीन वर्षों में रेलें राजस्व आरक्षित निधि से पैसे लेकर लाभांश का पूरा भुगतान कर सकी हैं और अब इस निधि में केवल 1.29 करोड़ रुपये बच रहे हैं। पिछले वर्ष विकास निधि बिल्कुल समाप्त हो गयी थी और इस वर्ष इस निधि में हम कुछ जमा नहीं कर सकेंगे। अगले वर्ष भी प्रायः यही स्थिति रहेगी। विकास निधि से किये जाने वाले खर्च के लिए 1969-70 के अन्त तक हम सामान्य राजस्व से 45.80 करोड़ रुपये कर्ज ले चुके होंगे। यह सौभाग्य की बात है कि मूल्यह्रास आरक्षित निधि की स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक है। आशा है चालू वर्ष के अन्त में इसमें 86.01 करोड़ रुपये और 1969-70 के अन्त में 92.30 करोड़ रुपये होंगे। पेंशन-निधि में चालू वर्ष के अन्त में 62.55 करोड़ रुपये रहेंगे और यह रकम चालू दायिताओं

का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन इस वर्ष बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों के भविष्य निधि के बदले पेंशन-योजना अपनाने और महंगाई भत्ते का कुछ अंश वेतन में मिला देने के कारण पेंशन-सम्बन्धी दायिताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, इसलिए आगामी वर्षों में पेंशन-निधि में हमें अंशदान भी बढ़ाना पड़ेगा।

15. इन तथ्यों को मैं इसलिए सदन के ध्यान में ला रहा हूं ताकि सदन यह अनुभव करे कि आगामी वर्षों में रेलों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अधिशेष अर्जित करना जरूरी होगा। विकास निधि से सम्बन्धित खर्च के लिए सामान्य राजस्व से लिया गया कर्ज वापस करना पड़ेगा और विकास-निधि में फिर पर्याप्त रकम जुटाने के लिए आवश्यक अधिशेष की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अपेक्षित वित्तीय साधन जुटाने के उद्देश्य से अन्य सभी सरकारी उपक्रमों की तरह रेलवे को भी अपने हिस्से के अनुरूप अंशदान करना होगा। मैं आशा करता हूं कि रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के काम में हमें आगामी वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था के विकास और उसकी गतिशीलता से सहायता मिलेगी और मन्दी शीघ्र ही अतीत की बात बन जायेगी। परिचालन-दक्षता बढ़ाने, ऊंची दर वाला अधिक यातायात प्राप्त करने और ग्राहकों की उत्तरोत्तर अधिक सेवा करने के लिए रेल प्रशासन कुछ उठा न रखेंगे। हर क्षेत्रीय रेलवे में जो नया पणन और विक्रय संगठन बनाया गया है, वह ऊंची दर वाला यातायात प्राप्त करने और कन्टेनर सेवा का विस्तार करने में उपयोगी काम कर रहा है। इस वर्ष जनवरी में मद्रास और बेंगलूरु के बीच पांच-मीटरिक टन की नयी कन्टेनर सेवा आरंभ की गयी और आशा है दिल्ली-हावड़ा, बम्बई-मद्रास और बम्बई-सिकन्दराबाद के बीच भी शीघ्र ही कन्टेनर सेवाएं चालू कर दी जायेंगी। दिल्ली और बम्बई के बीच माल भेजने की एक नयी योजना चालू की गयी है। इस योजना में सड़क-वाहनों के मालिक, व्यापारियों के गोदाम से माल ले आते और गन्तव्य स्थान पर उसे सुपुर्द करते हैं और लाइन पर माल ढोने की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाती है। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो हम अन्य ट्रंक मार्गों पर भी इस योजना को आरम्भ करना चाहते हैं। यह योजना रेल-सड़क समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक अगला कदम सिद्ध होगी और इससे सड़क-वाहनों के मालिकों और रेलवे दोनों को लाभ होगा।

16. मैं बिना टिकट यात्रा की व्यापक समस्या की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हर महीने 9 लाख से भी अधिक लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। इससे न केवल रेलवे को कई करोड़ का नुकसान होता है, बल्कि इससे कानून और व्यवस्था की भी समस्या पैदा हो गयी है। इस बुराई को रोकने के लिए राज्य सरकारों और रेलवे सुरक्षा दल की सहायता से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है और इससे कुछ उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों को कड़ा दण्ड दिया जाये। इस सम्बन्ध में संसद् के सामने एक बिल पेश किया जा रहा है और मेरा निवेदन है कि इस विधान को यथासंभव शीघ्र पास कर दिया जाये।

17. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कुछ समय पहले रेलवे बोर्ड ने रेल-संचालन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में लागत-अध्ययन आरम्भ किया था। अब इस अध्ययन के परिणाम उपलब्ध हो गये हैं और रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य की हैसियत के एक प्रवर अधिकारी किराये और भाड़े को तर्कसंगत बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इस अध्ययन का एक उद्देश्य यह निश्चित करना है कि लागत-अध्ययन के परिणामों के अनुरूप भाड़े और किराये के ढांचे में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि रेल किराये और भाड़े को किस प्रकार अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाये। रेल और सड़क परिवहन के बीच समन्वय बढ़ाने के लक्ष्य का भी ध्यान रखा जायेगा। इन सिद्धान्तों के आधार पर भाड़े और किराये के ढांचे को तर्कसंगत बनाते समय यह भी संभव होना चाहिए कि रेलवे के विकास और अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साधन भी सुलभ हो जायें।

18. चल-स्टाक तैयार करने वाले रेलवे के तीनों कारखाने संतोषजनक काम कर रहे हैं। चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने में इस वर्ष लगभग 68 भाप रेल इंजन, 53 बिजली रेल इंजन और 24 डीजल शंटर तथा अगले वर्ष उत्पादन बढ़ाकर 70 भाप रेल इंजन, 60 बिजली रेल इंजन और 48 डीजल शंटर तैयार किये जाने की आशा है। मद्रास स्थित सवारी डिब्बा कारखाने में इस वर्ष 730 सवारी डिब्बों के खोल तैयार किये जाने और इनमें से 634 में साज-सामान लगाये जाने और अगले वर्ष 740 सवारी डिब्बों के खोल तैयार किये जाने और 670 में साज-सामान लगाये जाने की आशा है। वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन कारखाने में इस वर्ष बड़ी लाइन के 68 और मीटर लाइन के 10 रेल इंजन और अगले वर्ष बड़ी लाइन के 75 और मीटर लाइन के 30 रेल इंजन तैयार किये जाने की सम्भावना है। इन तीनों उत्पादन यूनिटों में कुछ अन्य प्रकार के चल-स्टाक भी तैयार किये जा रहे हैं : चित्त-रंजन में मीटर लाइन के रेल इंजन और डीजल शंटर, सवारी डिब्बा कारखाने में बिजली रेलगाड़ी के डिब्बे और रेलकार और डीजल रेल इंजन कारखाने में मीटर लाइन के डीजल रेल इंजन। इन तीनों कारखानों के कुल उत्पादन का मूल्य प्रति वर्ष 59 करोड़ रुपये से अधिक आता है।

19. रेल प्रशासनों को तकनीकी सलाह देने के अतिरिक्त इस वर्ष लखनऊ स्थित अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन वैकुअम ब्रेक और सम्पीडित वायु ब्रेक के कार्य के अध्ययन और डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने से सम्बन्धित जांच के काम में लगा रहा। संगठन ने रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के बहुत से अभिकल्प तैयार किये और माल डिब्बे निर्यात करने के काम में यह राज्य व्यापार निगम की सक्रिय रूप से सहायता करता रहा है। इसके अलावा संगठन ने न केवल देश की आवश्यकताओं के लिए, बल्कि निर्यात के लिए भी उपस्कर और सामान का निरीक्षण भी आरम्भ किया है; जैसे ईरान भेजने के लिए रेल की पटरियों का निरीक्षण, कोरिया से मिले आर्डर के लिए माल डिब्बों के पहियों का निरीक्षण, लंका भेजने के लिए बोगी टंकी माल डिब्बों का निरीक्षण, आदि।

20. चालू वर्ष में अक्टूबर, 1968 के अन्त तक, 23 नई गाड़ियां चलाई गई हैं—13 बड़ी लाइन पर और 10 मीटर लाइन पर। वर्तमान 22 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है—8 बड़ी लाइन पर और 14 मीटर लाइन पर। जहां तक उपनगरीय गाड़ियों का सम्बन्ध है, 33 नई गाड़ियां चलाई गई हैं—24 बड़ी लाइन पर और 9 मीटर लाइन पर और 10 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है। मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूं कि उपनगरीय सेवाओं में, विशेष रूप से बम्बई क्षेत्र में, आगे और विस्तार और सुधार करने की आवश्यकता है और हमारा प्रयास भी यही रहेगा; लेकिन उपनगरीय सेवाओं में सुधार के सम्बन्ध में हमारी कठिनाई यह है कि बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में बिजली गाड़ियों के बहुत से पुराने डिब्बों को बदलना है और इस समय अधिक तादाद में बिजली गाड़ी के डिब्बे बनाना हमारे लिए मुश्किल है। इस वर्ष लम्बी दूरी की कई नई गाड़ियां चलाई गई हैं जिसके फलस्वरूप दैनिक गाड़ी किलोमीटर में 3000 से अधिक की वृद्धि हुई है। इन नई गाड़ियों में बम्बई सेन्ट्रल और अमृतसर के बीच चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस भी शामिल है। नई दिल्ली और हावड़ा के बीच पहली मार्च से राजधानी एक्सप्रेस चलाने का विचार है। यह गाड़ी हफ्ते में दो बार चलेगी और 18 घण्टे से कम समय में नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी तय करेगी। इस वर्ष के शुरू में तीसरे दर्जे के 1260 शयन-यान चलाये जा रहे थे। वर्ष के दौरान लगभग 115 शयन-यान और चलाये गये। अगले वर्ष और शयन-यान बनाये जायेंगे।

21. माननीय सदस्य जानते हैं कि पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों को छोड़कर बाकी सब रेलें मण्डल प्रणाली के आधार पर संगठित हैं। इस बात की सम्भावना है कि चौथी योजना में रेल परिचालन अधिक जटिल हो जायेगा और रेलों पर काम का भार बढ़ेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों रेलों में भी मण्डल प्रणाली लागू करना आवश्यक हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे में चार मण्डल होंगे जिनके प्रधान कार्यालय आइजटनगर, लखनऊ, वाराणसी और समस्तीपुर में होंगे। समस्तीपुर मण्डल में पूर्वोत्तर रेलवे का पश्चिम कटिहार जिला भी शामिल होगा। जहां तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का सम्बन्ध है, इस रेलवे के वर्तमान जिलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मण्डल बनाया जा रहा है। केवल तिनसुकिया में उस समय तक परिवहन मण्डल रहेगा जब तक कार्य-भार को देखते हुए उसे पूरा मण्डल बनाना आवश्यक न हो।

22. मेरे सहयोगी श्री परिमल घोष की अध्यक्षता में जो रेलवे खानपान और यात्री सुविधा समिति नियुक्त की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1968 में दी। इस समिति की अधिकतर सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। आशा है इन सिफारिशों पर अमल किये जाने के फलस्वरूप खानपान सेवाओं से ग्राहकों को अधिक संतोष होगा। अब यात्रियों को कई प्रकार के भोजन के पैकेट दिये जा रहे हैं और यदि यात्री इस व्यवस्था को पसन्द करेंगे, तो संभव है कि महत्वपूर्ण गाड़ियों में इस समय जो भोजन-यान लगे होते हैं, उनकी जगह सवारी डिब्बे लगाकर यात्रियों के लिए कुछ अधिक स्थान की व्यवस्था की जा सके। 1967-68 में भारतीय रेलों की विभागीय खानपान व्यवस्था में लगभग 6 करोड़ रुपये की बिक्री पर लगभग 6 लाख रुपये का लाभ हुआ और आशा है कि लाभ की मात्रा इस वर्ष बढ़ेगी।

23. भारत के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, श्री कैलाश नाथ वांचू की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट के भाग 1 को माननीय सदस्यों ने देखा होगा। यह समिति रेल दुर्घटना समिति, 1962 (कुंजरू समिति) की नियुक्ति के समय से भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा कर रही है। इस रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि 1962-63 में समाप्त होने वाले छः वर्षों की तुलना में 1967-68 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं की वार्षिक औसत संख्या में लगभग 35 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई है। समिति द्वारा प्रकट किये गये विचारों और उसकी सिफारिशों और उन पर रेल मंत्रालय के विचारों का एक विवरण माननीय सदस्यों को दिया जा रहा है।

24. रेलवे में सुरक्षा और पुलिस-व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री शान्तिलाल शाह की अध्यक्षता में जो उच्चाधिकार-प्राप्त समिति बनायी गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट 10 अक्टूबर, 1968 को दी। इस रिपोर्ट की सिफारिशों का अब अध्ययन किया जा रहा है। इसकी कुछ सिफारिशों के प्रभाव बहुत दूरगामी हैं।

25. इस वर्ष कई निर्णय किये गये हैं जिनसे रेल कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बारह महीने के औसत मूल्य सूचक अंक 175 पर समूचा महंगाई भत्ता वेतन में मिला दिया गया है। इससे सेवा-निवृत्ति के बाद कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जिन कर्मचारियों ने पेंशन-योजना नहीं अपनायी है, उनकी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान की रकम बढ़ गयी है। इससे कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और यात्रा भत्ता भी बढ़ गया है। 1 मार्च, 1968 से यात्रा भत्ते और रनिंग भत्ते की दरों में जो संशोधन किया गया है, उसकी वजह से इनकी दरें काफी बढ़ गयी हैं। महंगाई भत्ते के एक अंश को वेतन में मिला दिये जाने के निर्णय के बाद उन रेल कर्मचारियों को पेंशन-योजना के लिए विकल्प देने का फिर एक अवसर दिया गया है जो अभी भी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत हैं। विकल्प देने की तारीख 31 मार्च, 1969 तक बढ़ा दी गयी है। भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ के अनुरोध पर और उसके परामर्श से एक-सदस्यीय अधिकरण बनाया गया है जो संघ की कतिपय मांगों पर विचार करेगा, जिनके बारे में रेल कर्मचारियों और रेलवे बोर्ड के स्थायी वार्तातंत्र के बीच समझौता नहीं हो सका है। इन मांगों में कुछ अन्य मांगों के साथ-साथ रात की ड्यूटी के भत्ते का विषय-क्षेत्र और उसकी दरें, नैमित्तिक मजदूरों की मजदूरी, स्टेशनों, शेडों और डिपुओं में तैनात क्लर्कों के लिए काम के घंटे और अवकाश, वर्तमान काम के घंटों और रनिंग कर्मचारियों के वेतन-मान और गैंगमैनों की परिलब्धियों की समीक्षा आदि मांगें शामिल हैं। गुजरात हाईकोर्ट के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, श्री एन० एम० मियाभाय इस अधिकरण के एकमात्र सदस्य होंगे। मैं महसूस करता रहा हूं कि जो कर्मचारी कुछ समय से अपने वेतन-मान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं, उन्हें कुछ राहत देने की आवश्यकता है। इस मामले पर हम विचार कर रहे हैं और एक-सदस्यीय अधिकरण की सिफारिशों के

आधार पर कर्मचारियों को जो लाभ मिलेंगे, उनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार राहत दी जायेगी। केन्द्रीय सरकार की समतुल्य सेवाओं की तुलना में रेल अधिकारियों का वेतन और उनकी पदोन्नति की सम्भावनाएं कम होती जा रही थीं ; अतः स्थिति को सुधारने के लिए उनके संवर्ग में, अपेक्षाकृत नगण्य लागत पर, कुछ समंजन किये गये हैं और कुछ अन्य समंजनों के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि उपलब्ध प्रतिभा का यथोचित अंश रेल सेवाओं की ओर आकृष्ट होता रहे और इस समय जो लोग रेल सेवा में हैं, वे यह महसूस करें कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है।

26. विगत वर्षों की तरह चालू वर्ष में भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई और काम किये गये, विशेषरूप से कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए इलाज की सुविधाएं बढ़ायी गयीं। उत्तर रेलवे के बीकानेर मण्डल में लालगढ़ में एक अस्पताल बनाया गया है। दक्षिण रेलवे में एक और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में दो स्वास्थ्य यूनिटों को अस्पताल में बदल दिया गया है। चालू वर्ष में सामान्य रोगियों के लिए 528 और क्षय के रोगियों के लिए 120 खाटें बढ़ायी गयी हैं। निदान और उपचार के लिए विशिष्ट यूनिटों की संख्या बढ़ायी जा रही है और रेलवे अस्पतालों में अतिरिक्त उपस्कर की व्यवस्था की गयी है। सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए जो अंशदायी स्वास्थ्य योजना आरम्भ की गयी है, उसका लाभ अब सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को भी दिया जा रहा है। रेल चिकित्सा सेवाएं परिवार नियोजन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और इस काम में रेल कर्मचारियों की अनुक्रिया उत्साहवर्धक रही है। रेलवे स्कूलों का विस्तार इस वर्ष भी जारी रहा और सहायता-प्राप्त हास्टलों, तकनीकी शिक्षा के लिए दी गयी छात्रवृत्तियों और चलते-फिरते पुस्तकालयों आदि का उपयोग भी होता रहा। खेल-कूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सहायता दी जाती रही। रेलें आठ खेल-कूदों में राष्ट्रीय विजेता रहीं और 24 रेल कर्मचारी उन भारतीय टीमों के सदस्य रहे जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 1967 में छः रेल कर्मचारियों ने स्पृहणीय अर्जुन पुरस्कार जीता है।

27. चालू वर्ष के दौरान रेल प्रशासन और संगठित श्रम के बीच आमतौर पर सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहा और स्थायी वार्तातंत्र उपयोगी काम करता रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि रेल-संचालन से मेरा पहले भी सम्बन्ध रहा है और मेरी धारणा है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों में उच्च कोटि की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि रेल कर्मचारियों से मेरा जो यह फिर सम्पर्क हो रहा है उससे उनकी योग्यता और कर्त्तव्य-निष्ठा के प्रति मेरी धारणा और बलवती होगी। मुझे यह भी विश्वास है कि वे रेलवे और देश की अधिक से अधिक सेवा करते रहेंगे।

मैं इस बात से बहुत चिन्तित हूं और मेरी तरह माननीय सदस्य भी चिन्तित होंगे कि बहुत से कारणों से, जिनका रेलवे या उसके परिचालन से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है, रेलों पर आक्रमण और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यह अत्यन्त दुखद प्रवृत्ति

बढ़ रही है। मैं उन बहुत सी अराजक गतिविधियों को गिनाना नहीं चाहता जिनसे रेल कर्मचारियों का काम उत्तरोत्तर अधिक कठिन और खतरनाक बनता जा रहा है और रेल-परिचालन में उत्तरोत्तर बाधा पड़ रही है। इन गतिविधियों और चल-स्टाक तथा संस्थापनाओं को पहुंचायी गयी क्षति के कारण रेल सेवा में सुधार करने की दिशा में हमारे प्रयास प्रायः विफल हो जाते हैं। माननीय सदस्यों को अपनी चिन्ताओं से अवगत कराने के साथ-साथ मैं इस सदन में और इससे बाहर लोकमत को दिशा निर्देश देने वाले नेताओं से अपील करता हूं कि वे हमें अपना पूरा-पूरा सहयोग दें ताकि रेलें देश के हर कोने में सुगमतापूर्वक चल सकें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 20 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Twenty minutes past Fourteen of the Clock

[**श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए** / **Shri R. D. Bhandare in the Chair**]

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी
MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

सभापति महोदय : अब 18 फरवरी, 1969 को श्री पी० राममूर्ति द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है।"

Shri Manubhai Patel (Dabhoi) : The mover of this No-confidence motion had concentrated himself on two or three points. He has alleged that the Congress and the Congress Government have failed in taking any concrete steps against Shiv Sena. He has further alleged that the results of mid-term elections have proved that popular verdict is against the Congress. His third allegation was that Government had failed to remove regional imbalance. I want to say that there is no weight in his allegations. He has given more emphasis on the question of Shiv Sena. I want to tell him that Shiv Sena is not a creation of Congress. We all know that Congress is always opposed to regionalism, communalism and casteism. The Congress have always opposed these tendencies. But on the contrary the S. S. P. and P. S. P. in connivance with the Communists have joined hands with Shiv Sena in Bombay during elections. It was the P.S.P. leader, Shri Nath Pai who said that Bal Thakre is a leader and Government should release him. So far as S.S.P. is concerned it is clear that they are following the Communist principle of character assassination.

Shri S. M. Joshi (Poona) : What is Shiv Sena ?

Shri Manubhai Patel: I will tell you that. The basic source of the ideology of Shiv Sena are Communists. The Communists want to create disorder and lawlessness in the country in the name of class struggle and they join hands with all those organisations who believe in class struggle. During last session a question was asked from the Hon. Home Minister whether he was contemplating to ban Red Army in Kerala and when he replied that legally it was not possible to ban the Red Army, the Communists were overjoyed. The question of Shiv Sena is similar to that of Red Army.

We do not like the activities of Shiv Sena. We are deadly against them. Bombay is a cosmopolitan city. People belonging to all religions, States and communities reside there. The Shiv Sena is out to destroy its cosmopolitan character. They are acting against that constitutional provision by which every citizen has been given a right to settle in any part of the country and carry on any profession. Shiv Sena should understand that their activities will destroy the cosmopolitan character of Bombay. Whatever is being done by them is unprecedented in the history of Bombay. There have been agitations and demonstrations in Bombay during the past, but never before such a picture was projected. I demand that the true picture of the activities of Shiv Sena should be brought before the people of India, so that they become sure that Congress never encourages such tendencies. The Communists and the S.S.P. have joined hands with Shiv Sena, because their aim is one. Both these parties believe in character assassination. They are fully aware that they are unable to throw any party out of power by criticising their policies and programme. So they have adopted this path of character assassination. The S.S.P. has tried to defame the Prime Minister by raising the question of mink coat and then that of diamond necklace during the last sessions of Parliament. They also tried to defame the Finance Minister by saying this and that about his son.

Now they are trying to defame the Home Minister by saying that he is giving encouragement to Shiv Sena. The Communists believe that if they succeed in defaming four or five top leaders of Congress, they will be able to uproot Congress and that is why they have brought this no-confidence motion. I want to warn both these parties that they will never succeed in their aims.

So far as the question of imposing legal restrictions on Shiv Sena is concerned, it should have been legally banned if other Senas like Red Army, Lachit Sena and R.S.S. would have been banned. Shiv Sena had done many wrong things. They have taken the law in their own hands. They have burnt buses and indulged in so many other acts of violence. But I fail to understand why Socialist Party is silent on this point. They are silent because they have joined hands with Shiv Sena during election. I appeal to all the parties to condemn such activities.

While moving this No-confidence motion Shri Ram Murthi had said that no reference had been made in the President's Address regarding these incidents. I want to tell him that a reference had been made in the President's Address about these incidents. The President had said, "Last year, I referred in my speech to certain disturbing trends in our national affairs. Parochial, regional, caste and communal movements have caused tensions and violence in the country." In his address the President has further said, "However, while legal and administrative measures are necessary, the fight against these fissiparous movements has to be carried to the broad masses of our people. The key to success lies in fostering the concept of Indian Nationalism and Secularism in the minds and hearts of our people." So it is wrong to say that no

reference has been made about these incidents in the President's Address. The need of the hour is to create public opinion in favour of national unity and integrity. A collective action should be taken in this regard.

So far as the results of the elections are concerned, they are talking about Bengal only. They do not talk about U. P., Bihar and Punjab, where Communists have been badly defeated. Moreover you all know as to what is happening in Bengal. The bickering has already started among the constituents of the United Front in Bengal and they are finding it difficult to choose their leader. There cannot be any ideological unity in the United Front which is composed of 14 parties. Our past experience of the United Fronts had been very bitter and there is every reason to believe that the present United Front will meet the same fate. The Communists want to capture power. They have no faith in Constitution. They want to capture power by any means—including unconstitutional means. The Public has fully understood them.

I also want to tell to Shri P. Rama Murthi that the President has also said in his Address that the country faces the danger of violence from certain extremist political groups. The doctrines propounded by these groups are clearly subversive of our Constitution and the rule of law and detrimental to the order by Government and progress. There is no place in a democratic society for groups which seek to change the social and political structure by armed insurrection. So we have to keep this caution in view and we have to expose them who have no faith in democracy, who have no faith in the Constitution and who only pretend to be democratic just to deceive the Public.

I oppose this motion of No-confidence.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Chairman, Sir, yesterday the Members of my party did not rise in their seats, when this No-confidence motion was moved. But it does not mean that we had confidence in this Government. The only fact is that my party was not so much anxious to remove this Government as other parties, who have moved this No-confidence motion. Now after having heard the speeches of Hon. Members I have come to the conclusion that they have done nothing wrong by moving this motion.

In the elections of 1967, the people of Punjab, U. P., Bihar and West Bengal had rejected the Congress and now in the mid-term elections of 1969 the people of these States had confirmed their decision to reject the Congress.

After the General Election of 1967 a new experiment of Coalition Governments was made in the country. The different constituent parties of the Coalition Governments prepared their minimum programmes and tried to save the people from the misrule of Congress. But the Congress could not tolerate those Governments and they were toppled. Those Governments were Constitutional Governments and had the majority support in the respective legislatures. But in order to capture power by back door, the Congress created minority Governments. I want to know how a minority Government can be termed as a democratic Government. But Congress did all this in order to capture power.

Today in Punjab Jan Sangh and Akalies are again in power. I want to know where Sardar Gill had gone who was supported by Congress. In Bihar the non-Congress parties are now again in a position to form Government. I want to know where Shri Mandal had gone who was supported by Congress.

In Bengal, the people have voted U. F. to power and they have rejected Congress. I want to know where Shri P. C. Ghosh had gone who was favoured by Congress. All this shows that people have lost faith in Congress. They do not like their policy and programme and they are fed up with it.

It has become clear in the mid-term elections that Congress party can go very low in order to capture power. The Congress party had claimed to be the protector of the interests of Hindus in Punjab in order to defeat Jan Sangh. In U. P., they have appealed to the narrow feelings of Brahmins and Vaishes. In Bengal they have tried to organise the non-Bengalis. In Bihar they promised a separate state of Jharkhand if they were returned to power. The Congress party has said that Congress had created the States of Andhra, Maharashtra and Haryana and it is Congress which would create a separate State of Jharkhand. I want to know whether the Prime Minister is aware of such tactics of Congressmen ? I want to know whether the Home Minister is aware that a promise has been given by Congressmen for a separate State of Jharkhand and if so, what action he contemplates to take to stop such things ?

The incidents in Andhra were very heart rendering. The people of the same State having a common language shed the blood of one another. Whatever has happened there had made it clear that the leadership which had been at the helm of affairs for last twenty years had utterly failed in creating confidence in the people of Telangana. The people of Telangana had been given certain assurances at the time of formation of the State of Andhra Pradesh. But those assurances were never implemented by the Congress which was in power both at the Centre as well as in the State. The backward people of Telangana were not given a fair deal by the Congress. They became dissatisfied and lost their faith in Congress. The Jan Sangh do not plead for a separate State of Telangana, but we plead for the removal of regional imbalance. Regional imbalance is the root cause of dissatisfaction. So it is high time that proper steps should be taken to remove regional imbalance.

Recently the report of the Gajendragadkar Commission has been published. This report should be an eye-opener to the Government. The report has confirmed the complaints of the discriminatory treatment being meted out to the people of Ladakh by the Government of Jammu and Kashmir. It is not surprising that the quantity of ration is more in Srinagar and it is less in Jammu and Ladakh ? It is also not surprising that ration is being given at cheap rates in Srinagar, whereas more price is being charged in Ladakh and Jammu. The people of Jammu and Ladakh are patriots, but for how long they are going to tolerate this discrimination ? The Gajendragadkar Commission had made some important recommendations in order to put an end to this discrimination. The Commission has recommended that there should be separate Development Boards for Jammu and Ladakh.

The Commission has also recommended that there should be a separate University for Jammu. The Commission has also emphasised the need for a Medical and Engineering College in Jammu. These recommendations should be implemented well in time, otherwise the Government should be prepared to face a people's movement.

What had happened in Bombay from February 10 to 14 should make every Indian hang his head in shame. The Maharashtra-Mysore border dispute certainly needed a solution, but it could not be solved in the streets by taking resort to violence. The State Government has

totally failed to take proper steps to check the acts of violence. The police did not take any action even when cases of loot and arson were reported to them. This dispute can not be settled in the present atmosphere. A proper climate should first be created and then efforts should be made to settle the dispute on the basis of certain agreed principles.

Is it not surprising that no mention of the famine conditions in Rajasthan has been made in the President's Address ? The people of Rajasthan are facing grave difficulties. About 4 lakh cattle heads had perished there and about seven to eight lakh people with their families are living under open sky. They have no house to live in. Their condition is very pitiable. Their is acute shortage of water. These poor people who are engaged in road construction work are facing untold hardships.

There had been political stability in Rajasthan. Even then why there are famine conditions. The reason is that the Rajasthan Canal Project has been neglected by the State Government. The Rajasthan Government is trying to show that the problem is not very serious. But it is not so. There is actual shortage of water and now summer is approaching and whatever little water is available, it will be dried up by sun. So I warn the Government if proper steps not taken in time another Bihar will be enacted in that state.

There are non-Congress Governments in certain states and some new non-Congress Governments are likely to be formed. I want to appeal to the Central Government that they should not play the game of toppling U.F. Governments with the help of Governors. It is unconstitutional and undemocra-tic. The Government should keep this in mind that from the era of one party Government, we are entering in the era of multi-party Governments. It is unfortunate that the Governors are finding it difficult to play their honest role and in all cases their actions go in the favour of Congress.

What is the position in Haryana today ? The Congress is in power there with the support of defectors who fought elections against the Congress candidates. The Congress who condemns defections is licking the feet of defectors in Haryana today.

The Governor did not ask the Chief Minister of Haryana to call the Assembly meeting within a week and face a trial of strength when the 41 legislators of S. V. D. placed their claim of majority in the State Assembly before him on 9th December, 1968. On the contrary, he advised them to test their strength when the Assembly met. The Governor during the course of his address to the Assembly stated that the Assembly was summoned to consider the Demands for grants and transact some legislative business. But before the opposition could throw a challenge to the ruling party for the trial of strength, one M. L. A. of SVD, Shri Jogindra Singh was kidnapped to Jaipur and Ajmer by two C. I. D. officers at the instance of the Chief Minister. Later on Shri Jogindra Singh made a detailed statement as to how he was treated and behaved during his disappearance. And we are prepared to give facts, figures and evidence in support of the charges levelled against them. It is a very serious incident and the Home Minister should institute an enquiry into this matter so that the veracity of the charges may come to light. Previously the non-Congress Government in Haryana was dismissed due to frequent defections in the State Legislative Assembly. But the Governor even after witnessing the recurrence of those happenings today is entirely unmoved . . . why? Because the congress party is in power there.

The Prime Minister during these mid-term-elections undertook hurricane tours and instead of educating the voters accused various political parties. But the question involved is who bore the expenses for her tours. Plateforms were erected wherever she went to address the people and a large number of police force was deployed. Not only this, thousands of rupees were spent on the repairs of dak-bunglows where she stayed for some time, for lunch or rest. The Congress President, Shri Nijalingappa expressed surprise when a bill for Rs. 3 lakhs was submitted to him and he said it appears that the Bihar Government is not having funds for this purpose. According to the Press, lakhs of rupees were collected during the elections for the Congress party. In this connection I would like to quote a news item which appeard in the 'Hindustan Times' dated the 23rd January and it reads : "Shri Nijalingappa also discussed with Mrs. Gandhi the question of funds for the election. The Prime Minister has been able to secure contributions totalling more than Rs. 10 lakhs for the A. I. C. C. so far, the A. I. C. C. has collected nearly Rs. 20 lakhs. Mrs. Gandhi has reportedly assured Mr. Nijalingappa that she would get at least another Rs. 5 lakhs for the Party."

The news has not been refuted. If this money was for the Congress party, it could well be given to either the Party President or the Treasurer. The question is how Mrs. Gandhi secured these contributions ? Was it a secret donation ? After all who are the parties to contribute these funds ? The Prime Minister who is answerable to the Parliament and the people of the country should make a categorical statement so as to make the position clear. The question is whether the donators asked for anything in return for what they have contributed ? Capitalism is vitiating politics and damaging the healthy conventions of Democracy and is also contaminating the purities of Democracy by misusing the administrative set-up of the country.

The planks of our foreign policy are not based on self-respect, independent thinking, self-dignity and principles of a free nation as we are. Today our foreign policy is guided by Russia and they are exerting their pressure on our Government to follow their dictates in the matter of foreign policy. It has lowered the prestige of the country. Self-respecting and sovereign Indian people will not tolerate the pussillanimous and appeasing foreign policy of the Government. We do not want them to be guided by any foreign powers, small or big.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : A few days back, the brisk convassing for the mid-term-elections was going on, a prominent S. S. P. Member, Shri Madhu Limaye who is a member of the House also, condemned Communist Party and appealed to the voters, while addressing a public meeting at Patna, not to vote for that party as they were traitors. But to my utter surprise and just immediately after one month, the same Hon. Member and his party have supported this Communist sponsored No-confidence Motion, and now they place a rediculous demand that the Congress should abdicate power for the C P I have secured an overwhelming majority in West Bengal Legislative Assembly. If they want to make out a plausible plea of what they are demanding, I would ask all the parties other than the C P I which has secured a majority in West Bengal, to resign their seats here as they have badly lost in all the states. To quote Bengal as an example of the Congress's debacle is not fair on their part when they themselves have suffered debales and heavy blows during these mid-term-polls.

The C. P. I. has become very proud of their achievement in West Bengal today. But just before the elections, the C P I and C P I (M) were vehemently opposing each other and now they have again joined their hands to form Government there. The people of that State have

now given them an opportunity to rule them. But I am sure that the people of West Bengal will certainly revise their verdict tomorrow. No doubt, their emergence may pose a threat to our party. But what would happen if it poses a threat to the whole country ? We have our Constitution and we have to abide by it. Parties will come and parties will go. There is nothing new and wrong in it.

Hon. Member, Shri A. B. Vajpayee knows very well that he cannot support the fundamental ideologies of the members who have tabled this No-confidence Motion. He knows this fact also that corrupt practices are resorted to during the elections to malign other parties and also to influence the electorate, with the result that we are spoiling our political conventions. We are not proud of our performance and I confess that we have committed mistakes. But we are certainly proud of one thing—the Congress was never in the grip of communalism, casteism, classism and parochalism. We have never been a victim of any ism. We have always followed the legacy and healthy conventions of our predecessors and we follow the line of constructive approach and believe in democracy and secularism. We enjoy the liberty even to criticise our own party if it commits any mistake and our party revises its policies if the public opinion demands the same. But other parties hardly enjoy any such liberty.

The mover of the Motion has charged the Congress with encouraging the Shiv Seva movement in Bombay. I refute this charge for the opposition is taking undue advantage of the situation and Congress Party is itself suffering loss and is growing weaker as a result of activities of Shiv Sena. So how can we encourage their activities when we have to suffer for that ? This is a baseless and unfounded charge. The opposition itself is responsible for the present sorry state of affairs, because they go there and raise communal and parochial slogans in the area and create tensions among people which ultimately breaks out in violence. The Congress always believes in and preaches healthy and constructive national approach, we have always been appealing to certain political parties not to encourage and engineer communal and parochial approach and fissiparous tendencies.

Narrating some incidents that took place in Maharashtra, Shri Jyotirmoy Basu put a blame on the Congress and held it responsible for that. But I would like to ask him who is responsible for what happened in Tanjore, where 42 Harijans were burnt alive and where D. M. K. is in power.

I ask him why did they not table a No-Confidence Motion against the D. M. K. Government in Madras ?

In West Bengal, as many as 636 factories had been closed down during the rule of the United Front there rendering a large number of workers jobless. Secondly. the employment percentage in that state in 1968 has fallen by 5 percent as compared to 1966 with the result that at least 25 lakh youths have been deprived of employment opportunities.

Now coming to Orissa, the only achievement made by the Government of Orissa is that they have raised the number of Government officials from 1.67 lakhs in 1966-67 to 1.83 lakhs during 1968-69 so far. And according to official break-ups confirmed by that Government, out of two houses, the income of one house is less than Rs. 50. So it is for the hon. members to judge what they have achieved during their rule.

Today the country is passing through a political crisis. There are various problems we are faced with. There are agitations, communal disturbances, unemployment problem, students' unrest, strikes, etc. There are national problems and we should adopt a national outlook to solve them. We have to deal with various issues which lead to differences and we have to resolve them. I would, therefore, appeal to all the political parties to adopt a national approach and find out the root causes of these agitations, disturbances, etc. and strike at their roots rather than quelling or encouraging them with the force at our command.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, during the course of this debate on No-Confidence Motion, a lot has been said about what happened in Bombay as a result of the activities of Shiv Sena there. There was also a lot of discussion on how far the Government or the Congress party and the police have discharged their duties during these disturbances in that city when according to official figures 25 persons were killed as a result of the police firing and property worth Rs. 25 crores was destroyed.

The behaviour of the local police officers in Bombay had been very very offending. When we were driving to Bandra we found a dozen of police officers standing on the roadside. We stopped and inquired whether the road was clear to lead us to Bandra. They informed us that we could go on as long as we desired without any hitch. But we had covered hardly 50 yards when we found the people burning motor vehicles. We immediately drove back and on seeing us back the police officers laughed at us and put some remarks. We complained about it to the Congress people and Mr. S. K. Patil, but they also pleaded for the police officials saying "what else can they do? They have already killed 58 people."

But the fact is that only poor and innocent people have been killed, not even a single gunda. This is what has been prevailing in Bombay.

About a year back, it was said that Shiv Sena of Bombay was being financed by big businessmen in the country. So why do not you use your CIB or CBI to find out the businessmen who finance this Shiv Sena, and whether those business concerns give this money to the Shiv Sena out of their accounts in India or outside India? You should find out how the Shiv Sena gets money.

It is of no use to discuss who has established this Shiv Sena but it is beyond any doubt that it has been being used against non-Congress parties since October 1966. This Sena worked against Shri George Fernandes also when he was fighting election against Shri S. K. Patil. In this connection I quote the words of Shri G. N. Acharya who is a well-known journalist-friend of Shri Chavan. In his article he wrote—

"It was not however, till the night of October 30, that the Sena impinged on the public mind. At a rally at Shivaji Park, the venom and vitriol that was poured out was directed against non-Maharashtrians—including the Chief Justice of the Bombay High Court, who was then classified as a non-Maharashtrian..... But the principal target was Sri George Fernandes who, by then, had pitted himself against Sri S. K. Patil and was vigorously canvassing for his own election to the Lok Sabha.

At the end of the meeting some of the more inflamed members of the crowd stoned Udipi hotels. The slogans they shouted were : "Madrashana Haklun Lava," (drive out the Madrasis)

and "Idli Sambhar Bandh Kara" (stop Idli-Sambhar). Nothing more droll could be imagined by way of political slogans to inspire the rank and file of a new and rising party.

It soon became apparent however, that the Shiv Sena's principal concern in that election was to secure the defeat of Sri Krishna Menon. A plethora of claims and counter-claims, statements and contradictions have been made on this issue. But there is no doubt that the Sena's aid was requisitioned for the election of the late Sri S. G. Barve. Chief Thackaray has asserted that but for the Sena's campaign Sri Barve would not have been elected. From my own observation, I find it easy to accept this claim.

After the death of Shri Barve, Shri S. K. Patil produced Smt. Tara Sapre as a Congress candidate, as a magician produces a rabbit out of his hat. She does not seem to have had any political interest ; and the only public work that she had ever done was on behalf of the R.S.S. Once again the Sena was summoned to the rescue, and it did a successful job."

So it is needless to prove who has been using the Shiv Sena for the last five years. It was only last year that the Shiv Sena contested elections against Congress ; and only on this plea the Congressmen say that they have no connections with the Shiv Sena. But we should not forget that "..... at the first Municipal Congress Party meeting (March 28, last year) after the recent election, Shri Patil hailed the Sena and told its leader that he need not call himself an opposition."

After that the P.S.P. joined hands with the Shiv Sena which they are still continuing. I do not want to say anything, about the ideas, policies and programmes of the P.S.P. but about the Leftist and Rightist Communist Parties, the Shiv Sena Chief Shri Bal Thackrey says—"Both are rascals. Both are crooks."

Then referring to Shri Y. B. Chavan, he says—"While the Shiv Sena leader was confident of keeping Communists in check in Bombay, his suggestion for action at the national level was—"Ban the Leftists parties."

Then Shri Bal Thackrey has written that when Shri Chavan was asked whether he included the S.S.P. and P.S.P. also, Shri Chavan replied—"I am not discussing those buffoons now."

My own party has also been victim of this Shiv Sena. We were throned and hurt.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Thus, on one hand these people join hands with such elements and on the other hand they hold National Integration Conference and issue big declarations in regard to national integration. My party did not join this Conference. We believe that until the elements which indulge in subversive and violent activities whether that of creating communal riots, or enemity between North and South or territorial disputes ; are stopped fully, we cannot achieve national integration.

Let Shri Piloo Moody know that after the Congress, it is the Swatantra Party who have been encouraging the Shiv Sena for the last two and a half years. Shri Madhu Mehta, in a seminar, declared in his very first words that "if the Shiv Sena was meant to finish all the huts

in Bombay, I also consider myself to be a Shiv Senik" Similarly, the Joint Secretary of Bombay and a member of Shri Mody's party Nana Choorisaman has been publicly appreciating the praise of Shiv Sena in America. And there are many examples alike.

Thus there remains no doubt as to who are on the back of the Shiv Sena.

Yesterday, several Hon. Members blamed Shri S. M. Joshi and Shri S. A. Dange for creating boundary disputes by setting up a Samyukta Maharashtra Samiti in regard to Belgaum. Why don't they blame Mahatma Gandhi also who iniated the setting up of States on linguistic basis ?

It is useless to discuss whether there are boundary disputes or not. Those are there and have to be solved. The Mahajan Commission, appointed by the Prime Minister was meaningless. It is the result of a conspiracy between the Prime Minister and Shri P. Vasantrao Naik. The result is that the Belgaum problem is still there. All the new difficulties or obstructions in regard to the settlement of this issue are the creation of Shiv Sena and the powers who are on its back and who are determined to uproot the labour unions of Bombay and also to finish Socialist and Leftists Communist Powers. They are against all non-Maharashtrians.

The situation in Bombay is pitiable. Out of 53 lakhs of people there 34 lakhs are homeless. The Congress Government of Shri V. R. Naik is selling plot @Rs. 9,000 per sq. yard. How will then they give houses to the poor labourers ? The housing problem cannot be solved that way. Besides this, there is unemployment everywhere in the States of this country. About 25 lakhs young men more will come to you in the next June after passing their High School and Degree Examinations.

Our Prime Minister went on a country-wide election tour. She delivered a lot of meaningless speeches, but spoke nothing about policies. She criticised all opposition parties but did not give a word of consolation in regard to unemployment.

So if they say that the problems of unemployment in Bombay could be solved only by extricating non-Maharashtrians from there, no body will believe this declaration of the Shiv Sena. The Shiv Sena itself is not sure whether these proplems of the Maharashtrians in Bombay could be solved. Their movement is meant only to disintegrate the labour union and their movements so that the capitalists and profiteers prosper in Bombay and the daring public-movement, the revolutionary public movement may be crushed. It is only their aim and we have to face it.

I am not prepared to accept this thing that Shiv Sena is responsible for all these things. I think that Congress is more responsible than Shiv Sena because it was Congress who had spread these diseases during the last twenty-two years. By looking at the figures of different States we find that there is a lot of disparity in them. During the last three Five Year Plans and two annual plans the **per capita** amount spent in Bihar for development purposes was only Rs. 168 whereas in Uttar Pradesh it was Rs. 172, in Gujarat Rs. 313, in West Bengal Rs. 234, in Punjab Rs. 366, in Mysore Rs. 268, in Maharashtra Rs. 264 and in Rajasthan Rs. 242. Similarly by looking at the figures of Central assistance we find that there is a big difference in them. The per capita Central assistance for Punjab was Rs. 231, in Bengal Rs. 130, in Rajasthan Rs. 185, in Assam Rs. 182, in Bihar Rs. 99 and in Uttar Pradesh Rs. 102. I

have given these figures in order to find out as to where the root of this disease lies. By going through the whole matter we find that the wrong policies of the Government have been responsible for all these troubles. So, I am of the view that unless and until these policies are amended this matter cannot be set right. But the Congress Party does not want any non-Congress party to flourish to a great extent in the country.

We have been compelled to give this motion of non-confidence because of the happenings of Bombay and Telengana and all th at has happened during election in these four States. During these elections we have seen that wherever there was pressure of the opposition parties that was crushed by the Congress. It was also said that S. S. P. has no policy of their own and they have not chalked out any programme. On this point I would like to challenge even the Prime Minister. We are prepared to discuss our programme at any place.

Before I close I would like to say one thing more. The Congress has lost a seat of Phoolpur also. Hence they should learn a lesson now and make amendments in their policies, so that democracy may be saved in our country.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव पर पिछले दो दिनों से चर्चा चल रही है परन्तु मुझे सभा के सामने तथ्य रखने के लिये हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। गत छः अथवा आठ घंटे से भाषण सुनने से मैं यह समझ पाया हूं कि दो तीन बातों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। पहली बात यह कही गई है कि जो कुछ बम्बई में हुआ है वह शिव सेना की गतिविधियों के कारण हुआ है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है मैं आरम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं कि वहां जो कुछ हुआ है मैं उससे बहुत शरमिन्दा हूं परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि इस समस्या का जो विश्लेषण कुछ सदस्यों ने किया है उससे हम इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि शिव सेना एक उग्रवादी जमायत है तथा उसने बम्बई में कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के अल्हड़पन का नाजायज फायदा उठाया है। मुझे पता चला है कि उप-चुनावों और आम चुनावों में शिवसेना के लोग कांग्रेस में घुसकर कांग्रेसी उम्मीदवार का प्रचार करने लग गये थे। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि उन्होंने कांग्रेस के लिये कुछ करना था। इससे उन्होंने स्वतंत्र दल के लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयत्न किया था। सभी लोगों को मालूम होगा कि बम्बई में स्वतंत्र दल के कुछ प्रसिद्ध कार्य कर्त्ता शिव सेना के साथ खुले आम सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। मुझे यह भी मालूम है कि बम्बई के कुछ अग्रणीय व्यापारी खुले आम शिव सेना का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि शिव सेना साम्यवाद का मुकाबला कर सकती है।

दूसरी बात करनाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा सम्बन्धी समस्या के बारे में कही गई थी। यह एक महत्वपूर्ण मामला है तथा राजनीतिक दलों ने इस समस्या का अब लाभ उठाना आरम्भ कर दिया है। मेरा आगे निवेदन यह है कि यदि वे दल जो अब शिव सेना का विरोध कर रहे हैं उन्हें यह मालूम हो जाये कि इस मामले का कांग्रेस के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है तो वे सम्भवतया आपस में मिल जाने को तैयार हो जायेंगे। अतः मैं समझता हूं कि शिव सेना प्रादेशिक भावना का शोषण करने के लिये ही बनाई गई थी। इसलिये मेरा निवेदन यह है

कि हमें इस समस्या पर गहराई से विचार करना चाहिये। मेरा एक और निवेदन यह भी है कि जब तक सभी राजनीतिक और लोकतंत्रीय दल इस बात से सहमत नहीं हो जाते कि ऐसी सभी समस्याओं पर जैसे भाषा की समस्या, साम्प्रदायिकता की समस्या, प्रादेशिक समस्या आदि, जो हमारे समाज में चिरकाल से है, किन्हीं भी परिस्थितियों में बाजार में विचार नहीं किया जाना चाहिये तब तक हम कोई आशा नहीं बांध सकते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर हम अकेले नहीं बल्कि सब मिलकर विचार कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं यह एक कठिन समस्या है क्योंकि हमें यह भी देखना है कि मैसूर और महाराष्ट्र के लोग भी हमारे साथ रहें। हम सबको यह तो पता ही है कि लगभग सभी राजनीतिक दल इस समस्या पर एक मत नहीं होते हैं। इसलिए इस समस्या का हल समूचे राष्ट्र को शान्ति से बैठकर निकालना चाहिये क्योंकि एक दूसरे दल की निन्दा करने से कोई हल नहीं निकल सकता।

अब मैं फिर शिव सेना के बारे में सही-सही स्थिति बताना चाहता हूं। जहां तक शिव सेना का सम्बन्ध है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति ने 1967 में उसके बारे में अपना अनुमान प्रकाशित कर दिया था। उसमें यह लिखा हुआ था कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारी समिति शिव सेना की गतिविधियों की निन्दा करती है जिसने ग्रेटर बम्बई में रहने वाले लोगों के कुछ भागों में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों के लोगों में अशान्ति की भावना पैदा कर दी है। उसमें यह भी घोषणा की गई है कि हम जात-पात का ध्यान न करते हुए भारत के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी भारतीय का समान अधिकार है इस बात पर विश्वास रखते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि हम महाराष्ट्र के किसी भी भाग में आकर बस जाने वाले सभी भाषा-भाषी लोगों को बढ़ने का हर सम्भव अवसर देने को तैयार हैं तथा इसमें यह भी आश्वासन दिया गया है कि उन लोगों का महाराष्ट्र के साथ उतना ही सम्बन्ध है जितना मराठी भाषी लोगों का है तथा उन्हें राज्य की ओर से पूरा-पूरा संरक्षण दिया जायेगा। यह शिव सेना के बारे में अनुमान लगाया गया था तथा यह घोषणा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से की गई थी।

शिव सेना के बारे में मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। श्री राममूर्ति ने कल श्री बसन्तराव नायक के भाषण का कुछ भाग पढ़ा था मैंने कल उनके साथ बातचीत भी की थी ताकि मुझे सारी चीज का सही-सही पता लग जाये। जब वह मुख्य मंत्री थे तब वे उस राज्य के सूचना मंत्री भी थे और उन्होंने लोकवार्ता सम्मेलन के बारे में हुए समारोह में भाग लिया था तथा उस समारोह में आरम्भिक समारोह भी हुआ था। यह समारोह 1966 में हुआ था जब शिव सेना अभी नई शक्ल में बनी भी नहीं थी। उस समय किसी को पता भी नहीं था कि यह बाद में शिव सेना का रूप धारण कर लेगी। उस अवसर पर श्री नायक ने सभा का सभापतित्व किया था। श्री राममूर्ति ने उनके भाषण का उद्धरण किया है तथा इसके साथ ही साथ यह भी कहा है कि यदि आप कोई चीज विषय के बाहर कहेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। मुख्य मंत्री होने के नाते उन्हें हर प्रकार की बैठकों में जाना होता है। इसलिये उन्हें यह कहना

उचित नहीं है कि वह शिव सेना आन्दोलन के लिये उत्तरदायी हैं। यह भी कहा गया था कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान भी उस समारोह में गये थे। मैंने उनकी स्थिति दूसरे सदन में स्पष्ट कर दी है। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि समारोह में भाग लेना शिव सेना का समर्थन करना है।

अब मैं इस महीने में हुई घटनाओं पर आता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इस बात का पहले अनुमान न लगा सकी कि आगे क्या होने वाला है। शायद उनका अनुमान इसलिये गलत निकला क्योंकि वे शिव सेना का नहीं बल्कि सीमा विवाद के मसले को हल करने का प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु जब उन्होंने देखा कि चीजें उपद्रवी रूप धारण कर रही हैं तो उन्होंने बड़ी मजबूती से काम लिया। बम्बई जैसे शहर में जब ऐसी चीजें फैल जाती हैं तो उन पर काबू पाना कठिन हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि वे इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। जहां तक शिव सेना के बारे में मेरे विचार करने का सम्बन्ध है उसके बारे में न तो मुझे पहले कभी कोई सन्देह हुआ था और न ही उन पर है। मैं अकेला ही अभागा पुरुष हूं जिसे बम्बई में शिव सेना की ओर से तथा शिव सेना के कारण संसद् में लताड़ पड़ती है।

जहां तक तेलंगाना का सम्बन्ध है ये समस्यायें 1956 में हुए राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न हुई हैं। मैं समझता हूं कि हर राज्य में अपनी-अपनी प्रादेशिक समस्यायें हैं, मैं समझता हूं कि सभी राज्यों में राजनीतिक मामलों के साथ-साथ प्रादेशिक संतुलन और असंतुलन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। तेलंगाना और आंध्र के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो गई थी जिसका गलत लोगों ने लाभ उठाया और आंध्र प्रदेश को नुकसान हो गया। जब मुख्य मंत्री ने यह देखा तो उन्होंने सारी बात पर ध्यान देकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया और उनके साथ समझौते किये। मुझे आशा है कि उनका पालन किया जायेगा।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है हम तत्सम्बन्धी विधेयक में संशोधन कर रहे हैं। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग एक ही राज्य में रहें तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखें।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है हमने उनके साथ पत्र-व्यवहार किया है। जहां पर सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता समझी गई हमने वहां वह दिखाई।

मैं समझता हूं कि अन्य मामलों का मुझे उल्लेख नहीं करना चाहिए। हारा हुआ व्यक्ति तो सम्भवतः अपना मानसिक संतुलन खो सकता है परन्तु विजयी होने वाले को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि वह जीत गये हैं, तथा मेरी इच्छा है कि वे सब संगठित रहें। उनमें संविधान के प्रति आस्था रहे तथा वे भारतीय राष्ट्र की शक्ति बनें।

वास्तव में वर्ष 1967 के चुनावों तथा मध्यावधि चुनावों का विश्लेषण अभी नहीं किया जा सकता परन्तु यह मैं जानता हूं कांग्रेस दल अब ऐसा नहीं रहा जैसा कि पहले था। इसे कभी

असफलता मिली तो कभी सफलता। यहां तो यह एक आदत सी बन गई है कि प्रत्येक व्यक्ति यही पूछने लगता है—"22 वर्षों में आपने क्या किया ?" बार-बार इस प्रश्न को दोहराने का क्या लाभ है ? ठीक है कि पिछले बाईस वर्षों से शासन हमारे हाथ में है परन्तु विपक्षी दल तो 22 मास तक भी शासन नहीं सम्भाल सके।

न जाने अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव परिणामों पर क्यों इतने खुश हैं जबकि उन्हें चरण सिंह के चरण छूने पड़े हैं। गद्दी के लिये हम तो किसी के सामने नीचे नहीं होते।

कुछ मित्र यह कहकर संतोष करते हैं कि कांग्रेस को उतने ही प्रतिशत मत मिले हैं। परन्तु वह यह तो सोचें कि उन्हें कितने प्रतिशत मत मिले हैं।

दक्षिणपन्थी साम्यवादी न जाने क्यों इतने खुश हैं और श्री ही० ना० मुकर्जी क्यों इतना बढ़-बढ़ कर बोल रहे हैं। मैं उन्हें और अन्य राजनैतिक दलों को चेतावनी देता हूं कि कुछ वर्षों के बाद वे यही इस सभा में आकर पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने अन्य दलों के साथ क्यों गठजोड़ किया। मैं यह राजनैतिक भविष्यवाणी करता हूं कि जो राजनैतिक दल आज मार्क्सवादी साम्यवादी दल के साथ मिल कर खुश हो रहे हैं कुछ वर्षों बाद वे स्वयं को "संयुक्त मोर्चे" का बन्दी पायेंगे। हालांकि इस भविष्यवाणी के साथ होने से मुझे दुःख होगा परन्तु फिर भी मैं समझता हूं मैंने ठीक कहा है।

परन्तु मैं यह नहीं समझता कि वे लोग बंगाल में जीते हैं और अविश्वास-प्रस्ताव यहां की सरकार के विरुद्ध पेश कर रहे हैं। वे बंगाल में शासन चलायें।

आज भारत की राजनीतिक स्थिति परिवर्तनशील है और हर राजनैतिक दल अपना-अपना दृष्टिकोण जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा है। इस सन्दर्भ में राजनैतिक दल समझदार हों अथवा न हों परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि भारत के लोग समझदार हैं और मुझे इस पर गर्व है। दल आते हैं चले जाते हैं; वे अच्छे और बुरे भी सिद्ध होते हैं, परन्तु विजय जनता के मत की ही होती है। आज हमारी सरकार बनी है क्योंकि लोग हमारे साथ हैं और हमारी यह सरकार तब तक बनी रहेगी जब तक लोग हमारे साथ हैं। अतः विपक्षी लोग चाहे जितने अविश्वास प्रस्ताव रखें परन्तु वे लोगों को नहीं बदल सकते।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं अपने उन सहयोगियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस चर्चा को इस स्तर तक उठाया है। इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों के भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। गृह-कार्य मंत्री भी आज बहुत अच्छे मूड में हैं तथा यदि हम उन्हें असफल करना चाहते हैं तो यही सर्वोत्तम होगा कि हम इन्हें यहां अकेला छोड़ जायें।

सर्व प्रथम तो मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के पेश करने के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले इस सम्बन्ध में मेरे दल के दृष्टिकोण के कारण नाराज हैं मैं

समझता हूं कि संसदीय ढांचे में यह साधन बड़ा ही गम्भीर शस्त्र है और इसीलिये इसका उपयोग बड़ी सावधानी, तैयारी तथा होशियारी से करना चाहिए। हमें यह प्रस्ताव उस समय पेश करना चाहिये था जबकि विपक्ष से सभी मत हमें मिलते तथा फिर यह प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जाता है। मेरा विचार है कि जब हम आक्रमण करें तो पूरी तैयारी से करें, पूरी शक्ति से करें सभी सम्भव प्रयत्नों से करें।

इस चर्चा को चलाने का मुख्य आधार देश के विभिन्न भागों, विशिष्ट रूप से बम्बई में हुई हिंसात्मक घटनायें हैं। इस बारे में कुछ कहने से पूर्व मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा।

प्रधान मंत्री अपने चुनाव-दौरों में जहां भी गईं वहां उन्होंने लोगों से यही कहा कि यदि आप स्थायी सरकार चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दें। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया। परन्तु यह स्थायित्व कैसा है? यह स्थायी सरकार तो स्थायी रूप से लोगों को निराशा दे सकती है उनके रहने के स्तर को स्थायी रूप से नीचे रख सकती है।

दूसरी बात मैं गृह-कार्य मंत्री के लिये कहूंगा जोकि यहां नहीं बैठे हैं। पिछले वर्ष सभा ने मेरे इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी कि किसी राज्य के राज्यपाल को केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के लिये एजेन्ट का कार्य नहीं करना चाहिए प्रत्युत संविधान को लागू करने तथा उसकी रक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिये। परन्तु जब वह प्रस्ताव चर्चा के लिये यहां आया था तो श्री डान्डेकर ने भारत सरकार को भ्रम में डाला तथा पश्चिम बंगाल की सरकार का पतन कराने में भाग लिया। यदि केन्द्र सरकार जल्दबाजी न करती तो स्थिति कुछ भिन्न ही होती। यह दुःख की बात है कि राजनैतिक प्रश्नों पर सिविल अधिकारियों का निर्णय लागू किया जाता है। श्री धर्मवीर बड़े प्रतिभाशाली तथा सचरित्र व्यक्ति होंगे परन्तु यह कि किसी राज्य सरकार के भाग्य का निर्णय सदन में हो, अध्यक्ष के कमरे में हो अथवा कि राज्यपाल के घर में हो इसका निश्चय एक भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी नहीं कर सकता (**व्यवधान**)।

मैंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। पश्चिम बंगाल अपनी सर्वविदित बहादुरी और देशभक्ति को नहीं भूला है। प्रत्येक बंगाली में देशभक्ति कूट-कूट कर भरी है। परन्तु यहां प्रकट हुआ लोगों का मत किसी वामपन्थी अथवा दक्षिणपन्थी या किसी जाति भेद के पक्ष में नहीं है बल्कि उन्होंने अपना मत उन नीतियों के विरुद्ध प्रकट किया है जिन्हें केन्द्र सरकार वहां चला रही है। ये परिणाम इस बात का प्रतीक हैं कि वहां के लोग केन्द्र सरकार द्वारा उस राज्य के मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करते है। अतः क्या सरकार ऐसी नीतियों को त्यागने का प्रयत्न करेगी? इससे यही परिणाम निकलता है कि किसी राज्य की सरकार का भाग्य वहां के लोग ही निश्चित करते हैं, केन्द्रीय सरकार, राज्यपाल अथवा सभा-अध्यक्ष नहीं।

मेरा विश्वास था कि हमारा देश एक समान प्रकार की सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक परम्पराओं के एक सूत्र में बंधा हुआ है परन्तु बंगाल का दौरा करते समय मुझे यह कष्टप्रद अनुभव हुआ कि हम लोग तो वास्तव में समान रूप से पिछड़ेपन, शोषण, निराशा और निरुत्साह

की रेशमी डोरियों में जकड़े हुए हैं। केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक लोग समान रूप से पिछड़े हुए, निर्धन और हतोत्साह हैं।

अब, सरकार इस बात पर विचार करे कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सरकार ने क्या अच्छा किया? उनके परिवारों का शोषण हुआ। परिणाम-स्वरूप पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल को उसका मूल्य चुकाना पड़ा। इन बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यद्यपि अब प्रधान मंत्री ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का भार छोड़ दिया है तथापि मूल रूप से वह उसकी नीतियों के लिये उत्तरदायी हैं। राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में उन्होंने संसार के सबसे बड़े राष्ट्रमण्डल देश का प्रतिनिधित्व किया था। वहां केवल वही महिला प्रतिनिधि थीं। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रधान मन्त्री को यथोचित सम्मान नहीं दिया। एक चित्र में उन्हें पुरस्कार लेने वाली एक साधारण स्कूली छात्रा के भांति इग्लैंड की महारानी के पीछे शर्माती हुई सी खड़ी दिखाया गया है जबकि उनका उचित स्थान सामने की ओर होना चाहिए था। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इससे भारत को हीन स्थिति की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है। इंग्लैंड में महिलाओं के प्रति बड़ा आदर प्रकट किया जाता है। परन्तु उस चित्र में हमारे प्रधान मंत्री को पिछली पंक्ति में स्थान दिया गया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत के प्रधान मंत्री राष्ट्रमण्डल बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। परन्तु वे लोग उचित सम्मान भी नहीं प्रदर्शित करते। हमें राष्ट्रमण्डल छोड़ देना चाहिए।

बम्बई और तेलंगाना की चर्चा करने से पूर्व मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। डा० जाकिर हुसैन, हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में एक अत्यन्त सज्जन और विद्वान व्यक्ति हैं। यद्यपि हमने उनके चुनाव का विरोध किया था परन्तु हम उनका बहुत ही आदर करते हैं तथा उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि अत्यन्त पुरानी बादशाही परम्परा का प्रतीक बना एक अलग झण्डा राष्ट्रपति भवन पर क्यों लहराता है। हम ब्रिटेन की इतनी नकल क्यों कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पास तो वही हमारा अशोक चक्र वाला तिरंगा होना चाहिए। हम राष्ट्रपति के प्रति कोई अनादर का भाव प्रकट नहीं कर रहे परन्तु उनके सलाहकारों को इस बारे में विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति का झण्डा हमारे राष्ट्र-ध्वज से भिन्न नहीं होना चाहिए।

देश में फैले हिंसा के वातावरण के बारे में केवल मैं ही नहीं अनेक लोग चिन्तित हैं। तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश में हमने हृदय विदारक प्रदर्शन देखे। मुंगेर में लोगों ने लड़ते समय पटाखे, बन्दूकें, चाकू और तलवारें इस्तेमाल कीं। तमिलनाडू में भी ऐसा हुआ। जब देश के लोग ऐसी हिंसा के शिकार हैं तो हमें विचारना चाहिए कि इस सम्बन्ध में त्रुटि कहां है।

हिंसात्मक वातावरण की यह समस्या अन्य देशों में भी है परन्तु इस समस्या के बारे में ऐसी नीतियां नहीं चलाई जातीं जैसी कि भारत सरकार चला रही है। पिछले दो वर्षों में

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नीग्रों लोगों को नागरिक अधिकार दिये जाने के बारे में हिंसा की घटनायें हुई । वहां के राष्ट्रपति ने तुरन्त इस सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त कर दिया । उस आयोग ने जो ठोस रिपोर्ट दी है उसका दिग्दर्शन हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा ।

परन्तु हिंसा के कारण क्या हैं ? लोग परस्पर क्यों लड़ते हैं ? महाराष्ट्र में तथाकथित महाराष्ट्रियों ने गैर-महाराष्ट्रियों पर आक्रमण किया । यह बड़े शर्म की बात है तथा इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाता है । हमें इनके कारणों को जानना तथा दूर करना है । मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ हुआ वह ठीक था । हम तो हिंसा के किसी भी कार्य की निन्दा करते हैं ।

परन्तु क्या निन्दा करने से ही यह हिंसा समाप्त हो जायेगी ? पिछले 20 वर्षों से हम हिंसा की निन्दा करते आ रहे हैं । परन्तु इससे क्या यह समाप्त अथवा कम हुई है ? हम सच्चे दिल से इस पर विचार करके देखें ।

बम्बई जैसे महानगर में हिंसा का भयंकर वातवरण उत्पन्न हुआ । हमें इसका अनुभव हुआ । हम अपनी कार में जा रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी रुकी और हमने देखा कि एक नवयुवक हमारी गाड़ी पर एक भारी चट्टान लुढ़काने जा रहा था । उसे किसी प्रकार रोक कर जब हमने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके और उसके साथियों के घरों को आग लगा दी गई । उसके अनेक साथी को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया है और वह बदला लेना चाहता है । उसने कहा कि वह किसी को नहीं छोड़ेगा । परन्तु जब मैंने पूछा कि अन्य लोगों को मार कर अथवा उन पर आक्रमण करके वह कैसे अपना घर और अपने मृत साथी पा सकता है तो वह कोई उत्तर न दे सका ।

मैं पुलिस आयुक्त, इन्स्पैक्टर जनरल तथा मुख्य मंत्री से मिला और कहा कि हिंसा की निन्दा करने वाला कोई वक्तव्य प्रसारित कर देने से हिंसा नहीं रुकेगी । हमें वहां चल कर लोगों को समझाना चाहिये । परन्तु पुलिस आयुक्त ने बताया कि वहां जाना खतरनाक है तथा यदि आप जायें तो अपने साथ कुछ शस्त्र आदि ले जायें । मैंने कहा कि यदि लोगों के सामने बोलने हेतु हमें रक्षा के लिये यदि हथियारों की आवश्यकता आ पड़ी है तो फिर तो सार्वजनिक सेवा से अलग हो जाना होगा ।

इसके बाद हम वहां गये तथा लोगों के समक्ष मैंने बाहर बैठकों में भाषण दिये । मैंने उनसे कहा कि यदि वे बम्बई को अपनी राजधानी मानते हैं तो फिर उसे लुटता हुआ देख कर वहां लोगों को त्रस्त देख कर कैसे चुप बैठ सकते हैं । क्या ऐसा कहना कोई अपराध है ? हिंसा करने के लिये मैंने उनकी निन्दा की और ऐसा करना भी अपराध नहीं है ।

इसके बाद फिर दूसरी सभा में व्यंग्य-बाण छोड़े गये । परन्तु ज्योंही इसका समाचार मिला, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने विशिष्ट रूप से इसकी निन्दा की तथा शिव सेना के

नेताओं को इस हिंसा, लूट और डाकाजनी के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। क्या उन्होंने यह गलत किया ? मैंने कहा था कि हमें इस बारे में गहराई से विचार करना चाहिये और ऐसे उपाय करने चाहिये कि ऐसी घटनायें कलकत्ता, कोइम्बटूर, मुंगेर अथवा बम्बई में न हों। यह कह कर मैंने क्या गलती की ? हमने कौन सा पाप किया ?

बम्बई में नेतृत्व बिलकुल समाप्त हो गया है। प्रशासन, सरकार पुलिस अथवा राजनैतिक नेता सभी असफल हैं। इन सभी नेताओं को इकट्ठे होकर वहां जाना चाहिये था तथा कहना चाहिये था कि बम्बई में सब लोग रहेंगे वह किसी एक दल अथवा समुदाय का नगर नहीं है। भारत का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी स्थान पर जा सकता है, वहां रह सकता है। हमने यही बात कही थी। और यह बात इन पृष्ठों में भी है।

यह बड़े खेद की बात है कि महात्मा बुद्ध, अशोक, गांधी के इस देश में, गांधी शताब्दी के दौरान भी ऐसी हिंसा की घटनायें घटीं। तेलंगाना में आंध्र का व्यक्ति आंध्र के ही व्यक्ति से भिड़ गया। लोग जीवित ही दफन कर दिये गये। लोगों के कपड़े फाड़ कर उन्हें नंगा कर दिया गया। यहां किसी भाषा अथवा क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। कुछ और ही गहरी बात हैं। इसका मूल-कारण यह है कि हमारे देश में नेतृत्व बिल्कुल समाप्त हो गया है।

ये चित्र देखिये। मैं एक-एक करके भेज रहा हूं। ऐसे चित्र कभी श्री म० ला० सोंधी भी इन्द्रप्रस्थ की घटना के बारे में लाये थे। चित्रों में देखिये। हर बिल्डिंग की ओर बन्दूक तनी है वहां खड़े लोगों पर निशानें जमा रखे हैं। शरारत करने वाले लोग चालाक होते हैं। वे उपद्रव उत्पन्न करके भाग जाते हैं परन्तु बाद में अभागे लड़के लड़कियां मारे जाते हैं। यह मैंने स्वयं अपनी आखों से देखा। झाबावादी में मेरे पहुंचने से पूर्व एक स्कूल छात्र छज्जे में खड़ा था और उसे गोली मारी गई। वह पत्थर फेंकने के लिये शायद वहां नहीं खड़ा था। परन्तु पुलिस यह नहीं देखती कि दोषी कौन है। वे आवेश में आकर कार्यवाही करते हैं और हिंसा आरम्भ हो जाती है।

गम्भीर समस्याओं के हल करने में विलम्ब करना इस सरकार की आदत है। यह सरकार कोई कार्यवाही तभी करती है, जबकि लोगों का असंतोष तथा रोष प्रकट हो जाता है। हमारे सामने अन्तर्राज्यीय समस्यायें हैं तथा अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद हैं। सरकार का यह कर्त्तव्य था कि उनके हल करने के लिए गम्भीर प्रयत्न करे तथा उन्हें शीघ्रातिशीघ्र हल करे। यदि सरकार उन समस्यायों को हल करने में असमर्थ है तो उसे घोषणा कर देनी चाहिये कि वह इस देश पर राज करने में असमर्थ है। इन विवादों को इतने लम्बे समय तक लटकाये रहने का क्या कारण है ?

यह दुख की बात है कि हमारे दल पर शिव सेना के साथ सांठ-गांठ करने का आरोप लगाया गया है। वास्तविकता यह है कि आज का युग समझौते का युग है पहले हम पर आरोप लगाया था कि हम साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) भारतीय साम्यवादी दल तथा जनसंघ से समझौता नहीं कर रहे हैं अन्ततः हमारे दल ने यह निर्णय किया था कि गैर-कांग्रेसी मतों को

बढ़ने से रोका जाये। हमने कुछ स्थानों के बारे में समझौते किये थे और कहा था कि जिन स्थानों में उन दलों की स्थिति मजबूत है वे वहां से चुनाव लड़ें और जिन स्थानों में हमारी स्थिति मजबूत है, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। आज देश का यह सामान्य वातावरण है तथा यही बम्बई में भी किया गया है। शिव सेना के साथ हमारे समझौता बस इसी प्रकार का था और इसके अतिरिक्त उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था। वहां जो हिंसात्मक घटनायें हुई हैं उनके प्रति हम गहरा दुख प्रकट करते हैं। ऐसी घटनाओं को होने से रोका जाना चाहिये तथा उनकी जांच के लिये एक व्यापक जांच आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। उन घटनाओं की व्यापक जांच होनी चाहिये तथा जांच का क्षेत्राधिकार केवल इस बात की जिम्मेदारी निर्धारित करने तक ही कि इन घटनाओं का उत्तरदायी कौन है सीमित नहीं होना चाहिये, बल्कि हमें उस जांच से यह जानने के प्रयत्न करने चाहिये कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। ऐसी घटनाओं के प्रति आज तक सरकार की जो प्रतिक्रिया रही है, वह केवल यह है कि हिंसा को और अधिक हिंसा का प्रयोग करके दबा दिया जाता है। यह प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। इससे तो हिंसा का कुचक्र चलता ही रहता है।

अन्त में मैं अनुरोध करता हूं कि देश की एकता को बनाये रखने के लिये तथा जनता में यह विश्वास पैदा करने के लिये कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है, हम सबको मिलकर भरसक प्रयत्न करना चाहिये। देश की एकता को बनाये रखना किसी एक दल की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु यह हम सब की जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश, तंजौर तथा बम्बई की घटनाओं से हमें यह सीखना चाहिये कि भविष्य में हम कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे देश में पुनः ऐसी घटनाएं हों, जो कि हमारे देश के नाम पर कलंक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें आज इस वाद-विवाद को पूरा करना है। कल प्रधान मंत्री उत्तर देंगी तथा इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री पी० राममूर्ति को भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। इसलिये आज सभा कुछ अधिक देर तक बैठेगी ताकि वाद-विवाद को पूरा किया जा सके।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : Today the Unity of our country is at stake. The fissiparous tendencies have been raising their heads in the names of language, religion and State. They are creating the feelings of hatered among the citizens of our country. National property is being destroyed. So when such things are happening which are detrimental to our national Unity, democracy and national Values, it becomes the bounden duty of all of us who are sitting in this supreme democratic House to ponder over such matters very cool headedly and try to find out the reasons why our national fibre is being disintegrated by these forces in the names of religion, language and State. I appeal to the leaders of the opposition parties that it is not proper to consider them by bringing a motion of No-confidence. These questions can only be considered when we rise above from our political affiliations and try to solve them from a national point of view. But the difficulty with our opposition parties is that they are unable to rise above the political considerations. I want to know how these national problems can be solved by bringing No-confidence motions, when baseless charges are levelled against the Government.

It is very unfortunate for the unity of our country that the fissiparous forces like the Shiv Sena, the R. S. S. and the Lachit Sena are disintegrating our national fibre in the names of religion, caste, region and language etc. I was surprised to hear that the Jan Sangh leader Shri Atal Bihar Vajpayee had asked where Shri Lachman Singh Gill, Shri Mandal and Shri Ghosh had gone who were supported by the Congress? I want to know from him where Shri Tamreshwar Prasad, Shri Barmeshwar Pandey and Shri Ganga Bhagat Singh had gone, who were minister in the last U. F. Government of U. P. and who belonged to Jan Sangh? Had they not been defeated in the elections? So these questions can not solve our national problems.

Shri Atal Bihari Vajpayee had levelled certain charges against the Prime Minister and he was so angry that he lost his mental equilibrium. He has alleged that the Prime Minister has tried to organise several public meetings with the help of Government servants. He has also alleged that the Prime Minister made no attempt to educate the people about national problems. The Prime Minister had an objective approach to the elections. Her object was to warn the people against the fissiparous tendencies which were creating disunity in the name of religion, caste and regional loyalty. She felt that Jan Sangh was responsible for spreading communalism in U. P., Bihar and the rest of north India. She warned the people against the communal tendencies of Jan Sangh which was detrimental to our national unity, national values and national policy. The result was that the Jan Sangh's dream of forming Government in U. P. ended in smoke. This was a great shock to the Jan Sangh leader Shri Vajpayee and that is why he is so much flared up that he lost his mental equilibrium.

The Jan Sangh claims to be the only protector of national Unity. But it is a tall claim. It is far from reality. I want to know if Jan Sangh is a nationalist party, why they have formed coalition Government with Akali Dal, which is disintegrating our national life. On one hand Jan Sangh is pleading for a legal ban on communists because they are traitors and on the other hand they are sitting with the communists in the cabinet. What is all this? So far as S. S. P. is concerned they are saying that Congress is responsible for crushing socialism, but why they have entered in alliance with Shiv Sena in Bombay which is a fascist party. Do they want to bring socialism with the help of fascism?

Jan Sangh is a communal party and their base is R. S. S. They are out to destroy national unity and for that purpose they are entering in alliances with every party.

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं गांधी जी के कातिल की बात नहीं सुनना चाहता ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उन्होंने एक माननीय सदस्य को गांधी का कातिल कहा है । यह शब्द वापस लिए जाने चाहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : ऐसे बेबुनियाद आरोप बर्दाश्त नहीं किये जा सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात सुनिये तथा इन शब्दों को वापस लेना और न लेना उनके स्वविवेक पर छोड़ दीजिए ।

Shri Chandra Jeet Yadav : Had the Hon. Member not levelled a personal charge, I would not have used these words. Keeping in view the dignity and decorum of the House I withdraw my words.

So I was saying that our problems can not be solved by allegations and counter allegations. Shri Fernandes had alleged that the Prime Minister was not worried about national problems, but she was more worried about international problems like vietnam war and Arab Israel conflict. I do not know what is wrong if she tries to solve these problems. She is a Prime Minister of a great country and we should feel proud if she solves these problems. It is no use in laughing at the Prime Minister by saying that she is worried that there should be no war among the countries of the world and she is not concerned about national problems. It all shows how low we are talking.

Shri George Fernandes has alleged that the Central Government incures less expenditure for Bihar. He has also alleged that U. P. and certain other States are not getting justice from Government of India. This tendency is dangerous for our country. By raising such questions bitterness is being created among the people of different States. The opposition parties are appealing to the narrow feelings of the people some time on the name of religion, some time on the name of language and sometime on the name of State. A reference has been made about the famine in Rajasthan. I agree that the condition in Rajasthan is miserable and we should solve this problem. But can this problem be solved by mere questions ? We should give a cool and serious thought to this problem. I know that last time when the people of Bengal were flood stricken and we tried to help them, the opposition parties instigated the Railway employees to go on strike. Was it proper? Can these problems be solved by this ? I would appeal to the members of all opposition parties that they should rise above their party interests and view such matter with national point of view. The need of the hour is that all political parties should sit together and prepare a code of conduct for themselves.

There can not be two views that there is regional imbalance in the country. There are certain regions in the country which are economically backward and whose development has not been satisfactory during the last twenty years. This has given birth to dissatisfaction. We all should think over this problem and try to solve it.

Now we are seeing that the number of such parties whose ideology is based on regional loyalty and regional language is increasing. So the time has come when we should see as to why these complaints and difficulties are coming up. Today the question of Centre-State relations has assumed greater importance because different parties are coming in power in different States. So we should sit together and try to solve this question.

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने से पहले मैं इन आरोपों का खण्डन करना चाहती हूं कि विरोधी पक्षों द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा रेलवे इत्यादि को नष्ट किया जा रहा और कांग्रेसी सरकारों को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं यह बताना चाहती हूं कि वर्ष 1967 के आम चुनावों में राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया था और विधान सभा में विपक्षी दलों के सदस्यों को बहुमत प्राप्त हुआ था । इसके बाद कांग्रेस सरकार द्वारा गोलियां चलाई गईं और एक विद्यार्थी को मारा गया । तदुपरान्त राष्ट्रपति का

शासन लागू किया गया और इस बीच कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा विपक्षी सदस्यों को खरीदा गया। अतः मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि उन्हें विपक्षी दलों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए, जबकि वे स्वयं इस प्रकार के काम करते हैं। जो स्वयं शीशे के मकानों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार को लोगों की शिकायतों की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए ताकि बाद में विस्फोट न हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मैं इस सरकार में अविश्वास व्यक्त करती हूं। गत 22 वर्षों में यह भारत की जनता के लिए कुछ भी करने में असफल रही है। आज भी गरीबी है, भुखमरी है और बेरोजगारी है। जनता को सरकारी अधिकारियों में कोई विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी तब तक काम नहीं करता है, जब तक उसे पैसे की भेंट न चढ़ाई जाये। लोग कांग्रेसी सरकार से ऊब गये हैं। आज कांग्रेस की सरकारों का एक ही उद्देश्य है—चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार—और वह उद्देश्य है अपनी कुर्सी को बचाये रखना। सब सरकारी विभागों को इस प्रकार बनाया गया है कि उनके उद्देश्य केवल कांग्रेस की कुर्सी को बचाये रखना है। शिक्षा संस्थाएं तथा खेल-कूद संस्थाएं और यहां तक कि चुनाव आयोग भी जिनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, इस कुचक्र में फंस गये हैं। सरकार से कोई खुश नहीं है। मैं सरकार को सचेत करना चाहती हूं कि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों ने उनको बर्दाश्त किया है, परन्तु नई पीढ़ी जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, उन्हें बर्दाशत नहीं करेगी।

हर क्षेत्र में सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। वर्तमान मध्यावधि चुनावों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब लोगों का कांग्रेस में कोई विश्वास नहीं रहा। यद्यपि प्रधान मंत्री ने उन चार राज्यों में जहां मध्यावधि चुनाव हुए हैं, अनेक जन सभाओं में भाषण दिये, लोगों की भावनाओं को उभारा और कहा कि केवल कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो स्थिर सरकार बना सकती है, तथापि चुनावों के परिणामों से यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। बंगाल के चुनाव परिणाम से मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ है। गत संविद सरकार के दिनों में बंगाल के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। खाद्य पदार्थों की कीमतें चढ़ गई थीं। सुरक्षा की कोई व्यवस्था न थी। घेराव 'इत्यादि किये जाते थे। अतः यह आश्चर्य की बात है कि इन सब बातों के होते हुए भी बंगाल के लोगों ने कांग्रेस की बजाय संविद को सत्ता सौंपना अधिक अच्छा समझा है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है।

इस बार पहली दफा यह कहा गया है कि मतदाताओं से बलपूर्वक मतदान कराया गया। इसके कारण यह हैं कि कांग्रेस को पहली बार ऐसे स्थानों पर चुनाव लड़ने पड़े हैं, जहां कांग्रेसी सरकारें न थीं। अब तक जो चुनाव लड़ते रहे हैं, उन सबमें सरकारी तंत्र का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त मतपत्रों को मतपेटियों में डाला जाता रहा है। यह सब बातें कांग्रेस की सिखाई हुयी हैं तथा इस बार लोगों ने उनके साथ वही खेल खेला है, जो वे लोगों के साथ खेलते रहे हैं।

जनसंघ दल के एक नेता ने प्रधान मंत्री के चुनाव भाषणों के अंशों को आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने का विरोध किया था। यह एक और सबूत है जिससे यह सिद्ध होता है कि सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव के उद्देश्यों के लिये सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया।

जब सरकारी कर्मचारी अपने काम पर नहीं आते हैं तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है। क्या यह बात मंत्रियों पर लागू नहीं है, जबकि उन्हें सब सुविधाएं दी जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के लिये चुनाव प्रचार करने के लिये मंत्री कई-कई हफ्तों तक अपने कार्यालयों में नहीं आये और चुनाव यात्रा पर रहे। मैं जानना चाहती हूं इससे सरकारी विकास-कार्य पर कितना प्रभाव पड़ा तथा सरकारी कोष से उनकी यात्राओं पर कितना धन खर्च किया गया।

गृह मंत्री ने अभी कहा है कि मुख्य मंत्री अपने राज्य का पिता होता है। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया को पंजाब का चुनाव प्रचार सौंपा गया। अतः राज्य में अकाल के होते हुये भी मुख्य मंत्री महोदय राज्य से बाहर थे और चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। जब मुख्य मंत्री महोदय कलकत्ता जैसे बड़े शहरों का दौरा कर रहे थे तो हम समझते थे कि वे उद्योगपतियों से राजस्थान अकाल राहत निधि के लिये धन इकट्ठा कर रहे हैं, परन्तु जब वे खाली हाथों लौटे तो हमें पता चला कि वह सब धन कहां चला गया।

मैं अब एक बहुत दुखद बात का उल्लेख करना चाहती हूं। राज्य से लगातार गैर-हाजिर रहने के कारण वे राज्य में—जैसलमेर, जोधपुर, बारमेर तथा अन्य नगरों में चलाये जा रहे सरकारी राहत शिविरों पर नियंत्रण नहीं रख सके। इन राहत शिविरों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जाली मस्टररोल बनाये जाते हैं। हजारों पशु मर चुके हैं। परन्तु उन्हें इन सब बातों की अधिक चिन्ता नहीं है। कांग्रेस को तो केवल कुर्सी की चिन्ता है और इसके लिए लोगों को रिश्वत दी जाती है तथा उन्हें खरीदा जाता है।

मैं एक और दुखद बात का उल्लेख करती हूं। वे सब राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। कहा गया है कि देश में खाद्यान्न का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है तथा इस कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों को लाने ले जाने की रोक में ढील दे दी गई है। यदि यह सच है तो इन खाद्य जोनों को समाप्त क्यों नहीं किया जाता ? गुजरात के लोगों को क्यों भूखा मरने दिया जा रहा है ? राजस्थान के राहत श्रमिकों को दो किलो गेहूं तथा 6 किलो माइलो ही क्यों दिया जा रहा है ?

भोजन जीवन के लिए आवश्यक है और सरकार खाद्य क्षेत्र बनाकर राज्यों के बीच भेदभाव पैदा कर रही है, खाद्य-क्षेत्रों को समाप्त क्यों नहीं किया जाता है ? हमारी यह तथाकथित सरकार भारत के नागरिकों को भोजन, कपड़ा, आवास आदि जैसी मूलभूत वस्तुएं भी प्रदान नहीं कर पा रही है।

सरकार शहरों में गंदी बस्तियों को हटाने की बात कहती है परन्तु स्वयं भवन बनाकर

उसमें रह रही है। सरकारी कार्यालयों और भवनों के नजदीक मंत्रियों और अधिकारियों के निवास-स्थान बनाए जाते हैं और उनके पास अपनी कारें होती हैं, कर्मचारियों और मजदूरों को शहर के एक कोने में रहना पड़ता है और उनको यातायात के साधन भी सुलभ नहीं होते।

राजस्थान नहर परियोजना को ही लीजिए यह सबसे बड़ी योजना है परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अगर इस पर काम पूरा हो जाएगा तो यह भारत की प्रतिरक्षा, आर्थिक तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं को सुलझा सकेगी, जब श्री कृष्णामाचारी वित्त मंत्री बने तो उन्होंने राजस्थान नहर परियोजना को अपने हाथ में ले लेने का निश्चय किया परन्तु यह विचार त्याग दिया गया, बाद में सरकार ने अकाल का बहाना लेकर राजस्थान नहर परियोजना का कार्य अपने हाथ में लिया, जैसा कि मैंने कहा है कि यह समस्त भारत का नक्शा ही बदल देगा।

अगर भारत सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार की गैर-सरकारों को धन दे सकती है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी क्यों नहीं दे सकती है? बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने उस धन को कुओं को खुदवाने में लगाया परन्तु राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्र में 59 नलकूप लगाए गए और उनमें से केवल 3 ही काम कर रहे हैं।

सरकार केवल खर्चीली और उच्च स्तरीय समितियों का ही गठन करती रहती है ताकि वह विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती रहें परन्तु उन सिफारिशों को कभी भी कार्यरूप नहीं दिया जाता है, इसी प्रकार प्रशासन सुधार आयोग और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सिफारिशें सरकार को दी गई हैं परन्तु उन पर कुछ नहीं हुआ है। इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रतिवेदन को तैयार करने में बहुत खर्चा आया है परन्तु उसे भी रद्द कर दिया गया है और इस प्रकार पर्यटन के विकास में रुकावट डाला गया है।

सरकार पर विश्वास न होने का एक मुख्य कारण यह है कि हम इनकी नीतियों को नहीं समझ पाये हैं। हमारी विदेशी नीति गुटनिरपेक्ष रहने की है परन्तु वियतनाम के लोगों के प्रति हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। चेकोस्लोवाकिया की जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है परन्तु सरकार को उनके प्रति कुछ भी सहानुभूति नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि इस सरकार को, जिसकी आन्तरिक तथा विदेशी नीति असफल रही है, अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : कांग्रेस राज्य के प्रति जनता ने अविश्वास प्रकट किया है। हाल ही में चार राज्यों में हुए चुनावों से प्रकट होता है कि जनता कांग्रेस सरकार को नहीं चाहती है। यह सब इसीलिए हुआ कि क्योंकि सरकार की नीतियां गलत रही हैं और पिछले 22 वर्षों में सरकार जनता को आर्थिक संपन्नता तथा सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी है।

कांग्रेसी नेता धर्म निरपेक्ष राज्य और लोकतान्त्रिक आदर्शों के समर्थक होने का दावा करते हैं, उनका कहना है कि वे इसके संरक्षक हैं। परन्तु मैं कहूंगा कि ये तथाकथित, संरक्षक कहलाये जाने वाले सरकार स्वयं ही देश के इस रूप को बिगाड़ रही है। सरकार जनता की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे वस्त्र, निवास स्थान, भोजन आदि को पूरा करने में असफल रही है।

सरकार शिव सेना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसे प्रादेशिक तथा साम्प्रदायिक संगठनों को बढ़ावा दे रही है। आप जानते ही होंगे कि आज अल्पसंख्यक वर्ग अपने आपको कितना असुरक्षित समझ रहा है। इस देश में उनके जान माल तथा इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग यह अनुभव करता है कि उसकी संस्कृति, धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। वह सरकारी न्यास विधेयक को ला रही है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के वक्फ निकाय जो अपनी संस्थाओं को नहीं चला सकते, उनको अपने नियंत्रण में लाना है। मेरा निवेदन है कि यह संविधान के अनुच्छेद 36 और 37 के विरुद्ध है।

बम्बई में शिव सेना की गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, अभी हाल के दंगों में लाखों व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बम्बई में हुये दंगों में गैर-महाराष्ट्रियों, विशेषतया केरल और तामिलनाड के व्यक्तियों की सम्पत्ति नष्ट हुई है और 57 व्यक्तियों की जानें गईं, 500 व्यक्ति जख्मी हुए तथा 4000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

श्री चह्वाण कहते हैं कि सरकार शिव सेना की गतिविधियों से शर्मिंदा है और उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह संगठन इतना हिंसात्मक रूप धारण कर सकता है, वास्तव में इस आन्दोलन को खुलेआम श्री ठाकरे ने जो कि इसके नेता थे, भड़काया, यह कहा जा रहा था कि सीमा विवाद को बम्बई की सड़कों में सुलझाया जायेगा, मैं यह बता दूं कि यह इस तरह का पहला उदाहरण नहीं है, बम्बई में अगस्त 1967 में भी गैर-महाराष्ट्रियों पर अत्याचार किया गया। उस समय गृह मंत्री ने कहा था कि अब ऐसी घटना दुबारा नहीं होगी और गैर-महाराष्ट्रियों की जान-माल की रक्षा की जाएगी। परन्तु आज सरकार गैर-महाराष्ट्रियों की रक्षा करने में असफल रही है। यहां तक कि पुलिस ने भी भली-भांति अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया। बम्बई में होटल वालों पर, जिनमें गैर-महाराष्ट्रियों तथा मुसलमान अधिक हैं, आक्रमण किया गया और इन सबको अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। सरकार को इन सब स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और केवल इस प्रकार के बहाने नहीं बनाने चाहिए अगर संविधान के अन्तर्गत अल्प-संख्यक वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संगठन बनाते हैं तो उन्हें साम्प्रदायिक संगठन का नाम देकर भर्त्सना की जाती है परन्तु शिव सेना तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठनों को कुछ नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार का भेद-भाव क्यों किया जा रहा है ?

ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस सरकार जनता के प्राणों की परवाह नहीं करती। जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वह बुरी तरह असफल रही है। उनका कहना है

कि वे स्थायी सरकार बना सकते हैं, परन्तु वे इस प्रकार स्थायित्व कैसे ला सकते हैं जबकि वे जनता को सुरक्षा, शान्ति और आर्थिक समृद्धि नहीं दे पाये हैं, पन्द्रह वर्ष के बाद भी प्रादेशिक असंतुलन विद्यमान हैं, आज पश्चिमी बंगाल, पंजाब और अन्य राज्यों में जनता ने कांग्रेस के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है ।

आज कांग्रेस दल के नेता श्री निजलिंगप्पा कहते हैं कि केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये, केरल की सरकार भलीभांति शासन चला रही है और वहां के शासन को कोई खतरा नहीं है फिर भी यह कहा जा रहा है कि वहां असुरक्षा की भावना फैली हुई है और कानून तथा व्यवस्था का अभाव है, परन्तु आंध्र और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेसी राज्यों में भी अव्यवस्था फैली हुई है और यह कोई नहीं कहता कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये ।

मैं साम्प्रदायिक उपद्रवों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, हाल ही में कटक और इंदौर में इस प्रकार के उपद्रव हुए, प्रधान मंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में भी स्वीकार किया है कि इन सबके पीछे जनसंघ जिम्मेवार है, परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इन 22 वर्षों के दौरान जनसंघ की ताकत को कम करने के लिए क्या किया ? वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए में कहता हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है ।

आज जो दिल्ली में हो रहा है, उससे सरकार अनभिज्ञ नहीं है, निजामुद्दीन क्षेत्र में दिल्ली प्रशासन ने मस्जिदें आदि गिरायीं, कब्रों को तोड़ा गया तथा उन पर बुलडोजर चलाये गये, यह सब केन्द्रीय सरकार की जानकारी में हो रहा है, जब जमाऐत-उल-उलेमा के अध्यक्ष ने विरोध प्रकट किया तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, कांग्रेस सरकार इसी प्रकार का प्रजातंत्र और धर्म निरपेक्ष राज्य को चलाना चाहती है, हमें अनुभव से यह सबक मिला है कि कांग्रेस वास्तविक अर्थों में प्रजातंत्र और धर्म-निरपेक्ष नहीं ला सकती है अतएव वह अपनी गद्दी छोड़कर दूसरों को शासन चलाने का अवसर प्रदान करे ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण में बहुत ही भावुक थे । इसका कारण यह हो सकता है कि मध्यावधि चुनावों में उसको सभी राज्यों में हार मिली है । स्वतंत्र दल के साथ भी यही हुआ है । चुनाव के दौर के समाप्त होने पर हम इन परिणामों से कुछ शिक्षा ले सकते हैं, चुनाव के परिणामों से किसी भी दल को अपनी स्थिति का पता लग सकता है । कई राजनैतिक दल बड़े बढ़-चढ़कर कहा करते थे कि वे कांग्रेस को हटा करके वैकल्पिक सरकार बनाएंगे, परन्तु आज का मतदाता जागरूक हो गया है और उसने अपने अधिकार का प्रयोग बुद्धिमानी के साथ किया है तथा प्रतिक्रियावादी तथा सांमतशाही शक्तियों को उठने नहीं दिया है ।

मध्यावधि चुनावों के बाद विभिन्न राजनैतिक दलों ने परिणामों का विश्लेषण किया है । उत्तर प्रदेश की जनता ने उग्रवादी दक्षिणपंथी और वामपंथियों को अस्वीकार कर दिया है ।

संसोपा के नेता श्री राजनारायण भारतीय क्रांति दल के नेता पर जातिवाद को भड़काने का दोष लगा रहे हैं तो श्री वाजपेयी यह मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस यह बताये कि उन्होंने इतना धन किन साधनों से प्राप्त किया है। पंजाब में कम्युनिस्टों का सफाया हो गया है, अब बड़े राजनैतिक दलों के नेता वास्तविकता को समझने लगे हैं। लोक सभा के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि जनसंघ, प्रजासमाजवादी दल, स्वतंत्र तथा द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम ने प्रस्ताव का समर्थन न करने का निश्चय किया है। मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या कम्युनिस्ट मार्क्सवादी दल देश में प्रगतिवादी, समाजवादी और प्रजातंत्र की शक्तियों को मजबूत बना रही है ? प्रधान मंत्री ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों को हर प्रकार की मदद देगी परन्तु दूसरे पक्षों से कोई अनुमूल उत्तर नहीं मिला है। कम्युनिस्ट मार्क्सवादी दल के नेता ने कलकत्ता के एक भाषण में कहा था कि अगर संसदीय प्रजातंत्र द्वारा हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो हमें रक्तपात की क्रांति करनी पड़ेगी।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब चुनाव का ज्वर उतर जायेगा तो राजनीतिक दृष्टि से जागृत बंगाल की जनता को यह सोचने का अवसर मिलेगा कि क्या उन्होंने रक्त पात के लिए अथवा सस्ता भोजन, अधिक निवास-स्थान, साफ सुथरा कलकत्ता तथा समृद्धिशाली बंगाल के लिए अपना मत दिया है। जैसा कि श्री नाथपाई ने कहा है कि सब राजनैतिक दलों का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह जनता की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करे। स्थायित्व का तात्पर्य स्थिरता से नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जनता को मकान, शिक्षा तथा भोजन उपलब्ध करें। आज हमारे सामने यही एक बड़ी चुनौती है।

आज हमें गम्भीरता के साथ सोचना है कि ऐसे कौन से रास्ते होने चाहिए जिससे केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध ठीक बने रहें तथा जनता के निर्णय को पूरा किया जा सके।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : अभी कांग्रेसी सदस्यों ने जो बातें कही हैं, वे सब सारहीन हैं और समस्या की गम्भीरता की उपेक्षा की गई है। माननीय गृह-मंत्री ने शिव सेना की गति-विधियों को रोकने के जो प्रस्ताव दिये हैं वे भी ठोस नहीं हैं। शिव सेना की तुलना अन्य संगठनों के साथ करने में कोई लाभ नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो इस देश के नागरिकों के लिये चुनौती है। मैं नहीं समझता कि स्वतंत्रता के 22 वर्षों के पश्चात् भी मैं अपने आपको भारतवासी पहले कहूं या तामिल निवासी। अगर नागरिकता को राज्य का न मानकर भारतीय संघ का माना जाये तो सरकार ऐसे संगठनों के प्रति दयाभाव नहीं बरत सकती।

माननीय गृह-मंत्री कहते हैं कि वे इस संगठन पर पाबन्दी लगाने के लिए वैध रूप से कुछ भी नहीं कर सकते अगर वे स्वयं ऐसा नहीं कर सकते तो सभा में उचित विधान लाया जाये और इसकी सहायता से इस पर पाबन्दी लगाई जाये। मद्रास में भी जो पहले आन्दोलन हुए, उनमें गैर-तमिल निवासियों की सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हमने ऐसा कोई भी काम करने का प्रयत्न नहीं किया जिससे बाहर से आकर बसने वालों को किसी भी प्रकार की

कठिनाई हो। परन्तु अब ऐसे राज्य में यह काम किये जा रहे हैं जो कि भारत का आर्थिक केन्द्र है।

यह सब अचानक ही नहीं हुआ। दो वर्ष पूर्व ही हमले होने आरम्भ हो गये परन्तु माननीय गृह-मंत्री ने आश्वासन देने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज स्वतंत्रता के 22 वर्ष के बाद भी सरकार इस प्रकार के संगठनों के प्रति उदासीन है तो सरकार को गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे आशा है कि एक समय ऐसा आयेगा जब विरोधी दल इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और सरकार को अपदस्थ किया जायेगा।

तामिलनाडु में नेताओं की बुद्धिमानी के कारण वहां स्थिति शांत है। अभी तक वहां बम्बई में हुई घटनाओं की प्रतिक्रियास्वरूप कोई क्रांति अथवा आन्दोलन नहीं हुए, अगर स्थिति ऐसी ही चलती रही तो हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी नियंत्रण को काबू में रखना मुश्किल हो जायेगा। कोई नहीं चाहता कि तामिलनाडु में कोई आन्दोलन चले, हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई वारदात न हो। अगर सरकार इसको रोकने के लिये कुछ न करे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जायेगी।

कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने कहा है कि तामिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की सरकार के आने के बाद हरिजन जाति के 42 व्यक्तियों को जलाने की घटना हुई। यह एक शर्मनाक बात है परन्तु मैं अभी इस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ; फिर भी इस सम्बन्ध में जो व्यक्ति पकड़े गये हैं वे कांग्रेस दल से सम्बन्धित हैं और उच्च पद पर आसीन हैं। अगर कांग्रेसियों को कहा जाता है कि उन्होंने कई मामलों में गल्तियां की हैं तो वे हमसे उनके मामलों में दखल देने को मना करते हैं। ऐसी बातें कहने से कांग्रेस अपने आपको दोषमुक्त नहीं ठहरा सकती। कम से कम कांग्रेस दल को ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि एक उत्तरदायी सरकार है। संसद् में विभिन्न राज्यों के विभिन्न दलों के सदस्य आते हैं और वे अपने-अपने राज्यों के लिए अधिक धन की मांग करते हैं यहां तक कि गैर-कांग्रेसी राज्य से आने वाले कांग्रेसी सदस्य भी अपने-अपने राज्यों के लिये धन की मांग करते हैं परन्तु मेरे राज्य के कांग्रेसी सदस्य सोचते हैं कि अगर द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की सरकार को वित्तीय सहायता दी जाये तो उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे और कांग्रेस के लिए दुबारा सरकार बनाना कठिन होगा, इसलिए मेरे राज्य में जिम्मेदार कांग्रेसियों ने हमारे राज्य को कोई धन न देने का केन्द्र से खुले-आम अनुरोध किया। गोवा कांग्रेस के अवसर पर जब मद्य निषेध पर विचार-विमर्श किया जा रहा था श्री विनायकम ने, जो हमारे राज्य विधान मण्डल के एक सदस्य हैं, कहा था कि मद्रास सरकार को मद्य-निषेध के जरिये जो हानि हुई है उसे पूरा करने के लिये उसने पहले ही बिक्री-कर बढ़ा दिया है तथा अन्य कार्यवाही कर ली है। मद्रास सरकार को क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिये कोई निर्णय लेना हमारी पीठ में छुरा भोंकना होगा। यदि सत्तारूढ़ तथा सत्ता-पिपासु कांग्रेस तथा उसके सदस्यों का रुख यही रहा, तो हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते और इस देश का भगवान ही मालिक है। हमें इसका अब काफी आभास हो रहा है कि कांग्रेस

फिर से सत्ता हथियाने के लिये किस स्तर तक गिर सकती है । तंजौर में जो घटना हुई है उसने इस बात की और भी पुष्टि कर दी है ।

जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सम्बन्ध है, गृह-कार्य मंत्री के उत्तर से हमें अच्छी तरह यकीन हो गया है और हमारी यह पक्की राय है कि इस सरकार को देश पर शासन करने का अब कोई हक नहीं है ।

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : यह आरोप सर्वथा गलत है कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार को उखाड़ा था । लेकिन वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । डाक्टर पी० सी० घोष के अलग होने पर विधान मंडल के 17 और सदस्य भी उनके साथ चले गये और उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वे अजय मुकर्जी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे । राज्यपाल ने उनसे विधान-सभा में अपना बहुमत दिखाने को कहा किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे कांग्रेस को सत्ता-पिपासु कह कर उस पर आरोप लगाते रहे । इसलिये कांग्रेस से, जो कि वहां सबसे बड़ा एकल दल था, डा० पी० सी० घोष के साथ सरकार बनाने को कहा गया । लेकिन इस पर साम्यवादियों ने आन्दोलन पर आन्दोलन शुरू कर दिये । ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करते ? उन्होंने राष्ट्रपति को दी गई अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 5 में कहा है :

"श्री अजय मुकर्जी तथा श्री ज्योति बसु ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं आपसे वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करूं क्योंकि वहां यदि एक दिन के लिये भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सका, तो वे उस आन्दोलन को वापस ले लेंगे ।"

ऐसी स्थिति में कोई कैसे कह सकता है कि कांग्रेस ने वहां की सरकार को समाप्त किया है ?

मुझसे पहले जो माननीय सदस्या बोली हैं उन्होंने कहा है कि लोगों का कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं है और उसने पिछले बाइस वर्षों में कुछ भी नहीं किया है । लेकिन वर्ष 1951 में लोगों द्वारा कांग्रेस सरकार को दिये गये आन्तरिक ऋण की राशि 2022.30 करोड़ रुपये और विदेशों द्वारा दिये गये ऋण की राशि 3203 करोड़ रुपये थी और वर्ष 1968 में ये राशियां क्रमशः 6555.72 करोड़ रुपये तथा 5400.78 करोड़ रुपये थी। इससे जाहिर होता है कि देश तथा विदेश के लोगों का विश्वास भारत सरकार अथवा कांग्रेस सरकार पर कम नहीं बल्कि बढ़ा है ।

श्री दाण्डेकर ने कहा है कि हमारे प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा कम हो गई है और ब्रिटिश समाचारपत्रों ने उनके बारे में खराब रिपोर्टिंग की है । मैं नहीं जानती कि उन्होंने किस प्रेस का उद्धृत किया है जो गलत सूचनाओं तथा पक्षपातपूर्ण रवैये का शिकार है । ब्रिटिश पत्रकार श्रीमती जैगर, श्री फ्रैंक मोरेस तथा श्री मैक्सवैल जो भारत आये थे ने हमारे प्रधान मंत्री की तारीफ तथा सराहना की है । श्रीमती जैगर ने कहा है :

"It was only given to her to bear the strains of long and arduous journeys of such campaigns which showed her to be a woman of tremendous endurance and courage."

श्री फ्रैंक मौरेस ने कहा है :

"She has an independent mind and is extremely observant and sensitive".

श्री मैक्सवैल ने कहा है : "वह लोगों के दुखों तथा समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं।"

ब्रिटिश प्रेस तथा बी० बी० सी० का हमारे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा भारत के प्रति आदर तथा सम्मानपूर्ण रवैया है।

मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती हूं क्योंकि उसके प्रस्तावकों द्वारा लगाये गये आरोप बिल्कुल निराधार हैं और उनमें कोई वजन नहीं है।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : दो बातों का उल्लेख किया गया है—एक शिव सेना से सम्बन्धित घटनाओं का और दूसरा तेलंगाना का। पहली बात जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह कि क्या हमें भारत भर की हिंसात्मक कार्यवाहियों की आलोचना करने तथा उन पर विचार करने का अधिकार है ? जबकि हम खुद इस संसद् में अच्छा स्तर कायम नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सदस्य लोग चाहे वे इस ओर के हों अथवा उस ओर के, वाद-विवाद के दौरान कितनी वांछनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और अपना स्तर गिराते हैं। जब खुद हमारा व्यवहार ही आलोच्य है, तो हमें अन्य लोगों की गतिविधियों की आलोचना करना कहां तक शोभा दे सकता है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तेलंगाना आन्दोलन को शिव सेना की हिंसात्मक गतिविधियों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन बम्बई में हुई हिंसात्मक घटनाओं का तेलंगाना आन्दोलन के साथ किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं। यह आन्दोलन बहुत शान्तिपूर्ण था। कोई व्यक्ति मरा नहीं। यह आन्दोलन आन्ध्र के लोगों के खिलाफ कभी नहीं चलाया गया था, चाहे वे किसी जिले में रह रहे हों। रक्षोपायों की क्रियान्विति न करने के लिये केवल सरकार के विरुद्ध यह आन्दोलन था जिसे वास्तव में विद्यार्थियों द्वारा आयोजित किया गया था। मैं इस आन्दोलन के गुण-दोषों में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वहां कोई हिंसात्मक बात नहीं हुई। समाचारपत्रों ने, जो कि अधिकांशतः पक्षपातयुक्त थे, तोड़-मरोड़ कर रिपोर्टें दीं जिससे स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। इन गतिविधियों के दौरान केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और वह भी किसी विभाग के एक सर्वेयर की और ऐसा बताया गया था कि वह उनके बीच फूट तथा झगड़ों के कारण हुई थी। दो अथवा तीन व्यक्ति पुलिस द्वारा गोलियां चलाये जाने के परिणामस्वरूप मारे गये थे, लेकिन तेलंगाना आन्दोलन में एक भी व्यक्ति नहीं मरा था। संसद् के माध्यम से हिंसा को बढ़ा-चढ़ा कर सामने रखना सर्वथा गलत है और उससे कोई लाभ नहीं होता। इस आन्दोलन को जो रूप दिया गया है वह बिलकुल निराधार है। हां, इतना अवश्य था कि विद्यार्थियों द्वारा आयोजित इस आन्दोलन में कुछ समाज-विरोधी तत्व घुस आये थे और उनसे

सम्पत्तियों की रक्षा करने के लिये बाद में सेना तथा सी० आर० पी० बुलानी पड़ी थी अन्यथा आन्दोलन शान्तिपूर्ण था ।

जहां तक रक्षोपायों का सम्बन्ध है, जब वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, फजल अली आयोग ने तेलंगाना के शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा इस क्षेत्र की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुछ रक्षोपायों की सिफारिश की थी और कहा था कि जब तक केन्द्रीय सरकार इन रक्षोपायों को कार्यरूप देने की जिम्मेदारी न ले, वे निष्प्रभावी तथा बेकार हो जायेंगे । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने वह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली और न ही यह सुनिश्चित किया कि इन रक्षोपायों की वास्तव में क्रियान्विति की जाये ।

एक केन्द्रीय अधिनियम—जिसका नाम जन रोजगार (आवास के सम्बन्ध में आवश्यकताएं) अधिनियम, 1957 है, केवल आन्ध्र पर ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश, पंजाब के एक भू-भाग तथा केन्द्र प्रशासित कई अन्य राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है । इस अधिनियम के आधार पर, आन्ध्र प्रदेश में पांच वर्ष के लिये एक अलग अधिनियम पारित किया गया जिसके अन्तर्गत तेलंगाना के लोगों को रोजगार के मामले में अधिकार दिये गये । लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया गया । शिकायत यही है । इस कारण उपरोक्त विधेयक की अवधि और आगे पांच साल बढ़ा दी गई जो अब इस वर्ष 21 मार्च को समाप्त हो रही है । लोगों ने सोचा कि उसकी अवधि अब और आगे नहीं बढ़ायी जानी चाहिए । लेकिन फिर उसकी अवधि और आगे 5 वर्ष बढ़ाने की सिफारिश की गई । यह विधेयक इस समय राज्य-सभा के विचाराधीन है । गृह-कार्य मंत्री ने उसके बारे में आश्वासन दिया है ।

दूसरी बात वहां के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में है । वर्ष 1956 में आन्ध्र प्रदेश बनने से पूर्व आपसी समझौता हुआ था कि आबादी के अनुपात में कुल बजट का एक तिहाई भाग तेलंगाना में खर्च किया जायेगा और तदनुसार विनियोजन भी किया गया लेकिन वित्तीय वर्ष के अन्त में देखा गया कि पूरी राशि खर्च नहीं की जा सकी और परिणामस्वरूप करोड़ों रुपयों की राशि फालतू रह गई जो आन्ध्र के मुख्य मंत्री के अनुसार 30 करोड़ और तेलंगाना क्षेत्र के एक नेता के अनुसार 70 करोड़ रुपये थी । ऐसे रक्षोपायों की व्यवस्था की गई थी लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया । तेलंगाना के लोग पृथक तेलंगाना की मांग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले ऐसी आवाज जरूर उठाई थी लेकिन अब उन्होंने भी इस मांग को छोड़ दिया है । राज्य सरकार की इस समय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सभी आश्वासनों को क्रियान्वित कर सके, इसलिये केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार के लिये धन की तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह उन योजनाओं को क्रियान्वित कर सके और लोगों में विश्वास पैदा कर सके जिससे लोगों का क्षोभ कम हो, वहां की भावनात्मक एकता पर इस आन्दोलन तथा आन्ध्र प्रदेश के प्रत्यान्दोलन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । यदि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार और जनमत के नेता एकता तथा इन असन्तुलनों को दूर करने का सच्चे दिल से प्रयास करें और उससे लोगों के दिमाग में विश्वास पैदा करें, तो कोई शक नहीं कि यह समस्या न सुलझे और

उससे राष्ट्रीय एकता को जो हम सबको बहुत प्रिय है, बल न मिले । इसलिये केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह केवल एक दर्शक बन कर न रहे और इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करे और ठीक समय पर वित्तीय सहायता दे ताकि राज्य सरकार अपेक्षित योजनाओं को क्रियान्वित कर सके और लोगों में विश्वास बिठा सके ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : विरोधी पक्ष वाले अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिये सदैव अविश्वास के प्रस्ताव लाने की चाल खेलते हैं ताकि वे लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें । वास्तव में वे जनता को अपने पक्ष में नहीं कर सके हैं और यही कारण है कि उनमें से कोई किसी स्थान पर अपना स्पष्ट बहुमत नहीं बना सका है । वास्तव में वे सह-पत्नियों की तरह हैं जो सब एक-साथ नहीं चल सकतीं किन्तु वे मिलजुलकर सरकारें बनाना चाहते हैं पर चल नहीं सकते जिस कारण उनकी सरकारें असफल हो रही हैं । लेकिन दोष वे कांग्रेस के सिर मढ़ते हैं । ये सरकारें गरीब जनता के शोषण पर जीवित हैं और वे कुछ भी नहीं कर रही हैं ।

कुछ राजनैतिक दलों में विस्फोट के चिह्न दिखाई दे रहे हैं जो पतन की निशानी है । उदाहरण के तौर पर लचित सेना तथा शिव सेना और ऐसी ही अन्य चीजों को ले लीजिये । मैं नहीं समझ पाता कि किसी दल के गलतियों अथवा किसी मुख्य मंत्री की गलतियों या कार्यवाहियों या साम्प्रदायिक विस्फोटों के लिये प्रधान मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री कैसे जिम्मेदार या जवाब-देह हैं । वास्तव में अविश्वास का प्रस्ताव मद्रास में डी० एम० के० के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लाया जाना चाहिए था जो महाराष्ट्र के साथ मामला निपटा नहीं सके । लेकिन यहां इस प्रस्ताव को लाने का कोई अर्थ अथवा महत्व ही नहीं है ।

लचित सेना, शिव सेना तथा अन्य कोई सेना इस विषयार्थ सामाजिक बुराइयां हैं जिन पर ठंडे दिमाग से विचार कर दूर किया जाना चाहिए और न कि उत्तेजक भाषण देकर आग में घी की आहुति देने का काम किया जाना चाहिए । प्रतिपक्षी लोगों को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है इसके अलावा वे आपस में एक नहीं हैं इसलिये अविश्वास के प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और यह प्रस्ताव केवल निराधार ही नहीं अपितु इस अवसर पर महत्वहीन तथा अनावश्यक भी है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 20 फरवरी, 1969/1 फाल्गुन, 1890 (शक) के ग्यारह बजे (म० पू०) तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 20, 1969/Phalguna 1, 1890(Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 3-5-69—600.